लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र]

Fifteenth Session

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 57 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LVII contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 6—सोमवार, 1 अगस्त, 1966/10 श्रावण, 1888 (शक)

No. 6-Monday, August 1, 1966/Sravana 10, 1888 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	Oral Answers to Questions	
तारांकित प्रश्न संख्या S. Q. Nos.		
151. चीन के साथ बातचीत	Negotiations with China	1-5
152. भूतपूर्व सैनिकों के लिये रोजगार	Employment for Ex-Servicemen	5-8
153. अमरीका और ब्रिटेन द्वारा भारत को हथियारों की सप्लाई	Supply of Arms to India by U. S. A. and U. K.	9-12
154. चीन के प्रति अमरीका का रवैया	U. S. Attitude towards China	12-13
155. अमरीका द्वारा पाकिस्तान को फिर से सैनिक सहायता का दिया जाना	Resumption of U. S. Arms aid to Pakistan	13-17
156. चीन द्वारा परमाणु विस्फोट	China's Nuclear Explosion	18-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions	
157. छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Cantonment Board Employees	19-20
158. विदेशों में भेजे गये सद्भावना तथा विशेष प्रतिनिधि मण्डलों का प्रभाव	Impact of Goodwill and Special Delegations sent abroad	20
159. ब्रिटेन तथा दक्षिण रोडेशिया के बीच बातचीत	Negotiations between Britain and S. Rhodesia	20-21
160. रेडियो बल्बों की कमी	Shortage of Radio Valves	21-22
161. चीन और पाकिस्तान द्वारा किये जाने वाले प्रचार का खंडन करने के लिये ट्रान्समीटरों का लगाया जाना	Installation of Transmitters to Counteract Chinese and Pakistani Propaganda	22
162. चीन का परमाणु कार्यक्रम	Chinese Nuclear Programme	22-23
163. पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti-Indian Propaganda by Pakistan	23
164. शक्तिशाली ट्रान्समिटर	High Power Transmitters	23-24

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicate that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं०		
S. Q. Nos.		
165. गियाना को मान्यता	Recognition of Guyana	24
166. पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर नहरों का निर्माण	Construction of Canals on West Pakistan Border by Pakistan	24-25
167. काहिरा स्थित भारतीय राजनयिक कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप	Allegations against Indian Diplomatic Personnel at Cairo	25
168. विदेश यात्रा के सम्बन्ध में मंत्रियों को निदेश	Directive to Ministers on Foreign Tours	25-26
169. वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री का विदेश दौरा	Visits abroad of the Minister of State in Ministry of External Affairs	26
170. अमरीका द्वारा ट्रान्समिटरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव	U. S. Offer for Transmitters	27-28
171. पाकिस्तान के लिये रूसी हथियार	Russian Arms for Pakistan	28-29
172. आदिमजातियों के लिये कार्यक्रम	Tribal Programmes	29-30
173. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by H. A. L. Employees	30
174. पाकिस्तान का प्रतिरक्षा पर खर्च	Pak Defence Expenditure	30-31
175. दलाई लामा की लेह यात्रा	Dalai Lama's visit to Leh	31
176. प्रधान मंत्री का रेडियो भाषण जिस में वियतनाम सम्बन्धी प्रस्ताव है	Prime Minister's Broadcast containing proposals on Vietnam	31-32
177. सीमा क्षेत्रों में प्रचार	Publicity in Border Areas	32
178. सैनिकों में चीन का प्रचार	Chinese Propaganda amongst Army Men	32-33
179. पाकिस्तान में ब्लैक आउट तथा हवाई आक्रमण से बचने के उपायों का अभ्यास	Black-outs And Air Raid Precautions in Pakistan	33
अतारांकित प्रश्न संख्या		
U. S. Q. Nos.		
818. भूतपूर्व सैनिकों की संख्या	Census of Ex-Servicemen	33-34
819. भूतपूर्व सैनिकों की परिवहन समितियों के लिये फालतू मोटर गाड़ियां	Surplus Vehicles for Ex-Servicemen Transport Cooperative Societies	34
820. राजस्थान में दूसरा परमाणु रिएक्टर	Second Atomic Reactor in Rajasthan	34

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
821.	संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत के मामले का उठाया जाना	Tibet Issue for U. N. O.	34-35
822.	प्रावदा में प्रकाशित लेख	Article in 'Pravada'	35
823.	परमाणु बम बनाने पर खर्च	Cost of Atom Bomb	35-36
824.	केरल में समुद्री डीजल इंजन कारखाना	Marine Diesel Engine Factory Kerala	36
825.	पूर्वी तट पर नौसैनिक अड्डा	Naval Base on East Coast	36
826.	न्यूक्लिअर क्लब	Nuclear Club	36-37
827.	हिन्दू नागा शान्ति मिशन	Hindu Naga Peace Mission	37
828.	आकाशवाणी के महानिदेशक	Director-General A. I. R.	37-38
829.	रूस से हैलिकौप्टर	Helicopters from U. S. S. R.	38
830.	हाजी पीर दर्रे से सेना की वापसी	Withdrawls from Haji Pir Pass	38
831.	भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के लोग	Ex-I. N. A. Personnel	39
832.	गिलगित में चीन के सैनिक दस्ते	Chinese Military Team in Gilgit	39
833.	रूस के साथ पाकिस्तान की बात चीत रवैया	Pakistan's Approach to Soviet Union	39-40
834.	कछाटिबू द्वीप	Kachchativu Island	40
835.	जवाहर लाल नेहरू स्मारक निधि	Jawaharlal Nehru Memorial Fund	40-41
836.	मंडी हाउस, नई दिल्ली के समीप प्रसारण भवन का निर्माण	Construction of Broadcasting House near Mandi House, New Delhi	41
837.	विदेशों में स्थिति भारतीय दूतावासों के कर्मचारी	Employees in Indian Missions Abroad	41
838.	विदेश में स्थित भारतीय दूतावासों में प्रकाशित प्रचार साहित्य	Publicity Literature published in Indian Missions Abroad	42
839.	केन्द्रीय आयुध डिपो, चिओकी में अग्नि कांड	Fire in C. O. D. Cheoki	42
841.	उत्तर प्रदेश के लिये अखबारी कागज का अभ्यंश	Newsprint Quota for U. P.	43
842.	चिकित्सा कर्मचारियों की चयनात्मक अनिवार्य भर्ती	Selective Conscription of Medical Personnel	43-44
843.	हिन्दी में समाचार बुलेटिन	News Bulletins in Hindi	44
846.	सियोल में नौ राष्ट्रों का मंत्री स्तरीय सम्मेलन	Ministerial Conference of Nine nations in Seoul	44-45

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
847.	प्रचार साहित्य पर व्यय Expenditure on Publicity Literature	45
848.	भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना I. A. F. Plane Crash	45-46
849.	फिल्म डिवीजन का कार्यक्रम Programme of Films Division	46
850.	झांसी में प्रसारण केन्द्र Broadcasting Station at Jhansi	46-47
851.	श्री लालडेंगा का प्रत्यर्पण Extradition of Mr. Laldenga	47
852.	आकाशवाणी केन्द्रों की क्षमता Capacities of A. I. R. Stations	47-48
853.	सिविल रक्षा कर्मचारियों का चिकित्सा सम्बन्धी खर्च Medical expenses of Civilian Defence Employees	48-49
854.	जापानी प्रतिनिधिमण्डल का दौरा Visit of Japanese Delegation	49
855.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस Netaji Subhas Chandra Bose	49-50
856.	वृत्त चित्र Documentary Films	50
857.	इंडिया डायरी India Diary	50-51
858.	सैनिकों के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम Cultural Programme for Troops	51
859.	नाटक समारोह Drama Festival	51-52
860.	आगरा में केन्द्रीय आयुध (ओर्डनैंस) डिपो के कर्मचारियों को भत्ते की प्रतिपूर्ति Re-imbursement of Allowances to C. O. D. Employees in Agra	52
861.	भारत और पाकिस्तान के सर्वे अधिकारियों का सम्मेलन Indo-Pak. Survey officials Conference	52
862.	ट्राम्बे के निकट चम्बूरपुर में भूमि स्खलन (लैंडस्लाइड) Landslide at Chamburpur near Trombay	53
863.	भारतीय सांख्यिकी संस्था, कलकत्ता Indian Statistial Institute, Calcutta	53-54
864.	प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन में प्रशिक्षुता योजना Apprenticeship Scheme in Defence Research and Development Organisation	54
865.	प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन Defence Research and Development Organisation	54
866.	प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में पदोन्नति Promotions in Defence Research and Development Organisation	55
867.	भारतीय वायु सेना में भर्ती Recruitment in I. A. F.	55

विषय	Subjec	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. Q. Nos.		
868. बर्मा से मिजो लोगों को स्वदेश लौटाया जाना	Repatriation of Mizos from Burma	55-56
869. बरेली हवाई अड्डे के निकट गांवों का अर्जन	Acquisition of a Village near Bareilly Airport	56
870. भूतपूर्व सैनिकों के लिये रोजगार	Employment for Ex-Servicemen	56
871. पंजाब की सीमा पर चौकियां	Check Posts on Punjab Border	57
872. वायु सेना मुख्यालय के क्लर्क	Clerks in Air Headquarters	57-58
873. हैदराबाद में इलैक्ट्रानिक्स कारखाना	Electronic Workshop in Hyderabad	58
874. बम्बई में फिल्म डिवीजन का मुख्यालय	Headquarters of Films Division in Bombay	58
875. जवाहरलाल नेहरू के विषय में प्रकाशन	Publications on Jawaharlal Nehru	59
876. अम्बाला छावनी बोर्ड	Amballa Cantonment Board	59
877. भारत द्वारा परमाणु बम का निर्माण	Manufacture of Atom Bomb by India	59-60
878. अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	International Film Festival	60
879. रूस द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण	Clarifications asked for by Soviet Union	61
880. कटक में स्टाफ़ आर्टिस्ट	Staff Artistes at Cuttack	61
881. विदेशों में भेजे गये प्रतिरक्षा अधिकारी	Defence Officers sent Abroad	61-62
882. विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के प्रधान	Heads of Indian Missions Abroad	62
883. सिक्किम में कागज की लुगदी की परियोजना	Paper Pulp Project in Sikkim	62-63
884. क्षेत्रीय आकाशवाणी निदेशक	Regional A. I. R. Directors	63
885. भारत तथा चीन के बीच शिखर सम्मेलन	Summit Meet between India and China	63
886. सशस्त्र सेना के वेतन क्रम	Pay Scales of Armed Forces	63-64
887. अमरीका में भारतीयों के विरुद्ध जारी किये गये गिरफतारी के वारन्ट	Arrest Warrants issued in U. S. A. against Indians	64
888. भारतीय सैनिक संग्रहालय	Indian Army Museum	64-65
889. अर्जन्तीना की नई सरकार को मान्यता	Recognition of new Government of Argentina	65
890. मारिशस	Mauritius	65-66

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
891. कनाडा ब्राडकास्टिंग निगम द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti-Indian Propaganda by Canada Broadcasting Corporation	66
892. पालम हवाई अड्डा क्षेत्र से टायरों और ट्यूबों की चोरी	Theft of Tyres and Tubes from Palam Airport area	66
893. सेना में भर्ती	Recruitment in Army	67-68
894. आकाशवाणी के कर्मचारियों के लिए सवारी सम्बन्धी सुविधाएं	Conveyance Facilities for A. I. R. Staff	68-69
895. आणविक प्रभाव	Nuclear Effects	69-70
896. प्रतिरक्षा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Defence Employees	70
897. गाजा में भारतीय दस्ता	Indian Contingent in Gaza	70
898. प्रतिरक्षा कर्मचारियों को भूमि का दिया जाना	Allotment of Land to Defence Personnel	71
899. रेडियोधर्मी तत्व का पता लगाने के केन्द्र	Radio-Active Fall-out Detection Centres	71-72
900. तैजानिया को सहायता	Assistance to Tanzania	72
901. परिवार नियोजन सम्बन्धी साहित्य	Literature on Family Planning	72
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	72-74
संयुक्त राज्य अमरीका से आयात किये गये खाद्यान्न में लोहे के टुकड़े, कंकड़ आदि पाये जाने के समाचार	Reported Presence of Iron strips, stones etc. in foodgrains imported from U. S. A.	74
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	74-75
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति कार्यवाही-सारांश	Committee on Government Assurances Minutes	75-76
वर्ष 1966-67 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल) विवरण उपस्थापित किया गया	Demands for Supplementary Grants (Kerala) 1966-67 Statement presented	76
निष्कासित सदस्यों को वापस बुलाने के बारे में	Re: Recalling of expelled Members	76-77
वर्ष 1962-63 और 1963-64 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (केरल) विवरण उपस्थापित किया गया	Demands for Excess Grants (Kerala) 1962-63 and 1963-64 Statement presented	77
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	77

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक	Bills passed by Rajya Sabha	77
(1) टेलीग्राफ वायर (अवैध कब्जा) संशोधन विधेयक	(i) Telegraph wires (unlawful Possession) Amendment	
(2) प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक	(ii) Maternity Benefit (Amendment Bill)	
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द होने के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Closure of Banaras Hindu University	77-78
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla	
भारत-पकिस्तान सीमा पर स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement re. Situation on India-Pakistan Border	78
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	
निलम्बित सदस्यों के अधिकारों के बारे में	Re : Rights of Suspended Members	79
संयुक्त समाजवादी दल में सदस्य के शामिल होने के बारे में	Re. Addition of Member to S. S. P. Group	79
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 1965	Advocates (Amendment) Bill 1965	79
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में वापस लिया गया	As passed by Rajya Sabha-Withdrawn	
अवैध गतिविधियां (निवारण) विधेयक	Unlawful Activities (Prevention) Bill	
पुरःस्थापित	Introduced	79-80
अवैध गतिविधियां (निवारण) अध्यादेश, 1966 के बारे में वक्तव्य	Statment Re. Unlawful Activities (Prevention) Ordinance, 1966	80
भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) विधेयक, 1966-पुरःस्थापित	Defence of India (Amendment) Bill, 1966-Introduced	80-81
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1966 पुरः स्थापित	Advocates (Amendment) Bill, 1966-Introduced	81-82
मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers	82-97
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur	
श्री रंगा	Shri Ranga	
श्री हेडा	Shri Heda	
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi	
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 1 **अगस्त** 1966 / 10 **श्रावण**, 1888 (**शक**)

Monday, August, 1, 1966 / **Sravana, 10**, 1888 (**Saka**)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चीन के साथ बातचीत

*151. **श्री हेम बरुआ** :
श्री नाथ-पाई :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्रीमती जयाबेन शाह :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री वारियर :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बागड़ी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा चीन के बीच की न निपटी हुई सीमा समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने ताशकन्द बैठक के समान चीन के साथ बातचीत करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह बातचीत कोलम्बो प्रस्तावों के आधार पर करने का विचार है.

या यह बातचीत बिल्कुल स्ततंत्र रूप से की जायेगी और यदि यह स्वतंत्र रूप से की जायेगी तो उसका आधार क्या होगा ?

बैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सीमा के सवाल को निबटाने के लिए भारत सरकार चीन सरकार के साथ उचित आधार पर बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रही है। भारत सरकार का विचार है कि 1963 में गुटों से अलग छः देशों ने जो कोलम्बो प्रस्ताव रखे थे, जिन्हें भारत ने स्वीकार कर लिया था, उनमें ऐसा उचित आधार निहित है। लेकिन चीन सरकार ने इन प्रस्तावों को बातचीत का आधार बनाने से इन्कार कर दिया है।

ताशकन्द की तरह की बातचीत का जहां तक सवाल है, उसके लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष कम-से-कम मामले को शांति से निबटाना तो चाहते हों। हम तो अपनी बात से नहीं हटे हैं लेकिन चीन सरकार भारत और भारत की नीतियों के विरुद्ध अपनी शत्रुतापूर्ण कार्यवाइयों में इस बुरी तरह लगी प्रतीत होती है कि इस तरह की बातचीत का संकेत देने या रूचि दिखाने की बात तो दूर रही, उसने ताशकंद समझौते पर ही आक्षेप किया है।

श्री हेम बरूआ : क्या सरकार हमारे 14,500 वर्ग मील क्षेत्र पर चीन के अनधिकृत कब्जे को आधार कर या मेकमोहान रेखा के दक्षिण की ओर 90,000 वर्ग किलो मीटर पर चीन के अग्रेतर दावे को आधार कर बात करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने पहले बता दिया है कि कोलम्बो प्रस्ताव बातचीत का एक उचित आधार थे। दुर्भाग्य से चीन ने उसको आधार स्वीकार नहीं किया है। अतः इस समय चीन के साथ बातचीत का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है।

श्री हेम बरूआ : चूंकि चीन ने कोलम्बो प्रस्तावों को छूने से भी इन्कार कर दिया है और चीन ने 40 किलो मीटर के विसैन्यीकृत क्षेत्र में अपनी चौकियों को समाप्त नहीं किया है जैसा कि कोलम्बो प्रस्तावों में अनुबाधित है, फिर हमारी सरकार कोलम्बो प्रस्तावों पर इतना भरोसा क्यों करती है और विश्व का क्यों नहीं यह बता देती कि कोलम्बो प्रस्ताव हमारे लिए भी मर चुके हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं नहीं समझता कि यह कोई बुद्धिमत्ता होगी। यह कोई दलील नहीं है क्योंकि चीन ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है इसलिये हम भी इनको अस्वीकार कर दें। हम इन प्रस्तावों को बातचीत के लिये उचित आधार समझते हैं। चीन द्वारा इन प्रस्तावों के अस्वीकृत किये जाने का इन प्रस्तावों के बारे में हमारी नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

Shri Siddheshwar Prasad : Are Government aware that the repeated announcements on behalf of the Government that it is always prepared to hold negotiations with China are having unhealthy effect on our Countrymen because China says that it is not prepared to hold negotiations, if so, why such things are repeated by Government ?

Shri Swaran Singh. : The hon. Member is a very influeufial member and if the people entertain any doubts, he may dispel them. Since we are sticking to a principle, and if any doubt is created while sticking to principle, we should try to dispel that.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : माननीय मंत्री के अनुसार बातचीत के लिये एक मात्र आधार केवल कोलम्बो प्रस्ताव ही हैं जिन्हें चीन ने ठुकरा दिया है। ऐसी स्थिति में आक्रमण के उन क्षेत्रों को खाली कराने के लिये क्या कोई उपाय किये जा रहे हैं और यदि चीन उन क्षेत्रों को खाली नहीं

करता तो क्या हम उनको निकालने के लिये तैयारी कर रहे हैं। क्या संयुक्त अरब गणराज्य में राष्ट्रपति के साथ बातचीत के दौरान प्रधान मंत्री ने उस विषय को उठाया था। चूंकि कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, क्या वे चीन के साथ बातचीत का कोई आधार तलाश करेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमने किसी विदेशी सरकार को यह सुझाव नहीं दिया है कि वह चीन से यह पता करें कि क्या बातचीत का कोई और आधार हो सकता है। हमारी नीति स्पष्ट है कि कोलम्बो प्रस्तावों के आधार पर बातचीत आरम्भ करने की संभावना है, और हमने किसी मित्र राष्ट्र को यह नहीं कहा है कि वह चीन के स्पष्ट रवैये को ध्यान में रखते हुए इस मामले का अनुसरण करें।

निश्चय ही अपनी अखंडता की सुरक्षा के लिए हम सभी संभव तैयारियां कर रहे हैं और इस प्रश्न पर हमें वास्तव में निरन्तर यह आशा करते रहना है कि जल्दी या देर से हमारा अपना प्रदेश हमें लौट आयेगा।

श्री हरिविष्णु कामत : वह कैसे लौट सकता है ?

श्री हेम बरूआ : किन उपायों द्वारा ?

(**अन्तर्बाधा**)

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन् यह गोलमाल उत्तर है। आपको इस सभा और देश की सहायता करने का प्रयत्न करना चाहिए। वैदेशिक-कार्य मंत्री ने हमें बताया कि हमारा अपना प्रदेश हमें लौट आयेगा।

प्रधानमन्त्री ने एक बार कहा कि कैलाश और मानसरोवर एक दिन हमारे पास होंगे। हम चीन से उन्हें हस्तांतरित करने को कहेंगे। यह सरकार कहां पहुँची है ? क्या वे कोई कार्यवाही कर रहे हैं या अपनी ही भूमि को अपने अधिकार में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ? क्या आप मन्त्री महोदय से यह बताने को कहेंगे ? (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शांति। मन्त्री महोदय उत्तर दे चुके हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान आपको सभा की तथा देश की सहायता करनी चाहिए।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : हमारी अचल सम्पत्ति हमारे पास आने से चल सम्पत्ति बन गई है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। श्री दी० चं० शर्मा

श्री दी० चं० शर्मा : क्योंकि कोलम्बो प्रस्तावों के आधार पर बातचीत होने की सम्भावना धूमिल सी हो गई है तथा इसके परिणाम हम लोगों में से बहुतों के जीवन काल में शायद ही निकलें क्योंकि चीन हमारे प्रति अपनी शत्रुता बढ़ाता जा रहा है, चीन के प्रति इस प्रकार का नरम रुख दिखाने और उसे यह अनुभव कराने का कि भारत हमेशा आक्रमण की अपेक्षा सुरक्षात्मक स्थिति में रहेगा क्या लाभ हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : चीन का रुख वास्तव में नकारात्मक रहा है यद्यपि उन्होंने कुछ और ही बहाने बनाये और यह भी एक तथ्य है कि चीन अभी भी हमारे प्रति शत्रुता का रुख बनाये हुये हैं। इसलिये इससे हमारे ऊपर अपनी तय्यारियां करने का एक और बड़ा बोझ आ जाता है।

किन्तु इसके साथ ही हमें ऐसा रुख नहीं अपनाना चाहिये जिससे यह प्रतीत हो कि हम किसी भी स्थिति में वार्ता करने को तैयार नहीं है ।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, I would like to know from the hon. Minister, that we are in the habit of talking more of negotiations rather than, policy, basis, principles and pledges in our country. May I know whether the attention of the hon. Minister has been drawn to the recent statement of the Prime Minister in respect of Kailash and Mansarovar wherein she stated that we have our religious and cultural rights there ? It was a good statement and we should also get opportunities to appreciate at times. India as a whole would try to establish those rights May I further know whether the hon. Minister is aware that in a letter we discussed with China regarding a village named Mansar census records and land taxes etc. of which were sent to India ? May I know whether the note regarding Mansar village and the statement of Shrimati Indira Gandhi would be taken into consideration and keeping in view all the facts whether some policy would be thrashed out when negotiations take place.

Shri Swaran Singh : Yes, All these factors will be taken into consideration.

श्री रंगा : सरकार द्वारा भूतकाल में दिये गये आश्वासनों को ध्यान में रखते हुये, क्या सरकार का विचार ऐसी नीति बनाने का है जिससे हमारी भूमि पुनः हमारे कब्जे में आ जाये अथवा यही नीति बनाए रखी जायेगी कि प्रार्थना करते रहो भूमि मिल जायेगी ।

श्री स्वर्ण सिंह : इरादा यह है कि जितने क्षेत्र पर गैर कानूनी अधिकार किया गया है वह सर्व प्रथम बातचीत के द्वारा हमको मिलना चाहिये । यही वर्तमान स्थिति है । हमको दूसरे पहलुओं को नहीं अपनाना चाहिये जब तक ये सम्भावनायें समाप्त नहीं हो जातीं ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यह गलत उत्तर है । मंत्री महोदय कहते हैं "इसे हमारे पास आना चाहिये ।" क्या यह उचित वाक्यांश है । पृथ्वी अपने आप नहीं घूमती । हमको ही वहां जाना है और उस पर कब्जा करना है । क्या यह भूखंड हमारे पास चला आयेगा ।

अध्यक्ष महोदय : हमको बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिये । उन्होंने कहा हम पहिले बातचीत करेंगे यही वर्तमान स्थिति है । फिर दूसरे कदम उठाये जायेंगे ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : प्रश्न यह नहीं है कि यह हमारे पास आयेगा बल्कि क्या इसे हम प्राप्त करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह स्पष्ट किया है । पहिले हम बातचीत द्वारा प्रयत्न करेंगे और यही वर्तमान स्थिति है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह चीनियों द्वारा भूदान जैसा कुछ है ? यह हमारे पास कैसे आयेगा ?

Shri Ram Sewak Yadav: Mr. Speaker, the hon. Minister has stated that the territory occupied by China will some day come to us. How much time will it take, has this been thought over ? When will it come, with in one year, two years or four years ? Some time limit should have been fixed for this.

Shri Swaran Singh : No, no time has been thought over.

Shri Kishen Pattnayak: May I know whether the Government expects that China would agree to Colombo Proposals ? What efforts has our Prime Minister made to bring about that agreement.

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने यह नहीं कहा कि चीन से कोलम्बो प्रस्तावों को मानने की आशा की जा सकती है । मैंने दर असल यह कहा है कि वर्तमान संकेतों के अनुसार वे सम्भवत: इसे स्वीकार नहीं करेंगे । यद्यपि बाहरी तौर से वे उन्हें सिद्धान्त रूप में स्वीकार करने की बात करते हैं, तथापि उन्होंने इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाये । इसी दर्मियान यह कोलम्बो राष्ट्रों पर निर्भर करता है कि वे इस सम्बन्ध में कोई पहल करें । हम अपनी ओर से दूसरे राष्ट्रों से चीन के कोलम्बों प्रस्तावों को कार्य रूप देने के लिए नहीं कहलवाना चाहते ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार इस ऐतिहासिक तथ्य को जानती है कि जो लड़ाई के मैदान में खोया और जिसे युद्ध से प्राप्त नहीं कर सकते वह वार्ता के द्वारा ही मिल जायेगा ? यदि ऐसा है तो वर्तमान स्थिति में वार्ता का यह हास्य क्या चल रहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीमान मैं माननीय सदस्य के निराशावाद से असहमत हूँ (व्यवधान) ।

श्री वासुदेवन नायर : यह ध्यान में रखते हुये कि भारत चीन विवाद का कोई स्थाई हल निकट भविष्य में दृष्टिगोचर नहीं होता तथा भारत अपने पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध सुधारने में रूचि रखता है, क्या सरकार ने कभी चीन के साथ युद्ध वर्जन सन्धि प्रस्तावित करने के औचित्य के बारे में सोचा है जैसा कि पाकिस्तान के बारे में सोचा गया ?

श्री स्वर्ण सिंह : नहीं श्रीमान, हमने ऐसा न सोचा है और न आगे इन दिशाओं में सोचने का इरादा है ।

Shri Bade : Mr. Speaker, just now the hon. Minister has stated that China is not prepared to agree to Colombo proposals and he has also said that the Government has still been sticking to it. I would like to say that four years have elapsed from 62 to 66 and China is not prepared so far. Are the Government of India prepared to place some fresh proposals in the hands of Colombo Powers in order to do something further.

Shri Swaran Singh : The Colombo Powers have actually been exchanging views from time to time. But they have given a proposal. Now, China does not agree to that, what can we say to them for that ? It is difficult for us to say to Colombo Powers that they should do anything further.

भूतपूर्व सैनिकों के लिये रोजगा

*152. **श्री विभूति मिश्र :** **श्री क० ना० तिवारी :**

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में 20 प्रतिशत और तृतीय श्रेणी की सेवाओं 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अ० म० थामस) :

(क) जी हां ।

(ख) सरकारी आदेश 4 जुलाई 1966 को जारी किए गए थे । भर्ती के नियमों का संशोधन किया जा रहा है, और इन आदेशों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया बनाई जा रही है ।

Shri Bibhuti Mishra : I would like to know whether how many men are there of whom 20 percent would be employed in IV Class and 10 percent would be employed in III Class. How will they arrange this proportion ? Will there be some interview or will they be taken on adhoc basis.

श्री अ० म० थामस : श्रीमान, साधारणतया हम इन रिक्त स्थानों की सूचना रोजगार दिलाऊ दफ्तरों को देते हैं और हम उन लोगों में से ही नियुक्त करते हैं जिनके नाम रोजगार दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा भेजे जाते हैं। जहां तक रिक्त स्थानों का सम्बन्ध है कुछ प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिये सुरक्षित रखे जाते हैं जिसकी सूचना रोजगार दिलाऊ दफ्तरों को खासतौर पर दी जाती है तथा उन्हें इन व्यक्तियों के नाम भेजने ही होते हैं। जैसा कि मैंने प्रश्न के मुख्य उत्तरांश में बताया है कि नियमों को संशोधित किया जा रहा है तथा इनके कार्य रूप में परिणित करने के लिये विस्तृत प्रक्रिया को अन्तिम रुप दिया जा रहा है।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether the Government has assessed the number of persons who will be employed by absorbing 10 percent in Class III and 20 percent in Class IV and what is their Total.

श्री अ० म० थामस : श्रीमान, भूतपूर्व सैनिकों की सम्पूर्ण संख्या के बारे में एक दूसरा प्रश्न भी है। शायद मैंने उसका जवाब दिया है। हमारे पास भूतपूर्व सैनिकों की संख्या की सूचि नहीं है तथा विभिन्न शाखाओं से भूतपूर्व सैनिकों का विवरण एकत्र करना कठिन है। जहां तक अन्दाजा लगाने का प्रश्न है हम अभी कोई पक्का अन्दाजा नहीं लगा पाये। सदस्यगण अनुभव करेंगे कि अब हम आर्थिक कार्यवाहियों के अन्तर्गत तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों के पदों की संख्या कम से कम करना चाहते हैं। यह प्रतिबन्ध भी लगा है। किन्तु इसके अन्तर्गत ही हम भूतपूर्व सैनिकों के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। हमने बहुत सी राज्य सरकारों को भी लिखा है कि इसी तरह का कोटा भूतपूर्व सैनिकों के लिये नियत करें। सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों को भी इतना ही कोटा सुरक्षित रखने के लिये लिखा जा रहा है।

श्री क० ना० तिवारी : उन योजनाओं को केन्द्रीय सरकार की अपेक्षा राज्य सरकारों को ही अधिक क्रियान्वित करना है। इसलिये क्या मैं जान सकता हूँ कि राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया भी इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई है ?

श्री अ० म० थामस : उनसे भी इसी प्रकार के पदों में नियुक्ति के लिये भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवा में सुरक्षित स्थान रखने के लिये कहा गया है।

Shri Yashpal Singh : Will the Government be able to tell that the exsoldiers who have got employment in U. P. They have to pay 25 percent revenue as land revenue and irrigation tax and this is 10 % more from exsoldiers who were employed. Will the U. P. Government be asked to exempt them for this 25 percent revenue ?

श्री अ० म० थामस : यह मेरे ध्यान में नहीं आया। मैं इसकी जांच करूंगा।

Shri Yashpal Singh : Will this question be taken as notice ?

Mr. Speaker : It will be taken as notice.

Shri Shiva Narayan : Are Government employing only those who are below 40 or those above 40 are also being employed ?

श्री अ० म० थामस : अभी छंटनी किए गए भूतपूर्व सैनिकों को सेना में उनकी सेवा-काल के अनुसार उम्र की रियायतें दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त तीन साल और जोड़ दिये जायेंगे।

Shri Sarjoo Pandey : As the hon. Minister has just now stated that the State Governments do not provide employment to ex-Servicemen inspite of the repeated reminder of the Defence Ministry. What action are the Central Government taking to implement this decision so far as State Governments are concerned ?

श्री अ० म० थामस : यह ठीक है कि पहले भी निर्देश दिये गये हैं। रोजगार दिलाऊ दफ्तर भी उन भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता देते हैं। मेरा विचार है कि हाल के आदेशों एवं नियुक्ति के लिये विस्तृत प्रक्रिया नियमों के निर्धारित होने के बाद स्थिति सुधरेगी।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या सरकार ने इन भूतपूर्व सैनिकों की युद्ध सेवा को भी उन विभागों में जहां वे 20 तथा 10 प्रतिशत कोटे के अनुसार रखे जाते हैं वरीयता के लिये आंकने का निर्णय किया है ?

श्री अ० म० थामस : यही विचार है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I would like to know whether Government has a Scheme to rehabilitate those ex-servicemen who are not in Government Service and are agriculturists and who should be allotted land for cultivation.

Mr. Speaker : This question relates to services.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It is for providing them jobs. I have, therefore, asked with regard to cultivators. Probably they have some plan for this.

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रस्ताव है ?

श्री अ० म० थामस : जमीन दिये जाने के बारे में पहिले भी उत्तर दिया गया है। योजनाओं के कुछ पहलू भिन्न हो सकते हैं, सभी राज्य सरकारों की भूतपूर्व सैनिकों को भूमि देने की अपनी-अपनी योजनायें हैं।

श्री हरिविष्णु कामत : मेरा विश्वास है कि सभा सरकार के इन भूतपूर्व सैनिकों के लिये आवश्यक व्यवस्था करने के निर्णय का स्वागत करेगी। क्या यह भी सच नहीं है कि आजाद हिन्द फौज, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की शानदार आजाद हिन्द फौज के लगभग 95 प्रतिशत सैनिक स्वतन्त्रता के पिछले 17 या 18 सालों में तथा आज भी बेरोजगार हैं ? यदि ऐसा है तो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के लोगों के लिये सरकार क्या ऐसा ही व्यवहार करने की व्यवस्था कर रही है।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : क्या मैं इस सम्बन्ध में कुछ कह सकता हूँ ? प्रश्न केवल भूमि वितरण की योजना का नहीं हैं अपितु इन योजनाओं के लिये भूमि प्राप्य होने का भी है। राज्य सरकारों के पास विभिन्न प्राथमिकतायें होती है। कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों एवं शरणार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। आजाद हिन्द फौज के लोगों के बारे में मुझे अपने राज्य प्रशासन का अनुभव याद आता है। हमने कुछ प्राथमिकता उनके लिये निर्धारित की थीं किन्तु वे सब कागजी ही रहीं।

श्री हरिविष्णु कामत : केवल महाराष्ट्र में ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं केवल यह कह रहा हूँ कि जहाँ हमने उन्हें कुछ प्राथमिकतायें दी थी, वही कागजी प्राथमिकतायें रहीं ।

श्री हरिविष्णु कामत : अतः मेरा प्रश्न निरुत्तर रहा । मेरा प्रश्न था कि क्या कोई ठोस योजना है ? वे मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे सकते ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि यह कागजी ही रही ।

श्री हरिविष्णु कामत : इसका अर्थ है कि वे ठोस योजनाओं को कार्य रूप में परिणत नहीं करना चाहते । क्या कारण है ?

श्री बड़े : प्रश्न और उत्तर भी एक ही है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रश्न श्री कामत ने रखा था न कि श्री बड़े ने ।

श्री हरिविष्णु कामत : चूंकि आपने मुझे शांत रहने को कहा है, मैं आपके विनिर्णय का पालन करूँगा । परन्तु यह सरकार है जिसको कि शांत रहने के लिये कहा जाना चाहिये । यदि उसकी कोई ठोस योजनाएँ हैं तो उनका उल्लेख होना चाहिये । अन्यथा उसको कोई भी योजना न होने के कारण देने चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री कामत से सहमत हूँ ।

श्री हरिविष्णु कामत : श्रीमन्, यदि आप मुझ से सहमत हैं तो आपको इस सभा की रक्षा करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से कह रहा हूँ ।

श्री हरिविष्णु कामत : आप उनको अभी कहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री प्रिय गुप्त : आपकी निगाह पड़ने के लिये क्या अर्हतायें हैं ? मैं कई बार खड़ा हुआ, परन्तु दुर्भाग्य से आपकी निगाह मुझ पर नहीं पड़ सकी·····(**अन्तर्बाधा**)

श्री शिव नारायण : यह अध्यक्ष महोदय पर आक्षेप है ।

श्री प्रिय गुप्त : आपने मुझे नहीं बुलाया ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा हो गया होगा । मैं क्या कर सकता हूँ ? मैं सभी को तो नहीं बुला सकता ।

Shri Priya Gupta : You have called so many from Congress.

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों के लिये ये आक्षेप लगाना गलत है । सदस्यों को ऐसा नहीं करना चाहिये । कितने सदस्य मैंने कांग्रेस के बुलाये हैं और कितने प्रतिपक्षी दलों के बुलाये हैं, अभी देख लीजिये ।

Shri Priya Gupta : To whom shall I narrate my tale of woe if not to you ?

Mr. Speaker : To say how many members have been called from Congress amounts to complaining.

Supply of Arms to India by U. S. A. and U. K.

*153 **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :
Shri Linga Reddy :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri N. R. Laskar :
Shri R. Barua :
Shri Liladhar Kotoki :
Shri R. S. Pandey :
Shri Utiya :
Shri Madhu Limaye ;

Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) Whether the restrictions imposed by the Governments of U. S. A. and U. K. regarding the supply of weapons to India have been relaxed;

(b) if so, to what extent; and

(c) if not, the reaction of Government thereto ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री अ० म० थामस :

(क) से (ग) : पिछले सितम्बर में यू० एस० और यू० के० सरकारों ने भारत को साजसामान देने पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये थे, और उन सरकारों को सूचित किया गया था कि भारत को जो आक्रमण का शिकार हुआ था आक्रमणकारी के समतुल्य न माना जाए। तब से इन प्रतिबंधों में छूट हुई है। फरवरी 1966 में यू० एस० सरकार ने अध्वंसक सामान प्रति मामले में चयनात्मक आधार पर, फिर से देना जारी करने की सूचना दी। यू० के० सरकार ने भी सैनिक सामान देने पर लगाई रोक हटा दी है। रक्षा साजसामान के सम्बन्ध में अपने आपको आत्म निर्भर बनाने के प्रयास के बावजूद भी हमारे लिए बहुत से देशों से विभिन्न प्रकार का रक्षा सामान प्राप्त करना आवश्यक होगा। तदपि, इस दिशा में अपने प्रयास, अथवा उन साधनों को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा, कि जिनसे हम सप्लाई सुनिश्चित करते हैं। ऐसे प्रकटीकरण से सप्लाई सुनिश्चित करने के अपने प्रयास पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

Shri Prakash Vir Shastri : In view of the fact that Britain and America had suspended arms supply to both India and Pakistan in a uniform way, may I know whether it is a fact that despite these restrictions the supply of arms and spare parts to Pakistan is still continuing indirectly as is evidenced from the Press reports to the effect that 4 squadrons of Supersonic Saber Jets have found their way into Pakistan from Canada through Germany and Iran ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : अलबत्ता हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि पाकिस्तान उन उपकरणों को अन्य स्त्रोतों से प्राप्त करने का यत्न कर रहा है, परन्तु जहां तक अमरीकी नीति का सम्बन्ध है, हमें अश्वासन दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को घातक हथियारों की सप्लाई सम्बन्धी अमरीकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या सरकार दूसरे देशों द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिये जाने को रोकने के लिये कोई कदम उठा रही है।

श्री यशवंत राव चह्वाण : यह विशिष्ट तथ्य हमने उनकी जानकारी में ला दिया है और स्वभावतः हम आशा करते हैं कि वे इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करेंगे ।

श्री कपूर सिंह : अमरीकी सेबर जेट विमान पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष रूप से दिये गये हैं । यह प्रश्न किया गया था और इसका कोई सीधा उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस बारे में कोई जानकारी है ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैंने कहा है कि हमें जानकारी मिली है कि पाकिस्तान उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है । कुछ विमान उसको मिल गये हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri : These have already been received.

Shri Y. B. Chavan : I have also said that my information is that Pakistan has received these and from other coutnries.

इस विशिष्ट तथ्य की जानकारी भी हमने अमरीकी सरकार को दे दी है ।

Shri Prakash Vir Shastri : In view of the continuous adhrence of Tashkent spirit by Government of India despite the repeated violations by Pakistan of Tashkent Agreement concluded lately after the Indo-Pak conflict with the object of stabilising peace between the two Countries, may I know whether it is a fact that Pakistan Government is trying to get arms from these two Countries or from other Countries also, such as Russia, if, so, what is the amount of veracity in the statements made by Commander-in-Chief and other Army Officers and whether they have framed any scheme for the future, if not for the present ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हमारी यह जानकारी है कि पाकिस्तान विभिन्न देशों से सैनिक उपकरण प्राप्त करने का यत्न कर रहा है, परन्तु जहां तक रूस का सम्बन्ध है हमें यह आश्वासन दिया गया है कि रूस की ओर से कोई उपकरण नहीं दिये जा रहे हैं ।

Shri M. L. Dwivedi : Have the Government of India drawn the attention of U. S. Government to the flowing of American arms into Pakistan of the laters liking as also to the pouring in of Chinese tanks and arms into Pakistan which runs contrary to the policy of U. S. Government, if so, the reaction of U. S. Government thereto, if not, do Government propose to take up this matter with U. S. Government ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यह एक सुज्ञात बात है । पाकिस्तान सरकार ने भी यह बात मानी है कि वह चीन सरकार से उपकरण प्राप्त कर रही है । उसने हाल ही में प्राप्त किये गये कुछ उपकरणों का खुलेआम प्रदर्शन किया है । मैं समझता हूँ जैसे हमें इसका पता है ऐसे ही अमरीकी सरकार को भी इसका पता है । इस बारे में अमरीकी सरकार को क्या करना चाहिये इसका फ़ैसला निश्चय ही उसको करना है । हमने इस तथ्य की जानकारी उसको दे दी है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Have the Government of India drawn the attention of the Governments of U. S. A. and Britain to the collusion between Pakistan and China on the basis of which China is supplying some arms and nuclear devices to Pakistan as also to the Agreement having the stipulation that if China supplies arms to Pakistan, U. S. A. will give arms aid to India ? Have Government of India conferred with U. S. A. over this matter ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : निश्चय ही उनको इसका पता है । हम भी उनके साथ इस प्रश्न को उठा रहे हैं । इस बारे हम यही कुछ कर सकते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या राष्ट्रमण्डल के हमारे विशिष्ट मित्र ब्रिटेन की अनुकम्पा के सम्बन्ध में चन्द रोज पहले के इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि ब्रिटेन ने अमरीका से कहा है कि चूंकि उसने भारत को हथियारों की अपनी सप्लाई पर प्रतिबन्धों को शिथिल कर दिया है, इसलिये अमरीका को भी पाकिस्तान के सम्बन्ध में ऐसा करना चाहिये ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हमने निश्चय ही इस खबर को देखा है और स्वभावतः अमरीकी सरकार को बता दिया है कि उसे पाकिस्तान को ऐसे हथियारों की सप्लाई आरम्भ नहीं करना चाहिये ।

श्री भागवत झा आजाद : ब्रिटेन से आपने क्या कहा है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या हमारी सरकार निश्चित रूप से जानती है कि ये सेबर जेट विमान किस देश में हैं, क्या वे पश्चिम जर्मनी और ईरान के रास्ते आये हैं अथवा क्या वे उत्तर अटलाँटिक संधि संगठन के अन्तर्गत दिये गये किन्हीं सेबर जेट विमानों का एक भाग हैं या किसी सैनिक सन्धि द्वारा ईरान को दिये गये हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इसका पता है कि इस प्रकार के उपकरण तुर्की और ईरान दोनों द्वारा अन्य करारों के अन्तर्गत अमरीका से सहायता के रूप में प्राप्त होते हैं । परन्तु यह निश्चित है कि उनको ये इन देशों द्वारा प्राप्त हो रहे हैं । यह हमारी जानकारी है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : किस करार के अन्तर्गत वे अब उनको पाकिस्तान को बेच रहे हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है कि किस करार या किन शर्तों के अन्तर्गत ऐसा है । बात यह है कि इनका हस्तान्तरण किया जा रहा है । तथ्य यह है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : पाकिस्तान सरकार ने, एक घोर झूठ द्वारा कि भारत निकट भविष्य में अणु विस्फोट करने वाला है, विश्व मत पर फिर से प्रभाव डालना आरम्भ कर दिया है । क्या सरकार ने अपनी नीति अमरीका को स्पष्ट कर दी है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं समझता हूँ कि इस बारे में हमारी नीति बहुत स्पष्ट है और समय-समय पर इसको स्पष्ट कर दिया गया है ।

Shri Rameshwaranand : Have Government of India sent any protest note to America, the source of these Sabre jets and military equipment as also to other Countries receiving these equipments in aid from America and transmitting further the same in aid to Pakistan ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : अवश्य ही हम उन देशों से लिखा पढ़ी करते हैं ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : विभिन्न देशों द्वारा पाकिस्तान को नियमित रूप से सेबरजेट विमानों के दिये जाने को ध्यान में रखते हुए उन देशों से सेबरजेट विमान प्राप्त करने में हमें क्या कठिनाइयां हैं जो पाकिस्तान को ये विमान दे रहे हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : कठिनाई केवल यही है कि वे देश हमें नहीं देते ।

Shri Madhu Limaye : Is the hon. Minister prepared to lay on the Table a statement showing the details of the arms received by Pakistan from all the allies of U. S. A. and Britain under the various military alliances after the Tashkent accord, so that the people of India and the world may know as to what is happening ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इस बारे में कुछ जानकारी हमारे पास है और हमें समय-समय पर जानकारी मिलती रहती है। मैं नहीं समझता कि इस बारे में सारा ब्यौरा देना आवश्यक है अथवा हमारे हित में है।

Shri Rameshwaranand : Sir, I rise on a point of order. The hon. Minister is giving evasive replies. When we raise our voice you call us to order, you should also direct them to come prepared.

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister stated that it is not in the public interest to give details. It is for the hon. Members to decide whether it is in the public interest or not and not for the Minister. We must get this information.

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीन और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के कई और देश पाकिस्तान को हथियार, गोलाबारूद और विमान देकर खुले आम युद्ध की आग को भड़का रहे हैं, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद और अमरीका और ब्रिटेन जैसे मित्र देशों का ध्यान इसकी ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण: मैं व्यक्तिगत रूप से यह आवश्यक नहीं समझता कि सुरक्षा परिषद् को इसकी सूचना दी जाये क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जिनका उनमें से अधिकांश को पता है। प्रश्न यह है कि कभी-कभी सप्लाई करने वाले देश गैर सरकारी सौदों द्वारा भी ये सामान देते हैं। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमें भी विभिन्न देशों से उपकरण प्राप्त करने हैं। अतः यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर हम लिखा-पढ़ी कर सकते हैं।

चीन के प्रति अमरीका का रवैया

*154 **श्रीमती रेणुका राय** :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद।
श्री रिशांग किशिंग :
श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के प्रति अमरीका के रवैये में कोई परिवर्तन होने की जानकारी सरकार को मिली है, और

(ख) यदि हां, तो इससे भारत-अमरीकी सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख) : चीन के प्रति अमरीका की नीति में कोई परिवर्तन होने के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

श्रीमती रेणुका राय : क्या सरकार का ध्यान, अमरीका समाचार पत्र सम्पादक संस्था के प्रतिरक्षा सचिव द्वारा दिये गये उस वक्तव्य पर दिलाया गया है जिसमें यह सुझाव है कि व्यापार और मण्डियों की खातिर चीन के प्रति अमरीका के रवैये में परिवर्तन होना चाहिये।

श्री स्वर्ण सिंह : जी, हां। अमरीका में अनेक महत्वपूर्ण लोगों द्वारा ये सुझाव दिये गये हैं कि उनको अपनी अकेलेपन की नीति में परिवर्तन करना चाहिये और कुछ मत भेदों को दूर करने

का प्रयत्न करना चाहिये। ये विचार व्यक्त किये गये हैं, परन्तु नीति संबंधी परिवर्तन की हमें जानकारी नहीं हैं।

श्रीमती रेणुका राय : क्या सरकार जानती है कि इसका प्रभाव, पाकिस्तान-चीन करार की ओर नर्मी के रवैये, भारत के विरुद्ध हथियारों के प्रयोग के सम्बन्ध में सीटो करार के अपमान और पाकिस्तान को फिर से हथियार देने के सम्बन्ध में हाल की नीति में देखा जाता है ? क्या सरकार इस परिवर्तन को अनुभव करती है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि चीन के प्रति अमरीका की नीति में किसी परिवर्तन से इसका कोई सम्बन्ध है। कुछ अन्य भी कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ का उल्लेख मेरे साथी प्रतिरक्षा मंत्री ने किया है।

Shri Siddheshwar Prasad : Have Governnment of India conferred with the U. S. Government regarding the suggestion put forth before U. S. Government for bringing about change in U. S. Policy towards China and if that change is to be there what will be its bearing on our relations ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस विषय पर अमरीकी सरकार या उसके प्रतिनिधियों से हम री कोई बातचीत नहीं हुई है। परन्तु हमारा हमेशा ही यह मत रहा है कि किसी देश को और विशेष रूप से इतनी बड़ी आबादी वाले देश को अलग थलग करने की नीति उस देश के या अन्तर्राष्ट्रीय शांति के हित में नहीं है।

श्री प्रिय गुप्त : इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि अमरीका चाहता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में रूस का प्रभाव न बढ़े और इसलिये अमरीकी सरकार भारत को केवल उतनी ही सहायता देना चाहता है जितनी कि चीन के प्रभाव को रोकने के लिये आवश्यक है और इसलिये अमरीका इसमें रुचि नहीं रखता है दक्षिण पूर्व ऐशिया में भारत अधिक ऊँचा उठे और इसलिये अमरीका कभी सहायता को घटा देता है और कभी बढ़ा देता है, क्या भारत सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और अमरीकी सरकार से पूछा है ?

श्री स्वर्ण सिंह: पूरे ध्यान से सुनने के बावजूद भी मैं नहीं समझ पाया कि प्रश्न क्या है। मैं इसको समझने की कोशिश करूँगा।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को फिर से सैनिक सहायता का दिया जाना

\+

*155. **श्री किशन पटनायक :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री पन्नालाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ताशकन्द समझौते के बाद अमरीका पाकिस्तान को विशेषकर हथियारों की सहायता और आमतौर पर सैनिक तैयारी (सैनिक हवाई अड्डों राडार उपकरणों, संचार साधनों आदि) के मामले में किस प्रकार का सहयोग दे रहा है;

(ख) पाकिस्तान और चीन के भारत-विरोधी खतरनाक रवैये की विशेष पृष्ठ भूमि में, क्या सरकार ने अमरीकी सरकार का ध्यान उन गम्भीर परिणामों की ओर दिलाया है जो पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की फिर से सहायता दिये जाने के परिणामस्वरूप निकल सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : हमें अमरीका और पाकिस्तान के बीच ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद खास तौर से हथियारों की सहायता और आमतौर से सैनिक तैयारी के क्षेत्र में कोई नया "सहयोग" होने की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) : हमने अमरीका की सरकार को राजनयिक सूत्रों के जरिये अपने विचारों से अवगत करा दिया है । अमरीकी अधिकारियों ने हमें सूचना दी है कि पाकिस्तान को घातक हथियार नहीं दिए जा रहे हैं । हमें आगे यह बताया गया है कि अमरीका की सरकार ने "नकद दो ओर माल ले जाओ" (कैश एंड कैरी) के आधार पर भारत और पाकिस्तान को सीमित स्तर पर गैर-घातक सैनिक उपकरण देने का फैसला किया है ।

Shri Kishan Pattnayak : The hon. Minister has stated that U. S. A. is not giving any arms aid to Pakistan at present. Is it not the duty of the new U. S. Ambassador Shri Eugene Black to enter into negotiations with the Government of Pakistan regarding resumption of arms aid at least in the matter of spare parts to Pakistan. If so and if the supply of spare parts is resumed, then what will be the reaction of the Government of India in this regard ?

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान में नियुक्त किये गये नये अमरीकी राजदूत के उक्त कार्य की न ही मैं पुष्टि करता हूँ और न ही खण्डन ही करता हूँ । माननीय सदस्य इसका कोई भी अर्थ लगा सकते हैं । इस मामले में मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ ।

Shri Kishan Pattnayak : This was a news item in the Washington Post.

Shri Madhu Limaye : On a point of order, Sir !

श्री स्वर्ण सिंह : जहाँ तक अन्य प्रश्न का सम्बन्ध है, हमारा सदा यह मत रहा है कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता दिये जाने से निश्चय ही तनाव बढ़ेगा और अमरीका की इस कार्यवाही को भारत बिल्कुल पसन्द नहीं करेगा ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, on a point of order, Sir, I want to know why does the Minister feel it necessary to express his ignorance again and again. We are unable to understand all this. Our embassies are there both in Pakistan and Washington. After all what is the use of spending so much money on them ? If such a news appear in the newspapers of America and if this is not brought to the notice of the Ministry of External Affairs by our embassies then I would say that he is not fit for this post. He always tries to evade question. You may please give your final decision about this matter. We cannot proceed further like that.

Shri Bade : To day, this news has also appeared both in Hindi and English news-

papers. "The American Ambassador in Pakistan is trying to get more spare parts for Pakistan.

Mr. Speaker : He says that this has appeared both in Hindi and English newspapers. He might have also read it.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : He has not read ; He does not read them before he comes here.

Mr. Speaker : What information he should give on behalf of the Government on that basis.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इसके अलाबा एक और बात भी है। उन्होंने कहा है कि जब वैदेशिक कार्य मंत्रालय से इस बात की चर्चा की गई तो उनमें कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। ऐसा भी एक वक्तव्य है।

श्री स्वर्ण सिंह : इस बारे में हमारी बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया है। वास्तव में मेरी यह तीव्र प्रतिक्रिया श्री मधु लिमये की पसन्द की नहीं है।

Shri Madhu Limaye : You are treating this matter very lightly. You do not take any constructive steps in the matter.

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने कहा कि यदि अमरीका अब पाकिस्तान को सैनिक सामान देता है तो यह हमारे हितों तथा शान्ति के हितों के विरूद्ध होगा। सौभाग्य से विदेश मंत्री के रूप में बने रहने के लिए मैं श्री मधु लिमये की सदभावना पर निर्भर नहीं हूँ।

Shri Madhu Limaye : This much we also know. You always say like that. There is a question of ignorance. What about that.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : जो प्रश्न पूछा गया है वह यह है : अमरीका के तथा भारत के समाचार पत्रों ने जो जानकारी संसार को दी है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा क्यों है कि हमारे विदेश मंत्री, जिनको समाचारपत्रों वालों से अधिक जानकारी होनी चाहिये, इस प्रकार का उत्तर देते हैं ? उन्होंने जो उत्तर दिया है उससे उनकी अज्ञानता का पता चलता है तथा वह प्रश्न का उचित उत्तर नहीं है। यदि अन्य लोग इस बात को जानते हैं तो मेरे विचार में यह कहना हमारे लिये उचित नहीं है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमारे राजदूत तथा अन्य लोग वहां पर हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी धारणा फैले कि सरकार को इन बातों की जानकारी ही नहीं है। परन्तु आप ने ठीक ही कहा है कि समाचारपत्रों से जानकारी प्राप्त करना एक बात है और कराची तथा न्यू यार्क में स्थित हमारे राजनयिक मिशनों से अग्रेतर और जानकारी प्राप्त करना दूसरी बात है। इस बारे में यह मेरे साथी प्रतिरक्षा मन्त्री द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि हम अमरीकी अधिकारियों से लिखा-पढ़ी कर रहे हैं और उनको अपनी राय भेज दी है। हमें आश्वासन दिया गया है कि उन्होंने पाकिस्तान को किसी प्रकार के हथियार अथवा कोई सैनिक सामान देना स्वीकार नहीं किया है।

श्री हरि विष्णु कामत : मन्त्री महोदय ने न्यू यार्क में स्थित हमारे राजनयिक मिशनों का उल्लेख किया है। क्या यह न्यू यार्क में है अथवा वाशिंगटन में ?

अध्यक्ष महोदय : उनका आशय वाशिंगटन से था।

श्री स्वर्ण सिंह : न्यू यार्क तथा वाशिंगटन दोनों में हमारे मिशन हैं

श्री हरि विष्णु कामत : उनको यह जानकारी कहां से मिली थीं, न्यू यार्क से अथवा वाशिंगटन से ?

श्री स्वर्ण सिंह : दोनों स्थानों से ?

Shri Kishan Pattnayak : Mr. Dean Rusk while supporting the policy of giving arms aid both to India and Pakistan said in the Committe on Foreign Affairs of the American House of Representatives that military aid was being given to India against China but so far as the question as to why arms aid is being given to Pakistan is concerned, he would not say anything about that openly. Has the Government of India tried to ascertain this fact as to against whom America is giving arms aid to Pakistan.

Shri Swaran Singh : I have replied that except non-lethal weapons they are not giving any arms aid to Pakistan.

Shri Kishan Pattnayak : What ?

Mr. Speaker : The Government of America says that they are not giving any arms aid to Pakistan.

Shri Kishan Pattnayak : It is their policy to give arms aid to Pakistan. It is a different thing if it has been discontinued temporarily for some days. They were giving it in the past and they will give in the future also. It is quite clear. If they have no information, let them say that they have no information about it.

श्री स्वर्ण सिंह : पहले अवसरों पर यह सुज्ञात था और सभा में भी यह बताया गया है कि 1954 से अमरीका ने पाकिस्तान को विपुल मात्रा में सैनिक सहायता दी थी क्योंकि पाकिस्तान सीटो तथा सेटों का सदस्य था और अब भी वह इन संस्थाओं का सदस्य है। यह सहायता पाकिस्तान तथा अमरीका के बीच 1954 में हुए परस्पर प्रतिरक्षा सन्धि के अन्तर्गत दी गई थी।

श्री कृ० चं० पंत : क्या सरकार घातक तथा गैर-घातक हथियारों के बीच भेद करने को ठीक समझती है और क्या सरकार यह जानती है कि वह किस प्रकार के हथियार हैं जो अमरीकी सरकार पाकिस्तान को गैर-घातक हथियारों के रूप में देती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह कहना बिल्कुल ठीक है क्योंकि गैर-घातक हथियारों से भी प्रतिरक्षा-क्षमता इतनी बढ़ती है, अत: यह जो भेद किया गया है वह इतना कारगर नहीं है। जिस प्रकार के हथियार दिये जाते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी है परन्तु मेरे पास अभी इनकी आधार-सामग्री नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Pakistan has been successful in getting weapons from America, Russia, China and Iran. In this context may I know whether Government is making any efforts to this effect that Pakistan gets the least number of weapons from America.

Shri Swaran Singh . Yes, we will definitely make efforts to that effect.

श्री नारायण दास : क्या सरकार ने इस बात का पता लगा लिया है कि पाकिस्तान अपनी विदेश नीति निर्धारित करने में कौन-सी प्रविधि अपना रहा है, जिससे वह एक ओर तो अमरीका से और दूसरी ओर चीन से हथियार प्राप्त कर सके और अब तो वह रूस से भी हथियार प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस पर टिप्पणी करना मेरे लिये बहुत कठिन है। ऐसा हो सकता है कि ऐसी नीतियां अपनाने से, जिनमें परस्पर विरोधी बातें हों, कुछ देशों को थोड़े समय के लिये कुछ लाभ हो जाय, परन्तु इनको लम्बे अर्से तक जारी नहीं रखा जा सकता।

Shri Rameshwaranand : The hon. Minister has just said that America is not giving arms aid to Pakistan. Even when Pakistan has entered into an agreement with China who is an enemy of America. America has good relations with Pakistan. In this context may I know as to how does the Minister say that America is not giving any arms aid to Pakistan.

Shri Swaran Singh : On the basis of information which I have.

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार का ध्यान पेन्टगोन के एक विशेषज्ञ के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत के मामले में गैर-घातक हथियारों की परिभाषा ट्रक, मिट्टी हटाने वाली मशीनें इत्यादि है, पाकिस्तान के मामले में गैर-घातक हथियारों का अर्थ लगाना पेन्टगोन का काम है, चाहे वह इनकी कुछ ही परिभाषा दें ?

श्री स्वर्ण सिंह : अमरीकी प्रतिरक्षा-सेना के प्रतिनिधि का वह विवरण विशेष तो मेरे पास नहीं है परन्तु मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विभिन्न देशों से व्यवहार करते समय गैर-घातक हथियारों की अलग-अलग परिभाषा नहीं हो सकती।

श्री भागवत झा आजाद : अमरीका के मामले में ऐसा नहीं है।

Shri Yashpal Singh : Will the hon. Minister be pleased to state the measures, other than sending protest note which can be adopted to prevent America from giving arms aid to Pakistan.

Shri Swaran Singh : If the hon. Member has any in view, he may let us know. We are ready to adopt it.....(**Interruptions**)

श्री शिवजीराव शं देशमुख : अब जबकि अमरीका से भारत अथवा पाकिस्तान को गैर-घातक हथियार मिलने आरम्भ हो गये हैं क्या सरकार के पास अन्य देशों से हथियार प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को वहां भेजने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूँ कि वह बाहर से मंगाये जाने वाले हथियारों के सम्बन्ध में कार्यक्रम अथवा योजना का ब्योरा देने के लिए सरकार को मजबूर न करें।

Shri Madhu Limaye . The American authorities used to say that they were arming Pakistan against Communist China. There are only two big Communist Countries, one is Russia and the other is China. So far as Russia is concerned, Pakistan dare not do anything against it and so far as China is concerned, Pakistan is trying to have good relations with it. It is clear from the statement made by Dr. Dean Rusk that America proposes to give arms aid to Pakistan against India. Will the Minister place these facts before the people of America and also the peoples of the world and point out that to give arms aid to Pakistan now will be against India ?

Shri Swaran Singh : The hon. Member has rightly pointed out and it is also right that Pakistan had got the American weapons on the plea that they would use them against communism. It is now well known as how these weapons were used by them. The voice of Shri Madhu Limaye might also reach them and have its own effect on them.

चीन द्वारा परमाणु विस्फोट

*156. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **डा० म० मो० दास :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री विभूति मिश्र :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री गुलशन :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन द्वारा किये गये परमाणु विस्फोट की जांच से किसी ऐसे थर्मोन्यूक्लियर पदार्थ का पता लगा है जिससे इस बात के संकेत मिलते हों कि उसने अपने पहले हाइड्रोजन बम का विस्फोट कर लिया था ; और

(ख) अब तक की गई जांच के अन्य क्या-क्या महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (डा० सरोजिनी महीशी) :

(क) विस्फोट की जाँच से पता लगा कि परमाणु अस्त्र में थर्मोन्यूक्लियर पदार्थ मौजूद थे लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि अस्त्र हाइड्रोजन बम था ।

(ख) जांच के अन्य महत्वपूर्ण परिणाम हैं :—

(i) अस्त्र में काम में लाया गया खंडनीय पदार्थ यूरेनियम -235 था ।

(ii) अस्त्र में यूरेनियम -238 टैम्पर (केसिंग) का प्रयोग किया गया ।

(iii) अस्त्र में लिथियम -6 मौजूद था ।

(iv) अस्त्र का विस्फोट भूमि के स्तर पर नहीं किया गया ।

(v) अस्त्र की विस्फोटक शक्ति 100-200 किलोटन शक्ति के बीच थी ।

(vi) भारत में भूमि के स्तर पर रेडियोधर्मी धूलि न के बराबर गिरी तथा इससे स्वास्थ्य के लिए कोई विशेष खतरा पैदा नहीं हुआ ।

श्री भागवत झा आजाद : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परमाणु अस्त्र का बहुत ही अधिक महत्व है, क्या प्रधान मंत्री ने प्रतिरक्षा विशेषज्ञों को चीन के विरुद्ध इस देश की सामरिक व्यवस्था को नया रूप देने अथवा नवीकरण के आधार पर सोचने के लिये कहा है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं सभा में पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी सामरिक व्यवस्था निरंतर रुप से पुनर्विलोकनाधीन रहती है तथा इस मामले का ब्योरेवार अध्ययन भी किया जा रहा है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या हमें इस नये अस्त्र के बारे में और भी जानकारी है और क्या चीन ने इन हथियारों को निशाने पर गिराने की व्यवस्था में दक्षता प्राप्त कर ली है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस बारे में हमारे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है परन्तु यह स्पष्ट है कि वे एक बहुत ही बड़ा बम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैं नहीं जानती कि अस्त्रों को निशाने पर गिराने की व्यवस्था में उन्होंने कितनी दक्षता प्राप्त कर ली है ।

Shri M. L. Dwivedi : It is observed from the fresh press reports that there is going to be a nuclear collusion between China and Pakistan. It is perhaps because of the fact that Pakistan has created misunderstanding among the peoples that India is going to explode a nuclear device. May I know the stand which would be taken by the Government of India if China helped Pakistan in the manufacture of nuclear weapons ?

Shrimati Indira Gandhi : We cannot stand in their way. But it is yet to be seen as to how they will help. If they supply only bombs it is not known as to whether they would also supply delivery system and other things or not. It is obvious that we are very much perturbed over this matter. I may, however point out that Pakistan had also signed the Partial Test Ban Treaty.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीन निकट भविष्य में एक बहुत ही मजबूत परमाणु बम का विस्फोट करने जा रहा है और यह भी समाचार मिला है कि कलकत्ता के निकट तथा थाईलैंड तथा फिलिपीन जैसे पड़ौसी देशों में रेडियो-धर्मी धूल पाई गई है ? यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० सरोजिनी महीषी : विस्फोट से गिरी रेडियो-धर्मी धूल की जांच की गई है और ट्राम्बे में अणु-शक्ति संस्थान द्वारा इसका विशलेषण किया गया है और उन्होंने जो महत्वपूर्ण परिणाम निकाले हैं वे मैंने सभा में प्रस्तुत कर दिये हैं। पहले प्रश्न के उत्तर में मैं यह कह सकती हूँ कि सरकार जानती है कि वह एक अधिक शक्तिशाली उद्जम बम बनाने जा रहे हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि इस बारे में सरकार की, प्रधान मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। श्री हेम बरूआ।

श्री हेम बरुआ : क्या प्रधान मंत्री यह जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान के बीच अब एक परमाणु समझौता हो गया है और चीन की सहायता से पाकिस्तान 1968 में अपने पहले बम का विस्फोट करने जा रहा है इसीलिये वह भारत पर एक बम का विस्फोट करने की तैयारी करने आदि का आरोप लगा रहा है—और यदि हां, तो भारत के विरुद्ध चीन तथा पाकिस्तान के बीच इस समझौते का प्रतिकार करने हेतु क्या पूर्वोपाय करने का विचार है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे विचार में मैंने इसका उत्तर दे दिया है। हम केवल अपनी सुरक्षा के लिये ही उपाय कर सकते हैं। हम चीन और पाकिस्तान के बीच किसी सहयोग को नहीं रोक सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, यदि चीन पाकिस्तान में बम का विस्फोट करता भी है तो यह चीनियों का बम होगा। यह चीनियों की जानकारी के आधार पर बनाया जायेगा। मेरे विचार में पाकिस्तान यह ज्ञान तथा बम के लिये अन्य वस्तुएँ इतनी जल्दी नहीं हासिल कर सकता है।

श्री हेम बरुआ : जब पाकिस्तान में किसी बम का विस्फोट किया जाता है तो चाहे यह चीनियों का बम बने अथवा किसी अन्य व्यक्ति का, यह एक बम तो बनेगा ही। पाकिस्तान को हम से अधिक लाभ हो जायेगा। और यह भी ताशकन्द समझौते के बावजूद। हम इस बारे में बहुत चिंतित हैं। प्रधान मंत्री की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस मामले में हम भी उन की तरह बहुत चिंतित हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

*157. **श्री रा० बरूआ** :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के छावनी बोर्डों के कर्मचारियों के लिये एक मजूरी बोर्ड स्थापित करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :

(क) से (ग) : छावनी बोर्ड कर्मचारियों के बारे में उजरत बोर्ड या नेशनल इण्डस्ट्रीयल ट्रिबुनल स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय छावनी बोर्ड की प्रार्थना पर अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है। छावनी बोर्ड कर्मचारियों के लिए वेतनमान और भत्ते निर्धारित करने के लिए सरकार विभिन्न वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार कर रही है। इस दौरान में 2 अप्रैल 1960 को दिया गया नेशनल इण्डस्ट्रीयल ट्रिबुनल का फैसला कार्यान्वित होना जारी है, और इस फैसले के आधार पर समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा मंहगाई भत्ते के संशोधन के फलस्वरूप कर्मचारियों को मिल सकने वाले लाभ छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिए भी स्वीकृत किए जाते हैं।

विदेशों में भेजे गये सद्भावना तथा विशेष प्रतिनिधि मण्डलों का प्रभाव

*158. **श्री लिंग रेड्डी :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विदेशों में भेजे गये सद्भावना तथा विशेष प्रतिनिधिमण्डलों का विदेश नीति तथा काश्मीर सम्बन्धी दृष्टिकोण पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द समझौते का उल्लंघन किये जाने की बात को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए तथा संसार के राष्ट्रों में भारत का सही चित्र प्रस्तुत करने के उद्देश्य से क्या सरकार ऐसे सद्भावना प्रतिनिधिमण्डल भेजती रहती है ?

बैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य जिन देशों में गए, वहां उन्होंने उनके नेताओं के साथ खुलकर बातचीत की जिसके परिणामस्वरूप खास तौर से काश्मीर पर और आम तौर से विदेश नीति पर हमारे पक्ष की अब सराहना हुई है और उसके प्रति समझ बूझ बढ़ी है।

(ख) विदेशों में हमारे प्रतिनिधि पाकिस्तान द्वारा ताशकंद घोषणा के उल्लंघनों की ओर उन देशों का ध्यान बराबर दिलाते हैं, जहां वे भेजे गए हैं। स्वाधीनता दिवस समारोहों आदि में भाग लेने वाले अन्य प्रतिनिधिमंडलों ने भी राष्ट्र समुदाय में भारत के सही चित्र को प्रस्तुत करने में अवसर को उपयोग किया।

Negotiations between Britain and S. Rhodesia

*159. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri R. S. Pandey
Shri H. N. Mukerjee
Shri Vasudevan Nair
Dr. L. M. Singhvi
Shri Hari Vishnu Kamath
Shri Hem Barua
Shri Surendranath Dwivedy
Shri Nath Pai
Shri Shree Narayan Das
Shri Linga Reddy
Shri P. R. Chakraverty
Shri Alvares
Dr. Renen Sen
Shri M. Rampure

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the outcome of the negotiations between Britain and the illegal Government of Rhodesia;

(b) the attitude adopted by Government in this matter as a member of the Commonwealth ;

(c) the manner in which Government have continued their consultation with African countries in this regard , and

(d) the details of initiative taken by Government in regard to the solution of the Rhodesian Problem ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) :

(a) Government are not aware of the outcome of the negotiation between the U. K. and the illegal Smith regime.

(b) The Government of India has been in touch with the British Government and has repeatedly urged it to take adequate steps for ending the illegal regime We have left the British Government in no doubt that the steps so far taken by it were inadequate and had not produced the desired results. The Indian Representative had brought out these points forcefully in the Conference held at Lagos.

(c) Government have been exchanging views, on the Rhodesian problem, through its diplomatic representatives accredited to various African countries and at the periodical meetings o the Sanctions Committee being held in London under the auspices of the Commonwealth Secretariat.

(d) Both at the Lagos Conference as well as at the Security Council meeting held in January and May respectively, this year, India made it abundantly clear that, if necessary, force may be used to bring down the rebel regime in Rhodesia, should economic sanctions fail to achieve the desired result and that full democratic rights must be granted to the people of Zimbabwe on the basis of "one-man-one-vote".

रेडियो वल्वों की कमी

*160. **डा० राम मनोहर लोहिया :** **श्री रामसेवक यादव :**
श्री बागड़ी : **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :

क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इंलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में बनने वाले रेडियो वल्वो की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये वल्व भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा निर्धारित किये गये दामों से बहुत अधिक दामों पर काले बाज़ार में बेचे जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो रेडियो वल्वों की कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस):

(क) जी हां । रेडियो वल्वों की मांग उनके भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० में उत्पादन से अधिक है ।

(ख) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, कि भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० में निर्मित वल्व उनके प्रकाशित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर बेचे जा रहे हैं।

(ग) जब कि शिकायतों के संबंध में कार्यवाही की जा रही है, उसका हल उत्पादन बढ़ाने में है, कि रेडियों वल्वों की मांग पूरी की जा सके। रेडियो वल्बों का वर्तमान् उत्पादन लगभग 3.1 मिलियन प्रतिवर्ष का है। भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० का विचार था, क्षमता 5 मिलियन प्रतिवर्ष तक बढ़ा दी जाए। यह विचाराधीन है।

Installation of Transmitters to Counteract Chinese and Pakistani Propoganda

*161. **Shri Naval Prabhakar :**
Shri Liladhar Kotoki :
Shri R. S. Pandey
Shri R. Barua :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Lakhmu Bhawani :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have abandoned the scheme of installation of high powered radio transmitters to counteract the Propaganda of China and Pakistan ,

(b) if so, the reasons therfor , and

(c) if not, when it is likely to be installed ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The transmitters are likely to be commissioned at various times commencing from the end of 1966 to the end of 1968.

चीन का परमाणु कार्यक्रम

*162. **श्रीमधु लिमये:**
डा० राम मनोहर लोहिया:
श्री म० ला० द्विवेदी:
श्री सुबोध हंसदा:
श्री स० चं० सामन्त:
श्री भागवत झा आजाद:
श्री गुलशन:
श्री हेम राज:
श्री दलजीत सिंह:

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन के परमाणु कार्यक्रम तथा उन के द्वारा परमाणु हथियारों को छोड़ने की व्यवस्था का विकास किये जाने के बारे में कोई नवीन अनुमान लगाया है :

(ख) क्या उनका ध्यान अमरीका तथा अन्य देशों द्वारा लगाये गये ऐसे ही अनुमानों के समाचारों की ओर आकृष्ट हुआ है; और

(ग) उस से क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) परमाणु अस्त्रों के विकास और उन्हें छोड़ने की दिशा में जो प्रगति हुई है, उस पर सरकार बराबर ध्यान रख रही है।

(ख) सरकार ने रक्षा मंत्री, मैकनामारा के इस बयान की रिपोर्ट देखी है कि हो सकता है चीन 1967 तक मीडियम रेंज मिसाइल और 1975 तक अंतर महाद्वीपीय मिसाइल लगा ले, और यह कि हो सकता है कि चीन हथियारों का भण्डार करना आरम्भ कर दे।

(ग) चीन लोक गणराज्य की सरकार परमाणु अस्त्रों और उन्हें छोड़ने की व्यवस्था के विस्तार की जो कोशिशें कर रही है उसे सरकार चिंता की दृष्टि से देखती है जो कि चीन की आक्रामक नीतियों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए, विशेषकर एशिया के लिए खतरा है। सरकार का मत है कि इस विकास को देखते हुए यह अब और भी आवश्यक हो गया है कि सभी परमाणु अस्त्रों के परीक्षण पर रोक लगाने और भविष्य में परमाणु अस्त्रों का उत्पादन करने पर समझौता हो जाए। भारत 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति में और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस दिशा में प्रयत्न कर रहा है।

पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार

*163 **श्री नि० रं० लास्कर:** **श्री हुकम चंद कछवाय:**
श्री राम सहाय पाण्डेय: **श्री बड़े:**
श्री रा० बरुआ:

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने कुछ देशों में काश्मीर तथा अन्य प्रश्नों के बारे में भारत-विरोधी प्रचार तेज कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तानी प्रचार को निष्प्रभावी करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख) : जी हां। ताशकंद घोषणा की शर्तों के अंतर्गत विदेश स्थित हमारे मिशन पाकिस्तान के भारत-विरोधी प्रचार का प्रतिकार करने के लिए समुचित कदम उठा रहे हैं।

शक्तिशाली ट्रान्समीटर

*164. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय ने जिन शक्तिशाली ट्रान्समीटरों को लगाने की घोषणा की थी उन्हें प्राप्त करने और लगाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इन ट्रान्समीटरों की संख्या तथा क्षमता कितनी है ; और इन्हें किन किन देशों से मंगवाया जा रहा है ;

(ग) इनको लगाने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) परिवहन, भाड़े तथा लगवाने के खर्च समेत इन पर कुल कितना खर्च होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना अभी मंजूर होनी है। इसी बीच योजना आयोग ने देश के विभिन्न भागों में 15 उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाने के काम को स्वीकृति दे दी है। इन प्रोजेक्टों के लिए यन्त्रों को लेने, स्थान के चुनाव आदि का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(ख) इन 15 ट्रांसमीटरों से एक बहुत ऊँची शक्ति का मीडियम वैव ट्रांसमीटर रूस और एक यूगोस्लेविया से, 10 उच्च शक्ति मीडियम वेव ट्रांसमीटर जापान से, दो उच्च शक्ति शार्टवैव ट्रांसमीटर स्विजरलैंड से तथा एक उच्च शक्ति शार्टवैव ट्रांसमीटर आस्ट्रेलिया से प्राप्त किए जाएंगे।

(ग) आशा है ये ट्रांसमीटर 1966 के अन्त से 1968 के अन्त तक काम करना आरम्भ कर देंगे।

(घ) लगभग 16 करोड़ रुपये।

गियाना को मान्यता

*165. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतन्त्र गियाना को मान्यता प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके साथ किस प्रकार के तथा किस स्तर पर राजनयिक सम्बंध स्थापित किये गये हैं; और

(ग) उस देश के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने के लिये क्या-क्या सन्धियां तथा करार किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) हाई कमीशन के स्तर पर।

(ग) अभी तक कोई नहीं। लेकिन भारत में बने माल के लिए 10,000 टन चावल का आदान प्रदान करने के लिए गियाना सरकार के साथ एक वस्तु-विनिमय करार पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए थे।

पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर नहरों का निर्माण

*166. **श्री श्रीनारायण दास :** **श्रीमती जयावेन शाह :**

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के और बहुत से भागों के साथ-साथ इच्छोगिल नहर की तरह की बहुत सी नहरें बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस के बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश की रक्षा के लिये इसी प्रकार की कार्यवाही करने का है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :

(क) इस विषय की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

(ख) तथा (ग) : इन सभी संवर्धनों के प्रति सरकार सतर्कता से सावधान है। रक्षा कार्यों के निर्माण सहित अपनी सीमाओं की रक्षा के आवश्यक उपायों की निरन्तर समीक्षा की जाती है। उनके विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

काहिरा स्थित भारतीय राजनयिक कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप

*167. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** **श्री सं० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मई, 1966 के 'फ्री प्रेस जर्नल' में 'काहिरा न्यूजलैटर' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिस में काहिरा स्थित भारतीय मिशन के कुछ विशेष कर्मचारियों के विरुद्ध मोटर कारों के मामले में धोखाधड़ी से सौदे किये जाने के आरोप लगाये गये हैं;

(ख) क्या इन आरोपों के बारे में सरकार ने जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) जांच में दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी हां ।

(ग) ये आरोप निराधार हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश यात्रा के सम्बन्ध में मन्त्रियों को निर्देश

*168. **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सभी मंत्रियों को निदेश दिया है कि जिसमें उनसे विदेशों को जाने से पूर्व वैदेशिक कार्य मंत्रालय को सूचित करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) मंत्रियों ने कहां तक इस का पालन किया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख) : प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया है कि जब कभी मंत्रीगण विदेशों की यात्रा करने की योजना बनाएँ तो उन सभी को चाहिए कि वे विदेश मंत्री से संपर्क स्थापित करें ताकि

वह ऐसी यात्राओं का अधिकतम लाभ उठाने की दृष्टि से ऐसे सुझाव दे सकें, जिन्हें वह आवश्यक समझते हों ।

(ग) प्रधान मंत्री के सुझाव पर अमल किया जा रहा है ।

Visits abroad of the Minister of State in Ministry of External Affairs

*169 **Shri Ram Sewak Yadav :** **Shri Yashpal Singh :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of Officers who were included in the Delegation accompanying the Minister of State in the Ministry of External Affairs, on his visit abroad in May and June, 1966 along with the countries visited ,

(b) the purpose of the visit to the different countries and the persons whom this Delegation met ,

(c) whether Government consider this Delegation to be successful and the benefit accruing to the Government from this tour, and

(d) when the meeting between President Nasser, Marshal Tito and the Prime Minister Shrimati Indira Gandhi is likely to be held ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) :

(a) Following are the names of the officers included in the Delegation :-

i) Shri G. Parthasarthy, Permanent Rrepresentative of India to the United Nations.

ii) Shri Bikram Shah, Director (Americas), Ministry of External Affairs.

iii) Shri Muni Lal, High Commissioner for India, Trinidad.

iv) Shri Kundan Lal, Assistant Commissioner of India, Georgetown.

The countries visited by the Minister of State were Guyana, Trinidad, Yugoslavia and the U. A. R. The Minister of State also transited through U. S. A. , Trinidad and Switzerland.

(b) The purpose of the visit to Guyana was to attend the Independence Celebrations at Georgetown. The Minister of State had discussions with the Governor General and the important leaders, including the Prime Minister Dr. Burnham, Minister of Finance Dr. D' Aguair, leader of the opposition, Dr. Cheddi Jagan, and representatives of various Indian Parties/Associations in the country. In Trinidad the Minister called on the Governor General and met the Indian Community. In New York, the Minister of State had discussions with the Secretary General of U. N. and the Permanent Representatives to the U. N. or U. S. A. and U. S. S. R. At Belgrade and Cairo, he held discussions with Presidents Tito and Nasser, the Prime Minister of U. A. R. and the Foreign Ministers of the two countries.

(c) and (d) The Government consider that the Minister of State's visit to Guyana and Trinidad served a very useful purpose, as it made it possible for him to establish personal contacts with the leaders of Guyana. The country has just become independent and the majority of the people are of Indian origin, linked by cultural ties with India. The Minister of State's discussions at Cairo and Belgrade paved the way for Prime Minister's talks (with President Nasser and Marshal Tito), with a view to holding a Meeting of the three leaders. The Meeting is proposed to be held between October 21-25, 1966.

अमरीका द्वारा ट्रांसमीटरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव

*170. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री वसुमतारी :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी : **श्री पें० बेंकटासुब्बया :**
श्री राम हरख यादव : **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के नवीनतम तरीकों तथा परिवार नियोजन के बारे में ग्रामवासियों को जानकारी देने के लिये भारत के प्रत्येक जिले में एक अमरीकी ट्रांसमीटर लगाने के अमरीकी प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

(ख) क्या यह सच है कि इन ट्रांसमीटरों का संचालन अमरीकी इंजीनियर तथा विशेषज्ञों द्वारा किया जायगा ?

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत में अमरीकी शान्ति दल (अमीरिकन पीस कोर) के सदस्य इन ट्रांसमीटर केन्द्रों के दैनिक कार्यक्रम तैयार करने में सहायता करेंगे;

(घ) इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा;

(ङ) इसमें कितना व्यय अमरीका वहन करेगा , और

(च) इन ट्रांसमीटरों के कब तक लग जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) से (च) तक : एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

गत वर्ष अप्रैल मास में अमरीका के राजदूत ने सूचना तथा प्रसारण मंत्री को यह पत्र लिखा था कि यदि भारत स्थानीय ग्रामीणों के लिये कार्यक्रम प्रसारित करने वाले ग्राम्य-प्रधान रेडियो स्टेशनों का जाल बिछाये अर्थात 320 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक रेडियो स्टेशन खोले तो उसे लाभ होगा । प्रत्येक रेडियो स्टेशन में थोड़े से कर्मचारी रखने का प्रस्ताव था, जो कि जिस नगर में वह स्टेशन स्थापित किया गया है वहां के लोगों तथा उस जिले के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कार्यक्रम कर सकें ।

इसके उपरान्त गत वर्ष मई में राजदूत ने दो परामर्शदाता देने की पेशकश की जिनकी संख्या बाद में बढ़ा कर चार कर दी गई, जिन का कार्य ट्रांसमिटरों की संख्या निश्चित करने के बारे में अध्ययन करना, उनकी लागत का अनुमान लगाना, रिसिवरों आदि की लागत का अनुमान लगाना तथा प्रसारण प्रणाली के बारे में अन्य बातों को निश्चित करना था। उन परामर्शदाताओं का यह भी कार्य था कि वे कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता की जांच करें तथा उन स्टेशनों के लिये उपकरण और मशीनरी के बनाने तथा उपबन्ध करने के बारे में भी जांच करें ।

देश में सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी परिवर्तन लाने के लिये और विशेषत: भारत जैसे ग्राम प्रधान देश में, प्रसारण एक बहुत शक्तिशाली माधम है । भविष्य में क्षेत्रीय प्रसारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये तथा विभिन्न कृषि-क्षेत्रों के कार्यक्रमों के लिये रेडियो स्टेशनों की स्थापना

को बहुत आकर्षक समझा गया। यह महसूस किया गया कि ऐसा जाल राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करेगा तथा जनसाधारण की शिक्षा और साक्षरता अभियान के लिये नये रास्ते खोलेगा, अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देगा, आधुनिक तकनीकी के प्रति लोगों में इच्छा पैदा करेगा और आधुनिक तकनीकी की बातें उन तक पहुँचायेगा।

अमरीका के राजदूत के सुझावों के विभिन्न तकनीकी पहलूओं की बाद में इस मंत्रालय ने जांच की तथा उनकी क्रियान्विति में कुछ कठिनाइयां पेश आई जिनका कारण बहुत अधिक लागत का होना तथा फ्रिक्वेंसी का कम होना था, जैसे कि हम ए० एम फ्रिक्वेंसी से काम लेते हैं। और प्रत्येक जिले में रेडियो स्टेशन के लिये हमें एफ० एम० फ्रिक्वेंसी चाहिये, जिसके लिये और पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी, जिसे हम लगाने में असमर्थ हैं। इस के बाद इस मामले पर गतवर्ष अक्तूबर में योजना आयोग से विचार-विमर्श किया गया तथा यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक जिले में एक ट्रांसमिटिंग स्टेशन लगाना न तो आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होगा और न ही व्यवहारिक होगा।

योजना आयोग ने यह सिफारिश की कि कम संख्या में परन्तु सक्षम ट्रांसमिटिंग केन्द्र खोले जायें और कार्यक्रम सुनने की सुविधाओं का शीघ्रता से विस्तार किया जाय।

गत वर्ष अक्तूबर में भी बैंकोक में एफ ए० ओ० की कृषि शिक्षा संबंधी क्षेत्री गोष्ठी में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने यह अनुरोध किया था कि प्रसारण कार्यक्रम के लिये संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से सहायता दी जाये। तदनुसार एफ० ए० ओ०—यूनेस्को द्वारा संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से धन देने की सिफारिश के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना में 66 फार्म तथा होम रेडियो लगाये जायेंगे। इनमें से 10 लग चुके हैं और 6 और शीघ्र ही लग जायेंगे। यदि एफ० ए० ओ०—यूनेस्को दल की सिफारिशों को योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया और संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से सहायता मिल जाने पर चौथी योजना में शेष 50 रेडियो भी लग जायेंगे।

हमने उपरोक्त कठिनाइयां बता दी थी और इसी लिये अध्ययन दल का दौरा रद्द कर दिया गया था।

पाकिस्तान के लिए रूसी हथियार

*171 **श्री राम हरख यादव :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री राम सेवक यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री काजरोलकर :
श्री कु० चं० पन्त :
श्री बासप्पा :
श्री गुलशन :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री हेमराज :
श्री दलजीत सिंह :
श्री बृजराज सिंह :
श्री लक्ष्मु भवानी :

श्री राम सहाय पाण्डेय : **श्री रामपुरे :**

श्री पै० वेंकटासुब्बया : **श्री मे० क० कुमारन :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सोवियत संघ पाकिस्तान को उन्हीं शर्तों पर हथियार बेचने के लिए सहमत है, जिन शर्तों पर वह भारत को देता है;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी मात्रा में हथियार खरीदने के लिए रूस को क्रयादेश भेजा है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):

(क), से (घ) : सोवियत सरकार ने हमें विश्वास दिलाया है कि उन्होंने पाकिस्तान को कोई हथियार या गोलाबारूद नहीं दिया और न पाकिस्तान के साथ इस संबन्ध में कोई करार ही किए ।

आदिमजातियों के लिये कार्यक्रम

*172. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता, रांची तथा कटक के आकाशवाणी केन्द्रों से आदिमजातियों के लिए कितनी बार कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं;

(ख) इन कार्यक्रमों की विशेषताएँ क्या हैं; और

(ग) यह कार्यक्रम किन-किन बोलियों में प्रसारित किए जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) से (ग) तक : एक बिवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

आकाशवाणी कलकत्ता

कलकत्ता केन्द्र से आदिम जाति कार्यक्रम प्रतिदिन 15 मिनट के लिए त्रिपुरी भाषा में तथा 15 मिनट के लिए संथाली भाषा में प्रसारित होता है । त्रिपुरी कार्यक्रम में समाचार, बाजार भाव, मौसम का हाल, त्रिपुरी तथा बंगाली में वार्तायें तथा त्रिपुरी में संगीत आदि प्रसारित होता है ।

संथाली में केवल वार्तायें तथा संगीत होता है ।

आकाशवाणी रांची

कार्यक्रम की मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं ।

वार्तायें :—सप्ताह में एक बार, क्षेत्र की पांच मुख्य भाषाओं में प्रसारण होते हैं :

1. सन्थाली
2. इराहों
3. हो
4. नागपुरिया
5. मुन्दरी

पत्रिका कार्यक्रम : वार्ताओं के अतिरिक्त कहानी, कविता रुपक आदि का एक पत्रिका कार्यक्रम भी महीने में एक बार प्रसारित होता है। आदिमजाति कार्यक्रम, सामान्य भाषा नागपुरिया में रांची क्षेत्र के विभिन्न आदिमजाति वासियों के लिए होती है।

आदिमजाति संगीत : प्रतिदिन आदिमजाति संगीत होता है जिसमें सभी भाषाओं के प्रसारण होते हैं।

नाटक तथा रुपक : केवल नागपुरिया में ही नाटक हुए हैं।

आकाशवाणी कटक :

उड़ीसा राज्य में आदिमजातियों की कई भाषायें हैं। प्रति सप्ताह 15 मिनट के लिए विभिन्न आदिमजाति के लोग अपनी-अपनी भाषाओं में संगीत प्रसारित करते हैं। सूचनात्मक तथा सांस्कृतिक विषयों पर तिकादी उड़ीया में वार्तायें, चर्चायें आदि के कार्यक्रम होते हैं।

Strike by H. A. L. Employees

*173. **Shri Bade** : **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Hindustan Aeronautics, Limited resorted to hunger strike in June, 1966 because their pay and allowances had not been increased ,

(b) whether it is also a fact that the employees have threatened that they would take more serious action if their demands were not accepted , and

(c) if so, the steps taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) :

(a) Yes, Sir. Some of the employees of the Kanpur Unit resorted to hunger strike to press their demands, one of which related to revision of pay scales.

(b) **and** (c) No, Sir. The demands are under consideration by Hindustan Aeronautics Ltd.

पाकिस्तान का प्रतिरक्षा पर खर्च

*174. **श्री हरि विष्णु कामत** : **श्री वी० चं० शर्मा**

श्री सरजू पाण्डेय : **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

श्रीमती मैमूना सुल्तान : **श्री वासुदेवन नायर** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने अपने प्रतिरक्षा सम्बन्धी खर्चे में इस शर्त पर कमी करने की पेशकश की है कि भारत भी अपने प्रतिरक्षा व्यय में कमी करने के लिए तैयार हो;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी नहीं।

(ख) और ग) प्रश्न नहीं उठते।

दलाई लामा की लेह यात्रा

*175 **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री म० ना० स्वामी :**

श्री दशरथ देव : **श्री कोल्ला वेंकैया :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1966 के 'ब्लिटज' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दलाई लामा का विचार इस वर्ष अगस्त के मध्य में लद्दाख में लेह जाने का है।

(ख) क्या सरकार ने इस यात्रा की मन्जूरी दे दी है; और

(ग) क्या इस मामले में निर्णय करने से पहले उनके मन्त्रालय ने राज्य सरकार से परामर्श किया था।

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) जी हाँ,

(ख) और (ग) दलाई लामा की लद्दाख यात्रा का सुझाव दिया गया है लेकिन कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

प्रधान मन्त्री का रेडियो भाषण जिसमें वियतनाम सम्बन्धी प्रस्ताव है

*176. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** **श्री हरि विष्णु कामत।**

श्री हेम बरूआ : **श्री नाथ पाई :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री के रेडियो भाषण जिसमें वियतनाम की समस्या के बारे में शान्ति के प्रस्ताव हैं, की सूचना अमरीका और ब्रिटेन को पहले दे दी गई थी;

(ख) क्या प्रधान मन्त्री द्वारा घोषणा किये जाने से पहले इन प्रस्तावों के बारे में किसी अन्य देश अथवा देशों को भी सूचना दी गई थी; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी अथवा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क), (ख) और (ग) : जी नहीं । लेकिन वियतनाम समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के विषय में प्रधान मन्त्री के सुझाव का सारांश संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, पोलैंड, उत्तर और दक्षिण वियतनाम को तथा वियतनाम की स्थिति से सीधा सम्बन्ध रखने वाले अन्य देशों को प्रसारण के कुछ घन्टे पहले बता दिया गया था ।

उनकी प्रारम्भिक प्रतिक्रिया प्रतिकूल नहीं थी ।

Publicity in Border Areas

*177. **Shri Onkar Lal Berwa** :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether any new schemes have been formulated to make publicity work in border areas effective and popular ,

(b) if so, the details thereof , and

(c) the extent of co-ordination brought about in work being done by the Central and State Governments in this direction ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) :

(a) No, Sir

(b) Does note arise.

(c) Machinery for coordination exists both at the Central and State levels. Through this machinery as also through personal contact at the operational level between officers of the various agencies functioning in the border areas a good deal of coordination obtains between the Centre and the States.

सैनिकों में चीन का प्रचार

*178. **श्री हेमराज :** **श्री श० बरूआ :**

श्री लीलाधर कटकी :

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में चीनियों ने पूर्वोत्तर पर तैनात सैनिकों में रेडियो द्वारा अपना प्रचार आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसको निष्प्रभ बनाने के लिये क्या प्रभावशाली कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) क्या चीनियों के विरूद्ध तिब्बती व्यक्तियों में प्रचार करने और उसके लिये भारत में उसे तिब्बती शरणार्थियों की सेवायें उपयोग में लाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :

(क) 3 जुलाई 1966 से चीनी सिक्किम-तिब्बत सीमा के नाटुला क्षेत्र में स्थित हमारे सैनिकों की ओर प्रचार तथा संगठित प्रस्तुत करते रहे हैं ।

(ख) तथा (ग) : उनके इस कार्य के विरूद्ध चीन सरकार को एक विरोधपत्र भेजा गया है। माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित ढंग से विस्थापित तिब्बतियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, परन्तु चीनियों के प्रचार के प्रतिकार के लिए सरकार अन्य उपाय सोच रही है।

पाकिस्तान में "ब्लैक आउट" तथा हवाई आक्रमण से बचने के उपायों का अभ्यास

*179. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून 1966 में पाकिस्तान के सभी बड़े शहरों तथा पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में "ब्लैक आउट" तथा हवाई आक्रमण से बचने के पूर्वोपायों का अभ्यास किया गया था ;

(ख) क्या अब भी अभ्यास किये जा रहे हैं ;

(ग) क्या पाकिस्तान के लोगों को यह बताया जा रहा है कि भारत के हवाई आक्रमण से बचने के लिये ये पूर्वोपाय किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख) : पाकिस्तान की एक प्रेस रिपोर्ट के अनुसार जैसोर कस्बे (पूर्व पाकिस्तान) में 16 जून 1966 को दो घंटे के लिये ब्लैक आउट का अभ्यास किया गया था। इस तरह ब्लैक आउट का अन्य स्थानों में अभ्यास कराने की कोई खबर नहीं है।

(ग) और (घ) : जैसोर में इस अभ्यास को कराने के कोई कारण नहीं बताए गए लेकिन सरकार इस पर निगाह रख रही है कि आगे और क्या होता है।

भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

818. **श्री अ० व० राघवन :**

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के सैनिक नाविक तथा वायुसैनिक बोर्ड अपने क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों का कोई अभिलेख (रिकार्ड) रखते हैं;

(ख) यदि नहीं तो क्या देश में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या मालूम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या आगामी जनगणना के समय इस कार्य के लिये जनगणना आयुक्त की सहायता ली जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) :

(क) अधिकतम जिला सैनिक, नौसैनिक और वायु सेना सैनिक बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों और उनके कुटुम्बों का कुछ रिकार्ड रख रहे हैं, यद्यपि सम्पूर्ण नहीं।

(ख) तथा (ग) : मामला विचाराधीन है ।

भूतपूर्व सैनिकों की परिवहन समितियों के लिये फालतू मोटर गाड़ियां

819. **श्री पोट्टेकाट :** **श्री अ० व० राघवन :**

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवामुक्त भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के हेतु भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी परिवहन समितियों को रिआयती मूल्यों पर फालतू मोटर-गाड़ियां देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रति रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) ।

(क) तथा (ख) : सरकार रक्षा आवश्यकताओं से फालतू "वी" श्रेणी की गाड़ियों का 20 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा उनकी कोपरेटिव सोसाइटियों के लिए विमुक्त करने के लिए अलग रख रही है, कि असैनिक जीवन में पुनराबास में उन्हें सहायता मिल सके । उन से प्राप्त किए जाने वाला मूल्य उसी श्रेणी की गाड़ियों, अर्थात् उसी किस्म, उसी मेक और माडल की गाड़ियों के नीलाम में प्राप्त होने वाले औस्त मूल्य पर आधारित किया जाता है । कई अतिरिक्त खर्चे, जो इन विमुक्तियों पर पहले वसूल किये जाते थे, जैसे 5 प्रतिशत विभागीय खर्च, नीलाम की कीमत पर उसका 15 प्रतिशत और अधिक, हाल ही में बन्द कर दिए गए हैं ।

राजस्थान में दूसरा परमाणु रिएक्टर

820. **श्रीमती विमला देवी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा सरकार ने भारत सरकार से इस बात की गारन्टी मांगी है कि राजस्थान में राणा प्रताप सागर नामक स्थान पर स्थापित किये जाने वाले दूसरे अणु शक्ति रिएक्टर के उत्पादों का प्रयोग आणविक हथियार बनाने के लिये नहीं किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) तथा (ख) : कनाडा की सरकार ने तजवीज किया था तथा हमने स्वीकार किया था कि राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट पर सहयोग की वे शर्तें ही लागू हों जो पहले यूनिट के बारे में स्वीकार की गई थीं । इन शर्तों के अनुसार यह शर्त भी थी कि इस यूनिट में जो भी विखण्डनीय पदार्थ इस्तेमाल किया जायेगा अथवा उत्पन्न होगा उसका प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिये ही किया जायेगा ।

Tibet issue for U. N. O.

821. Shri Sidheshwar Prasad ;

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Dalai Lama has decided to raise the Tibet issue in the United Nations ;

(b) if so, the manner in which this issue would be raised , and

(c) the names of the countries which are supporting the move for it ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh):

(a) Government are not aware of any move by the Dalai Lama to raise the Tibet issue in the United Nations.

(b) and (c) Do not arise.

प्रावदा में प्रकाशित लेख

822. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** **श्री रिशांग किशिंग :**

क्या **वैदेशिक कार्य मन्त्री** 9 मई 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1550 के उत्तर के संबंन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 5 मार्च 1966 के "प्रावदा" में प्रकाशित लेख की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायगी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

जी हां । प्रावदा में 5 मार्च 1966 को "हू बेनिफिटर्स" शीर्षक के अन्तर्गत छपे लेख की एक प्रति लोक सभा की मेज पर रख दी है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी 6587/66]

परमाणु बम बनाने पर खर्च

823. **श्री मधु लिमये :** **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उनके इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि स्वर्गीय डा० भाभा ने जो एक परमाणु बम बनाने का खर्च 18 लाख रुपये बताया है, वह "बहुत ही थोड़ा" है;

(ख) यह वक्तव्य किस आधार पर दिया गया है;

(ग) क्या वास्तविक आधार पर उपकरण की लागत, वास्तविक उत्पादन और एक आण्विक प्रकिया का परीक्षण और एक "डैलीवरी" पद्धति के विकास के बारे में नये सिरे से अनुमान लगाया गया है; और

(घ) इसके क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) से (घ) : मुझे यह स्पष्ट नहीं कि मेरे किस वक्तव्य का जिक्र किया जा रहा है । डा० भाभा ने 18 लाख की राशि का उद्धरण एक लेख के आधार पर किया था जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के बारे में सितम्बर, 1964 में जनेवा में हुए तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अमरीका ने पेश किया था । 10 किलो टन शक्ति के बम को बनाने की लागत का यह अनुमान अमरीका के बारे में है जहाँ खरबों रुपये परमाणु अस्त्रों के विकास पर खर्च किये जा चुके हैं तथा इस अनुमान का भारतीय परिस्थितियों से कोई सम्बन्ध नहीं । परमाणु अस्त्रों तथा उनको ले जाने वाले साधनों के निर्माण कार्य के विकास पर अन्य देशों में अरबों रुपये खर्च किये जाते हैं । भारत

में ऐसे विकास पर किया जाने वाला खर्च उन देशों, जो औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत आगे हैं; में होने वाले खर्च से ज्यादा होगा।

केरल में समुद्री डीजल-इंजन कारखाना

824. **श्री मुहम्मद कोया :**

क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में समुद्री डीजल-इंजन कारखाना लगाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस कारखाने को उस राज्य से बाहर कहीं भेजने का निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)

(क) से (ग) : औद्योगिक और मेरीन डीजल इंजन के निर्माण के लिए पश्चिमी जर्मनी के सर्वश्री एम० ए० एन० के साथ सहयोग करार तय पाया हुआ है । स्थानों में एक कोचीन था, जो पहले, इस प्रायोजना के स्थान के लिए विचारा गया था। तदपि, सर्वश्री एम० ए० एन० के विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में, इस क्रम से स्थानों की सिफारिश की है :—(1) रांची, (2) विशाखापतनम, (3) मद्रास और (4) कोचीन। उपरोक्त सिफारिश के आधार पर निर्णय विचाराधीन है।

अर्णाकुलम, केरल में, मछली पकड़ने और ऐसे ही हल्के पोतों में फिट करने के लिए, डीजल इंजनों का निर्माण करने के लिये एक यूनिट स्थापित करने का एक अलग प्रस्ताव है, जैसा कि लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5545 दिनांक 13–5–1966 के उत्तर में बताया गया है।

पूर्वी तट पर नौ सैनिक अड्डा

825. **डा० म० मो० दास :**

क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार पिछले कुछ समय से भारत के पूर्वी तट पर एक एक नौ सैनिक अड्डा बनाने की आवश्यकता अनुभव करती रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के मिले योजना तैयार करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) :

(क) भारत के पूर्वी तट पर विशाखापतनम में एक बृहद् नौसैनिक अड्डे की स्थापना सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली है।

(ख) प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करवाने के लिये उपाय किये जा रहे हैं।

Nuclear Club

826. **Shri Bibhuti Mishra ; Shri K. N. Tiwari :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that China has been made a member of the Nuclear Club after her third atomic explosion ; and

(b) If so, Government's reaction thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) :

(a) **and (b)** A formal Nuclear Club of which the nuclear weapons powers alone are members does not exist. In any case, China, despite its third nuclear explosion, cannot be regarded at present to be in the same class as the recognised nuclear powers.

Hindu Naga Peace Mission

*827. **Shri Bibhuti Mishra :** **Shri K. N. Tiwari :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item appearing in the Statesman dated the 26th May, 1966 of Calcutta regarding the formation of a 5-Member Hindu Naga Peace Mission ,

(b) if so, whether it is a fact that two third of the population in Nagaland belongs to Hindu Nagas ,

(c) if so, whether Government recognise the Peace Mission consisting of Rani Guidello, Shri Prakash Vir Shastri, M. P., Shri S. P. Shastri, Shri Om Prakash Tyagi and Shri Prem Datt Tewari as its Members and founded by Shri G. P. Shastri, the Chairman of the Nehru Sewak Sangh ; and

(d) whether the Peace Mission has submitted any scheme to Government ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) :

(a) Government's attention has been drawn to a newsitem regarding formation of a five-member Hindu Naga Peace Mission.

(b) According to 1961 census about 53 percent of the Nagas are Christians, rest of them follow old Naga beliefs.

(c) The Government of India have not been approached on this matter and as such the question of recognition does not arise.

(d) No. Sir.

Director General, A. I. R.

828. **Shri Sidheshwar Prasad :** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Yashpal Singh : **Shri Bade :**
Shri Bhagwat Jha Azad : **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri M. L. Dwivedi : **Shri Bagri :**
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Informatian and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1308 on the 25th April, 1966 and state :

(a) whether a permanent incumbent for the post of Director-General, A. I. R. has since been appointed :

(b) if so, the mode of selection , and

(c) if not, the reasons for the delay ?

Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) :

(a) Not yet, Sir.

(b) The Union Public Service Commission is in charge of the selection.

(c) The Union Public Service Commission have not yet finalised the selections.The Commission have been requested to expedite.

रूस से हैलिकौप्टर

829. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स०चं० सामन्त
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामसहाय पान्डेय :
श्री रा० बरुआ

क्या **प्रति रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की एम० आइ-4 हैलिकौप्टरों की आवश्यकता बहुत कुछ रूस ने पूरी कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर रूस हमें कितने हैलिकौप्टर देगा और वे भारत कब आ जायेंगे ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :

(क) जी हां।

(ख) 33 हैलिकौप्टर नगद दामों पर और 36 हैलिकौप्टर विलम्बित अदायगी के आधार पर खरीदे गये थे। ये अब तक पहुँच भी चुके हैं। शीघ्र सम्पूर्ण की जाने वाली किस्तों में भुगतान के लिये 40 हैलिकौप्टरों के लिये एक और करार विलम्बित अदायगी की शर्तों पर तय हुआ है। अदायगी दोनों देशों में तय हुए व्यापार करार की शर्तों के अनुसार की जाती है।

हाजी पीर दर्रे से सेना की वापसी

830. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :

क्या **प्रति रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1965 के हमारी सेना द्वारा स्वतंत्र कराये गये क्षेत्र, अर्थात हाजी पीर दर्रा, टिथवाल और कारगिल ताशकंद घोषणा के अनुसरण में वहां से हमारी सेना की वापसी के बाद पाकिस्तान द्वारा वहाँ फिर घुसपैठ की जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो उन मार्गों को बन्द करने तथा घुसपैठ को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) :

(क) तथा (ख) : ताशकन्द समझौते के अन्तर्गत अपनी सेवाएं उक्त क्षेत्रों से हटाई जानी थीं, और पाकिस्तान को इन क्षेत्रों पर पुन: अधिकार करने को अधिकृत किया गया था। तदपि इन क्षेत्रों में से पिछले वर्ष की पाकिस्तानी सशस्त्र सेविवर्ग की घुसपैठ की पुनरावृत्ति के विरूद्ध सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं।

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के लोग

831. **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री हेम बरूआ : **श्री नाथ पाई :**

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री 9 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5030 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के लोगों (सैनिकों और अधिकारियों) के वेतन तथा भत्ते जब्त कर लेने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अ० म० थामस) :

(क) स्थिति संलग्न विवरण में स्पष्ट की गई है ।

(ख) जी नहीं ।

पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एलटी 6588/66]

गिलगित में चीन के सैनिक दस्ते

832. **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री नाथ पाई : **श्री हेम बरूआ :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन के सैनिक दस्ते हाल में गिलगित क्षेत्र में आये हैं ;

(ख) क्या वे दस्ते अब भी वहीं पर हैं ;

(ग) वे वहां क्या करते रहे हैं और क्या कर रहे हैं; और

(घ) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

रूस के साथ पाकिस्तान की बात-चीत का रवैया

833. **डा० राम मनोहर लोहिया** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री बागड़ी : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री विभूति मिश्र :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन समाचारों की ओर दिलाया गया है जो काश्मीर सम्बन्धी मामलों के बारे में रूस के साथ पाकिस्तान सरकार के बात-चीत के नए रवैये के सम्बन्ध में प्रकाशित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो जहां तक काश्मीर की स्थिति का सम्बन्ध है क्या सरकार ने रूस को नवीनतम स्थिति एक बार फिर समझा दी है; और

(ग) यदि हाँ, तो रूस तथा अन्य देशों में भारत के मामले को ब्यौरेवार समझाने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) सरकार ने इस बारे में बहुस-से काल्पनिक समाचार समाचार पत्रों में देखे हैं लेकिन कोई आधिकारिक सूचना उसके पास नहीं है।

(ख) और (ग) : सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सरकार काश्मीर के विषय में भारत के पक्ष को अच्छी तरह जानती है और सुरक्षा परिषद् में काश्मीर सम्बन्धी बहस में उसने हिस्सा लिया है। काश्मीर और अन्य मामलों के बारे में भी भारतीय राजनयिक समय-समय पर स्थिति उन्हें समझाते रहते हैं। हाल की अपनी मास्को यात्रा के दौरान, सोवियत नेताओं ने प्रधान मन्त्री को यह आश्वासन दिया था कि काश्मीर पर उनका रवैया यथावत है।

कच्छातिवू द्वीप

*834 **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री बागड़ी :
श्री रघुनाथसिंह :
श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री मधु लिमये :
श्री नाथ पाई :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री अल्वारेस :
श्री कोत्सा वेंकैया :
श्री हेम बरूआ
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री काजरोलकर :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छातिवू द्वीप के बारे में श्री लंका के दावे का निर्णय करने के लिये मई, 1966 में श्री लंका तथा भारत के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें जो विचार-विमर्श हुआ, उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

The Jawahar Lal Nehru Memorial Fund

*835 **Shri Naval Prabhakar :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) The total amount collected under the Jawahar Lal Nehru Memorial Fund so far (June, 1966), and

(b) the target fixed therefor ?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy Shrimati Indira Gandhi :

(a) The Jawaharlal Nehru Memorial Fund is not a Government Organization. According to the information furnished by the Fund authorities, the total collections up to the end of June, 1966 were Rs. 1,25,61,068. 32.

(b) The Fund authorities have intimated that no target has been fixed. but they expect to raise a sum of Rs. 18. 5 crores for the Fund.

Construction of Broadcasting House near Mandi House, New Delhi

836. **Shri Naval Prabhakar :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Broadcasting House will be constructed near Mandi House ;

(b) whether it will be a complementary building to the Akashvani Bhawan ;

(c) the estimated expenditure involved therein ; and

(d) the special features thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) :

(a) and (b) Yes, Sir.

(c) Rs. 1.9 Crores approximately.

(d) The proposed new building will be used exclusively for News and External Services of All India Radio. Apart from studio and the associated facilities, the building will have the following special facilities :

(i) A conference hall ;

(ii) A library with reading room facilities ;

(iii) An archive for storage of tapes and other archive materials ; and

(iv) A central library for gramophone records.

Employees in Indian Missions Abroad

837. **Shri Naval Prabhakar :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian nationals and citizens of respective countries respectively serving in the Indian Embassies and High Commissions abroad, country-wise ;

(b) the nature of duties assigned to the foreign nationals therein ; and

(c) the number of persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes amongst the Indian nationals so employed abroad ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) :

(a) to (c) The information is being collected and will shortly be laid on the Table of the House.

Publicity Literature Published in Indian Missions Abroad

838. **Shri Naval Prabhakar :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian Missions abroad where publicity literature disseminating information about India is published ;

(b) the number of such publications ;

(c) the languages in which these are published ; and

(d) how this literature compares with that published by other foreign Embassies ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) :

(a) Ninety-four Missions produce and distribute literature. Some bigger Missions produce more than others. Very small Missions produce pamphlets less than larger Missions.

(b) The number of publications issued by all our Missions abroad varies from time to time, depending upon the publicity requirements. Of the 85 publications which issue from the different Missions regularly, 23 are printed periodicals, the others being cyclostyled bulletins, hand-cuts and press releases.

(c) English, German, French, Spanish, Arabic, Portuguese, Flemish, Dutch, Russian, Swahili, Persian, Pushto, Burmese, Sinhalese, Malay, Bahasa Indonesia, Thai, Chinese, Japanese and Turkish.

(d) Within the limited funds available to them, the publicity literature produced by our Missions is comparable to that produced by other Missions.

Fire in C. O. D. Cheoki

889. **Shri Vishwa Nath Pandey ; Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Bagri : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Dr. Ram Manohar Lohia : Shri Raghunath Singh :
Shri Madhu Limaye : Shri Yashpal Singh :
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a fire broke out in the store of the Central Ordnance Depot, Cheoki near Allahabad on the 17th May, 1966 resulting in heavy losses ;

(b) if so, the causes thereof ;

(c) the total amount of loss suffered thereby ; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) :

(a) Yes, Sir.

(b) A Court of Inquiry was convened on 25-5-1966 to investigate into the circumstances under which fire broke out. Their findings have not yet been finalized.

(c) The exact loss is not yet known but according to a preliminary estimate the total loss is about Rs. 1.5 lakhs.

(d) Further action will be taken in the light of the findings of the Court of Inquiry.

उत्तर प्रदेश के लिये अखबारी कागज का अभ्यंश

841. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 और 1965-66 में उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों के लिये अखबारी कागज का कितना अभ्यंश आवंटित किया गया है ; और

(ख) क्या 1966-67 में इस अभ्यंश को बढ़ाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) :

(क) तथा (ख) : अखबारी कागज का कोटा अलग अलग समाचार पत्रों को दिया जाता है राज्यों को नहीं । राज्य के अनुसार आंकड़े नहीं रखे जाते । 1966–67 की अखबारी कागज की नीति 26 अप्रैल, 1966 को लोक सभा की मेज पर रखी गई थी । इस नीति के अनुसार अखबारी कागज का कोटा इन हालतों में बढ़ाया जा सकता है:–

(1) जिन पत्रों की प्रचार संख्या 10,000 से कम है उनको 10,000 तक, प्रचार संख्या बढ़ाने के लिये अखबारी कागज दिया जा सकता है ।

(2) 10,000 तथा 50,000 के बीच की प्रचार संख्या वाले पत्र अपनी प्रचार संख्या को 2½ प्रतिशत बढ़ा सकते हैं । उनको 15 प्रतिशत नेपा तथा शेष 7½ प्रतिशत सफेद कागज दिया जा सकता है ।

(3) 50,000 से अधिक प्रचार संख्या वाले पत्र 20 प्रतिशत प्रचार संख्या बढ़ा सकते हैं । इसके लिये उनको सफेद कागज दिया जायेगा, जिस पर उत्पादन शुल्क न लगेगा ।

चिकित्सा कर्मचारियों की चयनात्मक अनिवार्य भर्ती

842. **श्री मधु लिमये :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के पश्चात् चिकित्सा कर्मचारियों की चयनात्मक अनिवार्य भर्ती की योजना लागू करते समय, सेना में इस प्रकार अनिवार्य भर्ती के अन्तर्गत रखे गये व्यक्तियों के लिये क्वार्टर दिये जाने तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में शर्तें अथवा नियम निर्धारित किये गये थे ;

(ख) क्या ये नियम अनिवार्य भर्ती योजना लागू होने से पहले सेना में काम करने के लिये अपनी सेवायें पेश करने वाले लोगों पर लागू नहीं होते ;

(ग) चीन द्वारा आक्रमण के पश्चात् इस प्रकार कितने कर्मचारियों ने अपनी सेवायें अर्पित की थीं ;

(घ) क्या अपनी सेवायें प्रस्तुत करने वाले कर्मचारियों सम्बन्धी शर्तें तथा नियम अनिवार्य भर्ती के अन्तर्गत रखे गये कर्मचारियों पर लागू होने वाली शर्तों और नियमों की तुलना में अच्छी नहीं है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार का अनुचित भेदभाव समाप्त करने तथा सेना में

भर्ती किये गये सभी चिकित्सा कर्मचारियों के लिये सेवा के समान नियम तथा शर्तें लागू करने का है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) से (ङ) : चिकित्सा सेविवर्ग के लिये 1965 के भारत पाक युद्ध के पश्चात् कोई चयनात्मक अनिवार्य भर्ती के लिए कोई योजना संस्थापित नहीं की गई थी। ऐसे सेविवर्ग के सम्बन्ध में विशेष शर्तों और नियमों के बनाए जाने का प्रश्न नहीं उठता। अब तक भर्ती किए गए सभी चिकित्सा सेविवर्ग वालण्टीयर हैं। तदपि एक योजना है कि जिस के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकार काडरों तथा राजकीय उपक्रमों के लिये डाक्टरों की भर्ती के लिए नियमों में ऐसा उपबन्ध किया जा रहा है, कि भविष्य में उनमें शामिल होने वालों को (प्रशिक्षण अवधि सहित) कम से कम चार वर्षों के लिए सशस्त्र सेनाओं में सेवा करना होगा, या कहीं भारत में, अथवा आवश्यक हुआ तो विदेश में रक्षा सम्बन्धित कार्य में। सशस्त्र सेनाओं में सेवा करने की देयता उनकी सेवा के पहले 10 वर्षों तक सीमित है, और उन डाक्टरों पर लागू नहीं होगी जो 45 वर्ष से ऊपर की आयु के होंगे। नर्सों की हालत ऐसी कोई योजना विद्यमान नहीं है।

News Bulletins in Hindi

843. **Shri M. L. Dwivedi** : **Shri S. C. Samanta** :
Shri Subodh Hansda : **Shri Bhagwat Jha Azad** :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of various A. I. R. Stations which do not broadcast news bulletins in Hindi and also the names of such stations which have now discontinued to broadcast news bulletins in Hindi with reasons therefor ;

(b) the reasons for discontinuing the practice of broadcasting the news bulletins in English and Hindi followed by each other ; and

(c) the transmission waves on which news bulletins in Hindi are still broadcast in non-Hindi speaking areas and also the waves on which these are not broadcast ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) :

(a) Every Station of All India Radio broadcasts one or more Hindi news bulletins. No Station has discontinued any Hindi bulletin which it relayed earlier.

(b) Except the Hindi Bulletin at 8-15 P. M. and the English bulletin at 9 P. M., all other Hindi and English News bulletins are followed by each other, either on the same channel or, where more than one channel is available, on a different channel.

(c) A statement is placed on the Table of the Sabha. **[Placed in the library see No. LT-6589/66]**.

सियोल में नौ राष्ट्रों का मन्त्री-स्तरीय सम्मेलन

846. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : **श्री श्रीनारायण दास** :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व एशिया में एक नया संयुक्त सुरक्षा संगठन बनाने के बारे में विचार करने के लिए 14 जून 1966 को सियोल में हुए नौ राष्ट्रों के मन्त्री-स्तरीय सम्मेलन की और सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी हां। सरकार को जो सूचना सुलभ है, उसके अनुसार सम्मेलन ने दक्षिण पूर्व एशिया में कोई नए सामूहिक सुरक्षा संगठन की स्थापना करने पर विचार विमर्श नहीं किया। उसका मुख्य सरोकार भाग लेने वाले देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग करने से था।

(ख) सरकार एशिया में प्रादेशिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहती है लेकिन वह सहयोग कोलम्बो योजना, इकाफे और एशियाई विकास जैसे व्यापक आधार पर होना चाहिए न कि किन्हीं राजनीतिक दलबंदियों के आधार पर। भारत सरकार ने सेओल सम्मेलन में भाग नहीं लिया।

प्रचार साहित्य पर व्यय

847 **श्री यशपाल सिंह** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ताशकंद समझौते की घोषणा होने के पश्चात् विदेशों में हमारे विदेश नीति का स्पष्ट चित्रण करने के लिये प्रचार साहित्य पर कुल कितना व्यय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

सुलभ सूचना के अनुसार इस काम पर इस मंत्रालय ने और हमारे उन मिशनों ने, जिनमें प्रकाशन एकांश (प्रोडक्शन यूनिट) है कुल मिलाकर 2,97,898/– रु० खर्च किए हैं। लेकिन, इसमें वह खर्च शामिल नहीं जो कि मिशन समाचार बुलेटिन निकालने पर और कभी-कभी प्रचार साहित्य प्रकाशित करने पर करते हैं।

भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना

848. **श्री बागड़ी** : **श्री राम सेवक यादव :**

डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री मधु लिमये :**

श्री किशन पटनायक : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 मई, 1966 को इलाहाबाद के निकट भारतीय वायु सेना के एक-दो सीट वाले विमान की दुर्घटना में विमान चालक शिक्षक और एक प्रशिक्षणार्थी मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ;

(ग) क्या इस की कोई जांच कराई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच का परिणाम क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) जी नहीं।

(ख), से (घ) : इस घटना की जांच करने के लिए एक कोर्ट आव इन्कवायरी स्थापित की गई थी। वह इन बुनियादी निर्णयों पर पहुँची :–

(1) विमान चालक प्रशिक्षक और प्रशिक्षार्थी उड़ान के लिए समर्थ थे।

(2) विमान सर्वथा सेवा योग्य था, और उस पर ठीक-ठीक भार लादा गया था।

(3) उड़ान ठीक तौर पर अधिकृत की गई थी और उसके विषय में उचित-तौर पर समझाया गया था।

(4) दुर्घटना का सम्भावनीयतम कारण एक साभिप्राय स्टाल से चक्र काटना था जिस से संभल पाना संभव न था।

(5) सीधे या अन्यथा दुर्घटना के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है।

फिल्म डिवीजन का कार्यक्रम

849. **श्री बागड़ी :** **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री राम सेवक यादव :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म डिवीजन ने 1966–67 में बहुत सी फिल्मों बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो ये वृत्त चित्र तथा अन्य चलचित्र किन-किन विषयों पर बनाए जायेंगे;

(ग) क्या इन चलचित्रों को विदेशों में भी दिखाया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) :

(क) 1966-67 में फिल्म डिवीजन लगभग 160 समाचार चित्र तथा छोटी फिल्में बनाएगा।

(ख) समाचार चित्रों में सामयिक घटनाओं के दृश्य होंगे। छोटी फिल्म खाद्य, खेती, स्वास्थ्य, परिवार नियन्त्रण और विकास के अन्य विषयों पर बनाई जाएंगी।

(ग) जी हाँ, कुछ समाचार चित्र तथा छोटी फिल्में विदेशों में भी दिखाई जायेंगी।

(घ) 1966-67 में विदेशों में दिखाने के लिए फिल्मों की प्रतियाँ बनाने पर 10 लाख रुपये खर्च का अनुमान है।

झाँसी में प्रसारण केन्द्र

850. **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिये, जिसमें सात जिले हैं; और जहां हिन्दी भाषा की बुन्देलखण्डी बोली, बोली तथा समझी जाती है, कार्यक्रम प्रसारित करने के लिये झांसी में एक नया प्रसारण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी हां। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में, जो अभी योजना आयोग से मंजूर होनी है, झांसी में आकाशवाणी का एक मध्यम शक्ति का ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है। यदि इसकी मंजूरी मिल गयी तो, इससे बुन्देलखण्ड के अधिकांश भाग में कार्यक्रम सुने जा सकेंगे।

(ख) यदि योजना मंजूर हो गई तो चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के दौरान।

श्री लालडेंगा का प्रत्यर्पण

851. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिज़ो नेशनल फ्रंट के नेता, श्री लालडेंगा अभी तक पाकिस्तान में हैं ; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से श्री लालडेंगा को स्वदेश में लाने के लिये कोई कार्यवाही की है।

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) अब तक की खबरों के अनुसार, ख्याल है, कि श्री लालडेंगा मीज़ो पहाड़ी जिले में थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी केन्द्रों की क्षमता

852. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करीब एक किलोवाट जैसे बहुत ही कम क्षमता वाले आकाशवाणी केन्द्र कितने समय तक केवल आगे प्रसारित करने वाले (रिलेईंग) केन्द्र बने रहेंगे;

(ख) यदि इन केन्द्रों को अपने मूल कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दिये जाने की निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है, तो ये केन्द्र स्थानीय प्रतिभा, संस्कृति तथा परम्पराओं के विकास में कैसे सहायता कर सकते हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक केन्द्र का वार्षिक स्थापना व्यय क्या है और यदि इन केन्द्रों से कुछ समय के लिये स्थानीय तथा क्षेत्रीय कार्यक्रम भी मूल रूप से प्रसारित किये जायें तो इस व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संम्भावना है; और

(घ) इन में से प्रत्येक केन्द्र में भारी वेतन पाने वाले इंजीनियरिंग कर्मचारी रखने की क्या आवश्यकता है जब कि इन केन्द्रों के कार्य का नियंत्रण, अधीक्षण तथा प्रबन्ध बड़े केन्द्रों की सहायता से किया जा सकता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राजबहादुर) :

(क) अल्प/मध्यम शक्ति के मीडियम वैव ट्रांसमीटरों की क्षमता कम नहीं समझी जा

सकती। उनका एक निश्चित कार्य है। मध्यम तरंगों पर शहरों में विविध भारती कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। यहां भीड़ होती है अतः इसके लिए अल्प शक्ति के ट्रांसमीटर बहुत उपयुक्त समझे जाते हैं। राज्यों के जो क्षेत्र मुख्य प्रादेशिक केन्द्रों के प्रसारण क्षेत्र में नहीं आते, उनमें प्रसारण के लिए मध्यम शक्ति के ट्रांसमीटरों का प्रयोग किया जाता है। ये सहायक केन्द्र मुख्य केन्द्र का कार्यक्रम रिले करते हैं और इस प्रकार बहुत कम खर्च पर इनसे प्रसारण का विस्तार हो जाता है। इनको मूल कार्यक्रम प्रसारित करने वाले केन्द्रों में बदलने पर तभी विचार किया जा सकता है जब, स्टूडियो बनाने के लिए साधन उपलब्ध हों।

(ख) जैसा कि ऊपर (क) में बताया गया है, हमारे पास इस समय जो साधन हैं, उन से उन क्षेत्रों में, जो राज्यों के मुख्य रेडियो केन्द्रों के प्रसारण-क्षेत्र में नहीं आते, प्रसारण के विस्तार के लिए यह तरीका सबसे अच्छा है। इससे अधिक लोगों को प्रसारण सुनाने का अच्छा प्रबंध हो जाता है। स्थानीय संस्कृति और परम्परा के संवधर्न के लिए, सहायक केन्द्रों में स्टूडियो की व्यवस्था करना निस्सन्देह हमारा अगला कदम होगा। सरकार यथा समय इसे करेगी।

(ग) मध्यम शक्ति का एक सहायक केन्द्र स्थापित करने पर, पूंजी गत व्यय 12 लाख रुपया और उसके संचालन पर वार्षिक आवर्ती व्यय 1.9 लाख रुपया होता है। यदि इन केन्द्रों को नियमित रेडियो केन्द्रों में बदलना हो, तो यहां पर नए स्टूडियो केन्द्रों को बनाना होगा और उन पर पूंजीगत व्यय और वार्षिक आवर्ती व्यय दुगना होगा।

(घ) क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार तै किया जाता है कि वहां अल्प, मध्यम या उच्च किस शक्ति का ट्रांसमीटर उपयुक्त होगा। ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने मात्र से ही उसी हिसाब से प्रसारण क्षेत्र नहीं बढ़ जाता। उदाहरण के लिए, मध्यम तरंग का क्षेत्र दुगना करने के लिए ट्रांसमीटर की शक्ति को लगभग 16 गुना बढ़ाना होगा। इस लिए यह तर्क कि मध्यम शक्ति के ट्रांसमीटर वाले सहायक केन्द्र जितने क्षेत्र में प्रसारण करते हैं उतने में उच्च शक्ति के थोड़े से ट्रांसमीटर लगाने से उस से कम खर्च में प्रसारण हो सकता है, टेकनीकी दृष्टि से ठीक नहीं है। कल-कारखानों वाले तथा अधिक आबादी वाले बड़े शहरों के लिए ऊंचे सिगनल चाहिएं जो इन स्थानों के निकट अल्प/मध्यम शक्ति के बहुत से ट्रांसमीटरों को लगाने से ही हो सकता है न कि इन से दूर, उच्च शक्ति के थोड़े से ट्रांसमीटर लगाने से।

सिविल रक्षा कर्मचारियों का चिकित्सा सम्बन्धी खर्च

853. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता नगर में रहने वाले सिविल रक्षा कर्मचारियों को, किसी एम० बी० बी० एस० डाक्टर अथवा किसी पंजीकृत डाक्टर से इलाज कराने पर, उन के द्वारा किये गये चिकित्सा सम्बन्धी खर्च की प्रतिपूर्ती (रिइम्बर्समेंट) की जाती है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा अन्य क्षेत्रों में रहने वाले अथवा काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों को क्यों नहीं दी जाती है ;

(ग) क्या यह सच है कि 24 परगना में डा० बी० एन० बोस अस्पताल को ही, सारे जिले के लिये चिकित्सा सम्बन्धी लाभ की प्रतिपूर्ति के लिए मान्यता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री म० म० थामस) :

(क) जी हां।

(ख) चूंकि पश्चिमी बंगाल सरकार ने (असैनिक रक्षा कर्मचारियों सहित) केन्द्रीय सरकारी सेवकों के चिकित्सा उपचार और इलाज के लिए आवश्यक प्रबन्ध नहीं किए हैं, न ही कलकत्ता स्थित उनके कुटुम्बों के लिए, उनके लिए विशेष प्रबंध करना आवश्यक था। पश्चिमी बंगाल के अन्य क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक प्रबन्ध किए हैं।

(ग) डाक्टर वी० एन० बोस हस्पताल के अतिरिक्त इस उद्देश्य के लिए अन्य सरकारी और नगर-पालिका हस्पतालों को मान्यता दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जापानी प्रतिनिधिमण्डल का दौरा

854. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शांति स्थापना तथा परमाणु हथियारों विरोधी लोकमत बनाने वाली जापान की समिति (जैपेनीज़ आर्गेनाइजिंग कमेटी) के सभापति डा० मसातोशी मतसुशीता के नेतृत्व में एक जापानी प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली आया था और उस ने प्रधान मन्त्री, अन्य मन्त्रियों तथा अधिकारियों के साथ बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई थी और उसका क्या परिणाम निकला था ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी हां। 31 मई को डाक्टर मतसुशीता उप राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री से मिले थे।

(ख) प्रधान मन्त्री के साथ मुलाकात में, डाक्टर मतसुशीता ने अपनी संस्था के उद्देश्यों पर रोशनी डाली और टोकियो में उनकी संस्था की ओर से आयोजित होनेवाले सम्मेलन में कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। प्रधान मन्त्री ने उन्हें यह स्पष्ट किया कि भारत शांति चाहता है और यह भी कि अणु शक्ति का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

855. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फॉरमोसा सरकार ने हवाई अड्डे से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता हो जाने की जांच करने के लिए आयोग स्थापित किया है ;

(ख) क्या यह कार्यवाही गैर-सरकारी संस्थाओं के कहने पर की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) भारत सरकार मे प्रेस रिपोर्टें देखी हैं जिनमें कहा गया है कि फॉरमोसा की सरकार के एक अधिकारी को "नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता हो जाने के भेद की जांच पड़ताल करने का आदेश दिया गया है"।

(ख) प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, भारत के कुछ व्यक्तियों के कहने पर ऐसा किया गया है।

(ग) भारत सरकार के ताइवान की सरकार के साथ कोई राजनयिक संबन्ध नहीं है और जैसी कि रिपोर्ट है, उस सरकार द्वारा जांच के लिए दिए गए आदेश से भी उसका कोई सरोकार नहीं है। संसद में यह कई बार कहा जा चुका है कि भारत सरकार ने श्री शाह नवाज खां के नेतृत्व में बनी नेताजी जांच समिति के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है।

वृत्त चित्र

856. **श्री व० कु० दास :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वृत्त चित्र रायल्टी देने पर वाणिज्यिक प्रदर्शन के लिये दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन चलचित्रों के नाम क्या हैं ;

(ग) रायल्टी वसूल करने की क्या प्रक्रिया है ; और

(घ) क्या किसी पार्टी ने रायल्टी नहीं दी है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी** 6590/66]

(ग) सम्बन्धित पार्टी से बात चीत के द्वारा।

(घ) जी, हां। भारत में अभी तक केवल एक पार्टी ऐसी निकली, जिससे रायल्टी का अंश पाना बाकी है।

इंडिया डायरी

857. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 तथा 1966 में वार्षिक इंडिया डायरी की कुल कितनी प्रतियां प्रकाशित की गई थीं ;

(ख) उनके प्रकाशन पर कितना व्यय हुआ ;

(ग) इन डायरियों की बिक्री से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ; और

(घ) उपहार के तौर पर कितनी प्रतियां बाँटी गईं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) :

	1965	1966
(क) : प्रतियों की संख्या	77,686	72,410
(ख) : खर्चा	2,40,250.00 रुपये	3,14,803.00 रुपये
(ग) : बिक्री से लगभग शुद्ध प्राप्ति	1,38,250.00 रुपये	1,72,478.50 रुपये
(च) : मुफ्त बांटी गई प्रतियों की संख्या	38,186*	22,410*

सैनिकों के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम

858. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के मोर्चों पर तैनात सैनिकों का मनोरंजन करने के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने के लिये आकाशवाणी ने विशेष कलाकार दल बनाए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार के कितने दल बनाए गये हैं ; और

(ग) इन दलों ने किन किन क्षेत्रों में ये कार्यक्रम पेश किये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठते ।

नाटक समारोह

859. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत नाटक समारोह में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ;

(ख) इन सब नाटकों को रंगमंच पर खेलने पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) प्रवेश शुल्क के रूप में जनता से कितनी राशि प्राप्त हुई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर):

(क) सभी राज्य/केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र बुलाये गये थे, परन्तु केवल निम्न 15 ने भाग लिया :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. आसाम
3. बिहार
4. गुजरात
5. हिमाचल प्रदेश
6. मैसूर
7. मणिपुर
8. मध्य प्रदेश
9. मद्रास
10. पंजाब
11. महाराष्ट्र
12. उड़ीसा
13. राजस्थान
14. उत्तर प्रदेश
15. पश्चिम बंगाल

*(अधिकतर विदेशों मे)

(ख) लगभग 82,000.00 रुपये।

(ग) कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया गया। निमन्त्रित व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिये प्रवेश मुफ्त था। जो पहिले आए उनको पहिले स्थान दिया गया।

आगरा में केन्द्रीय आयुध (ओर्डनेंस) डिपो के कर्मचारियों को भत्ते की प्रतिपूर्ति

860. **श्री अचल सिंह** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आयुध डिपो आगरा में गत छः महीनों में (महीनेवार) चिकित्सा तथा अन्य प्रतिपूर्तियों पर कितना खर्च किया गया है;

(ख) क्या सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा के कर्मचारियों ने चिकित्सा, मकान भत्ता, नगर तथा बालशिक्षा भत्तों की प्रतिपूर्ति के लिये कुछ झूठे दावे किये हैं, जिससे विभाग का खर्च बढ़ गया है;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में केन्द्रीय जांच विभाग से कोई प्रतिवेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इस बुराई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 854454.89 रुपये।

(ख) से (घ) राज्य पोलीस के अधिकारियों, सी० ओ० डी० आगरा के कई कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं। सी० वी० आई० द्वारा आगे जांच की जा रही है। कुछ कर्मचारी तबदील किए जा चुके है और अगली कार्यवाही जो भी आवश्यक हुई सी० वी० आई० की जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर की जाएगी।

भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का सम्मेलन

861. **श्री राम हरख यादव** : **श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान सर्वेक्षण अधिकारी सम्मलन में भाग लेने वाली भारतीय पार्टी का एक अग्रिम दल सम्मेलन में भाग लेने के लिये 27 मई 1966 को ढाका के लिये रवाना हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको निर्धारित कार्यक्रम के विपरीत अपनी यात्रा का मार्ग बदलना पड़ा था;

(ग) यदि हां, तो मार्ग बदलने के क्या कारण थे; और

(घ) सम्मेलन का कार्य कब पूरा होने की आशा है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल सर्वेक्षण अधिकारियों के दो दल 25 और 26 मई 1966 को ढाका के लिए रवाना हुए थे।

(ख) जी हां।

(ग) कलकत्ते से काठमांडू को रायल नेपाल एयरलाइन्स की उड़ानें बंद हो जाने के कारण रास्ता बदलना पड़ा।

(घ) सम्मेलन ने 28 मई 1966 को अपना कार्य पूरा कर लिया।

ट्राम्बे के निकट चम्बूरपुर में भूमि स्खलन (लैंडस्लाइड)

862. **श्री राम हरख यादव :** **श्री ब्रज बिहारी महरोत्रा**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 मई, 1966 को ट्राम्बे में ऊर्जा संस्थान के निकट चम्बूरपुर नामक स्थान पर भूमि स्खलन के फलस्वरूप तीन व्यक्ति मर गये और अनेक व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आई थीं ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस दुर्घटना की कोई जांच की गई थी ; और

(घ) यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) और (ख) 26 मई, 1966 को ट्राम्बे ऊर्जा संस्थान में भूमि स्खलन के परिणाम स्वरूप दो व्यक्ति मारे गये और तीन व्यक्तियों को चोटें आई थी। ट्राम्बो में जमीन खोदने के काम का ठेका दिया गया था। इस में कुछ कटाई भी की जानी थी। पहाड़ी को ऊपर से काटने की बजाये उसे नीचे से काटना आरम्भ किया गया, जिस के परिणामस्वरूप वह हवा में लटकने लगी और अन्ततः उसके नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिर पड़ी।

(ग) जी, हां, इस दुर्घटना की जांच करने के लिये ट्राम्बे संस्थान द्वारा एक समिति नियुक्त की गई है।

(घ) समिति के निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना कटाई ऊपर से आरम्भ करने की बजाये नीचे से आरम्भ करने के कारण लटकती हुई पहाड़ी के गिरने से हुई। समिति ने यह मत भी व्यक्त किया है कि मजदूरों ने ऊपर से काटने की बजाये नीचे से काटने में निहित खतरे को नहीं समझा। पर्याप्त प्रवेक्षण की भी कमी थी। विधि के संगत उपबन्धों के अनुसार समिति के निष्कर्षों पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

भारतीय सांख्यिकी संस्था, कलकत्ता

863. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
डा० रानेन सेन :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकी संस्था, कलकत्ता के विकास वर्कशाप को बन्द करने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इसके फलस्वरूप हुई छटनी का कितने कर्मचारियों तथा प्रशिक्षुओं पर प्रभाव पड़ा है?

प्रधान मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी हां।

(ख) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान-परिषद् ने यह अनुभव किया है कि अपने उपलब्ध साधनों के बल पर विकास वर्कशाप को वाणिज्यिक उद्यम के रूप में अथवा आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर इकाई के तौर पर चलाना उसके लिए संभव नहीं था ।

(ग) छटनी से प्रभावित कर्मचारियों तथा प्रशिक्षुओं की संख्या क्रमश: 96 और 37 है ।

प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन में प्रशिक्षुता योजना

864. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा चलाई गई प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) योजना को जारी रखने के बारे में कुछ आपत्ति उठाई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये आपत्ति क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) :

(क) जी हां ।

(ख) पहले चुनावों के परिणामों पर यू० पी० एस० सी० ने असन्तोष प्रकट किया था, और इसीलिए सीधी भर्ती को अच्छा माना था, परन्तु अधिक विचार करने के पश्चात् चुनावों के एक दूसरे दल पर वह सहमत थे । दूसरे दल में, यू० पी० एस० सी० समालापों के आधार पर 90 छात्रों का चुनाव संभव हो पाया था । अब तक किए गए चुनावों में, प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर, अब समीक्षा की जायेगी, जिस के बाद निर्णय किया जायगा कि यह योजना जारी रहनी चाहिए या नहीं ।

प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

865. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन में 17 विषय-वर्ग हैं और सीनियर साईंटिफिक असिस्टैंटों/फोरमैनों को जूनियर साइंटिफिक आफिसर के पद पर पदोन्नति इन विषय-वर्गों के अनुसार की जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ विषय-वर्गों में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट/फोरमैन एक ही पद पर 10 वर्ष से भी अधिक समय से काम करते रहे हैं जब कि अन्य विषय-वर्गों में लोगों की तीन-चार साल के सेवाकाल में कई पदोन्नति हो गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किन विषय वर्गों में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंटों/फोरमैनों को पदोन्नति के मामले में नुकसान हुआ है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) :

(क) जी हां । ऐसे विषय समूह 18 हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) टेक्सटाईल्ज और जनरल स्टोर्ज से सम्बन्धित समूहों में कानूनी दृष्टि से ऐसा ही है, क्योंकि इन क्षेत्रों में, अनुसन्धान प्रसार की आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं ।

प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में पदोन्नति

866. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय के प्रतिरक्षा निरीक्षण संगठन और प्रतिरक्षा अनुसंधान विकास संगठन के लिये कुछ विषय-वर्गों की वरिष्ठता सूची इकट्ठी रखी जाती है जिसके परिणामस्वरूप पदोन्नति के अवसर कम होने के कारण सम्बन्धित कर्मचारियों में असन्तोष फैलता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस):

(क) तथा (ख) पदोन्नति के अवसरों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि डिफेन्स इन्सपेक्शन और रिसर्च तथा डिवेलपमेन्ट संगठन के सीन्यारिटी रोल संयुक्त हैं, परन्तु चूंकि पदोन्नति अलग अलग विषयवार दलों में और कुछ विषयों जैसे कि टेक्सटाईल और जनरल स्टोर्ज, में की जाती हैं, अनुसन्धान प्रसार की आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं।

भारतीय वायु सेना में भर्ती

867. **श्री गुलशन** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु सेना में तकनीकी तथा गैर तकनीकी, दोनों प्रकार के, विभिन्न पदों में भर्ती के क्या नियम हैं तथा उनके लिये क्या न्यूनतम शिक्षा अर्हतायें निर्धारित की गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उच्चतर माध्यमिक भाग-एक के ऐसे उम्मीदवार, जो अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के विषयों से परीक्षा पास किये होते हैं, एयरमैन टेक्नीकल ट्रेड के पद के लिये पात्र नहीं माने जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो मैट्रिक पास उम्मीदवारों और उच्चतर माध्यमिक भाग-एक के उम्मीदवारों के बीच ऐसा भेदभाव होने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) भारतीय वायु सेना में तकनीकी और गैरतकनीकी दोनों ट्रेडों में वायु सेना सैनिकों की भर्ती के लिए नियम नीचे दिए हैं। विभिन्न ट्रेड ग्रूप संलग्न विवरण में दिखाए गए हैं :—

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी 6592/66]

बर्मा से मिजो लोगों को स्वदेश लौटाया जाना

868. **श्री प्र० चं० बरूआ** :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार सरकार पर उन मिज़ो लोगों को, जो बर्मा की सीमा में घुस गये थे, वापस स्वदेश में लौटा लेने के लिये जोर डालती रही है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने मिजो वापस लौट आये हैं और शेष लोग कब वापस लौट आयेंगे ; और

(ग) उन्हें बसाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) बर्मा की सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की थी कि वह उन मीजो लोगों का देश-प्रत्यावर्तन स्वीकार कर ले जो इस वर्ष फरवरी में मीजो पहाड़ियों में हुई गड़बड़ी के दौरान बर्मा में चले गए थे ।

(ख) आपसी समझौते से 657 मीजो भारत भेज दिए गए हैं ।

(ग) इन्हें असम में एक कैंप में रखा हुआ है और उन्हें मीजो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में बसने के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ।

Acquisition of a Village near Bareilly Airport

869. **Shri Mohan Swarup ;**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a village in District Bareilly situated near Bareilly Air-port is being got vacated ;

(b) if so, the area which would be acquired ; and

(c) the action being taken regarding the payment of compensation to the inhabitants of the village ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) :

(a) Yes, Sir.

(b) 261.90 acres of land.

(c) Assessment of rental and other compensation has been taken in hand.

भूतपूर्व सैनिकों के लिये रोजगार

870. **श्री कृष्णपाल सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भूतपूर्व सैनिकों की (अधिकारी तथा अन्य श्रेणी के सैनिक) संख्या कितनी है और कितने भूतपूर्व सैनिक नौकरी में लगे हैं;

(ख) क्या उन्हें कोई भूमि दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी भूमि दी गई है तथा कितने लोगों को दी गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) :

(क) आवश्यक सूचना प्राप्य नहीं है ।

(ख) तथा (ग) सूचना राज्य सरकारों से इकठ्ठी की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Check Posts On Punjab Border

871. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact, that India has asked Pakistan that all check posts on **Punjab** border should be kept open;

(b) if so, the reponse of Pakistan; and

(c) the number of such posts which Pakistan has agreed to keep open ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) We have been informed by the Pakistan Government that the matter is receiving their attention.

(c) So far Pakistan Government have agreed to keep open only one checkpost each on the India-West Pakistan border and the India-East Pakistan border.

Clerks in Air Headquarters

872. **Shri Bade :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Unit Clerks and the number of Clerks working in the Air Headquarters, who have passed the U. P. S. C. examination;

(b) the period for which they are likely to be retained in the Air Headquarters;

(c) the criteria for keeping civilian Storekeepers in the Air Headquarters; and

(d) the extent of difference between their payscales and those of Lower Division and Upper Division Clerks ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) :

(a) Unit Clerks — Nil.

A. F. H. Q. Cadre. — 105

(b) As regards U. P. S. C. qualified Unit Clerks, the question does not arise. The A. F. H. Q. Cadre clerks referred to in (a) above are liable to be posted to any of the three Services Headquarters and Inter Service Organisations of the Ministry of Defence, depending on the exigencies of service.

(c) Civilian Storekeepers are required in Air Headquarters to deal with indents and other work pertaining to stores. They are serving against authorised establishment vacancies of Civilian Storekeepers in the various Directorates of Air Headquarters.

(d) Pay Scales of Civilian Storekeepers, Lower Division Clerks are given below :

(i) **Civilian Storekeepers**

Grade I - Rs. 335-15-425.

Grade II - Rs. 278-10-290-15-380.

Grade III - Rs. 210-10-290-15-335.

Grade IV - Rs. 150-5-160-8-240-EB-8-280-10-300.

(ii) Lower Division Clerks

Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180 (both AFHQ and Unit Cadre)

(iii) Upper Division Clerks

AFHQ Cadre-Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280.

Unit Cadre-Rs-130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300.

Electronic Workshop in Hyderabad

873. **Shri Bade :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2513 on the 21st March, 1966 and state :

(a) whether the details for setting up an Electronic plant at Hyderabad have been worked out;

(b) if so, when this work will be completed; and

(c) the articles that will be manufactured there ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) :

(a) to (c) Proposars to manufacture additional items in the Electronics Factory at Hyderabad are under consideration and have not been finalised.

बम्बई में फिल्म डिवीजन का मुख्यालय

874. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह हाल ही में बम्बई में फिल्म डिवीजन के मुख्यालय में गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने वहाँ पर काम करने की दयनीय दशा तथा सामान आदि रखने की अत्यन्त खराब व्यवस्था देखी थी ; और

(ग) चालू वर्ष में सरकार का इस मामले में क्या निश्चित कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) यह सही है कि काम करने की दशा, और सामान आदि रखने की सुविधाएं सन्तोष-प्रद नहीं हैं ।

(ग) वर्तमान इमारत की सामान्य देख रेख और मरम्मत केन्द्रीय लोक कर्म विभाग करता है । सरकार का विचार बम्बई में फिल्म विभाग के मुख्यालय के लिए एक बहु मंजिली इमारत बनाने का है । केन्द्रीय लोक कर्म विभाग का अनुमान है कि इमारत के प्रथम चरण पर 22.39 लाख रुपया खर्च होगा । राजसम्पत्ति प्रबन्धक ने फोर्ट क्षेत्र में कुछ जगह दी है, जहाँ पर फिल्म विभाग की वितरण यूनिट रखने का विचार है । इस प्रकार फिल्म विभाग के पास जो स्थान बचेगा, उसको सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ।

जवाहरलाल नेहरू के विषय में प्रकाशन

875. **श्री हनुमन्तैया :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात् उनके सम्बन्ध में निकाले गये विभिन्न प्रकाशनों की संख्या कितनी है और उन पर कितना व्यय हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) :

अपेक्षित जानकारी नीचे दी हुई है :—

निकाले गए प्रकाशनों की संख्या	7
उन पर हुआ खर्च	1,83,858.00 रुपए

अम्बाला छावनी बोर्ड

876. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा 1965 के पुनरीक्षण (रिव्यू) प्रार्थना पत्र संख्या 41 तथा इसके साथ 1965 की सिविल मिसलेनियस संख्या 4552 उमराव सिंह बनाम छावनी बोर्ड अम्बाला – दिनाँक 7 फरवरी, 1966 में छावनी बोर्ड अम्बाला तथा उसके अधिकारियों के विरुद्ध की गई सख्त भर्त्सना के बारे में सरकार को पता है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या उसने भविष्य में मार्ग–निर्देशन के लिये कोई आम हिदायतें जारी की हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

भारत द्वारा परमाणु बम का निर्माण

877. **श्री किशन पटनायक :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री मधु लिमये :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में भारतीय दूतावास में मंत्री, डा० पी० के० बनर्जी ने चेतावनी दी है कि यदि परमाणु हथियारों वाले देश परमाणु हथियारों के प्रसार को नहीं रोक सकते, तो भारत परमाणु बम बनाने के अपने निर्णय को बदलने के लिये बाध्य हो जायेगा ।

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने कहा था कि भारत 18 महीने में एक बम बना सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इन वक्तव्यों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) भारतीय राजदूतावास वाशिंगटन; में मंत्री, डा० पी० के० बनर्जी ने 3 जून 1966 को गनिनसन, कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमरीका में अपने भाषण में कहा था :

"उस दिन सेनेटर रोबर्ट एफ० केनेडी ने सीनेट में अपने एक भाषण में कहा था कि भारत पहले ही अस्त्र-कोटि में है, उसके पास खंडनीय (फिशनेबल) सामग्री है और कुछ ही महीने में परमाणु अस्त्र बना सकता है।" फिर भी, भारत के सभी प्रधान मंत्रियों ने बार-बार अपने इस निश्चय को दोहराया है कि वे बम नहीं बनाऐंगे। हम परमाणु शक्ति का विकास शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना चाहते हैं। किन्तु संसार को, विशेषकर, परमाणु अस्त्रों वाले देशों को, हमारे इस आत्म-त्याग को हमारा कर्तव्य और अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए। हमें इस बात का समुचित आश्वासन मिलना चाहिए कि इस विवरण के बारे में समझौता हो जाएगा और जल्दी ही हो जाएगा। अगर परमाणु अस्त्रों वाले देशों में परमाणु-अस्त्रों के फैलाव और उत्पादन के बारे में सहमति नहीं हुई तो हो सकता है भारत अपने निर्णय पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर हो जाए। एक लोकतंत्र के नाते, भारत सरकार को जनता की मांग के आगे झुकना ही होगा। वह किसी निर्णय को स्थगित कर सकती है किन्तु उसे टाल नहीं सकती। क्योंकि, तानाशाही की तरह हम जनभावना को दबा नहीं सकते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) इस वक्तव्य का उद्देश्य भारत के इस निर्णय पर बल देना था कि वह परमाणु शक्ति का विकास शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेगा बम बनाने के लिए नहीं। साथ ही इसमें उस स्थिति को भी स्पष्ट रूप से रखा गया है जो कि परमाणु अस्त्रों के फैलाव और उनके प्रयोग को रोकने से संबद्ध संधि के संपन्न न होने से उत्पन्न हो सकती है।

भारत की अब भी यह दृढ़ नीति है कि वह परमाणु शक्ति का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों में करेगा और 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति में तथा संयुक्त राष्ट्र में भी यह कोशिश करता रहेगा कि परमाणु अस्त्रों के उत्पादन को रोकने के बारे में संधि हो जाए और आम तथा पूरे निरस्त्रीकरण के बारे में समझौता हो जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

878. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशी फिल्म निर्माताओं से अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जिसकी दिल्ली में होने की संभावना है, उनकी फिल्मों के प्रदर्शन के लिये उन्हें विदेशी मुद्रा में किये जाने वाले भुगतान में कमी करने के बारे में बात चीत की थी;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) रुपये के अवमूल्यन के कारण फिल्म समारोह आयोजित करने पर होने वाले व्यय में सम्भावित वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी, नहीं। अगला अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह करने का प्रश्न अभी विचारधीन है ;

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठते।

रूस द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण

879. **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री हेम बरुआ : **श्री नाथ पाई :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने भारत-अमरीकी प्रतिष्ठान, उर्वरक कारखानों तथा चौथी योजना के लिये अमरीका और विश्व बैंक से सहायता के बारे में सरकार की नीतियों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो रूस द्वारा उठाई गई आपत्तियों तथा पूछे गये प्रश्नों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

कटक में स्टाफ आर्टिस्ट

880. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून 1966 तक कटक (उड़ीसा) स्थित आकाशवाणी केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्ट तथा अन्य कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले अनुसूचित तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की संख्या कितनी थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियाँ
स्टाफ आर्टिस्ट	—	—
अन्य कर्मचारी	27	1
कुल:	27	1

विदेशों में भेजे गये प्रतिरक्षा अधिकारी

881. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में प्रतिरक्षा सेवाओं के कितने अधिकारी विदेशों में भेजे गये ; और

(ख) वे किन-किन देशों में भेजे गये ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) :

(क) 14 (इस में प्रतिक्षण के लिए विदेश भेजे गए अफसरों की संख्या शामिल नहीं है)।

(ख) इथोपिया

स्वीडन

संयुक्त अरब गणराज्य

यू० के०

यू० एस० ए०

यू० एस० एस० आर०

पश्चिमी जर्मनी

युगोस्लाविया ।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के प्रधान

882. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में विदेशों में स्थित किन-किन भारतीय मिशनों के प्रधानों की नियुक्ति कर दी गई है ; और

(ख) कौन से पद अभी तक रिक्त हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) भारतीय मिशनों के नए प्रमुखों ने इन स्थानों पर कार्यभार संभाल लिया :

1. कम्पाला
2. बुडापेस्ट
3. अदिस अबाबा
4. बेल्ग्रेड
5. सिंगापुर
6. काहिरा
7. द हेग
8. स्टाकहोम
9. कोनाक्री
10. ओटावा
11. रिओ द जनेरिओ
12. अक्रा
13. ओस्लो

(ख) :

1. मोगादिशू
2. मास्को
3. प्राग
4. ब्रसेल्स

सिक्किम में कागज की लुग्दी की परियोजना

883. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री सिक्किम में कागज की लुग्दी की परियोजना के बारे में 25 अप्रैल 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1318 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना की व्यवहारिता संबंधी सर्वेक्षण कराने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) एप्लाइड इकानामिक रिसर्च, नई दिल्ली की राष्ट्रीय परिषद आजकल सर्वेक्षण कर रही है।

क्षेत्रीय आकाशवाणी निदेशक

884. **श्री रामचंद्र उलाका :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री 9 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4965 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में आकाशवाणी का एक क्षेत्रीय निदेशालय स्थापित करने के बारे में सरकार ने इस बीच निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादुर) :

(क) मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

भारत तथा चीन के बीच शिखर सम्मेलन

885. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **डा० महादेव प्रसाद**
श्री श्रीनारायण दास : **श्री मधु लिमये :**
श्री मे० क० कुमारन : **श्री राम सेवक यादव :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नासिर ने भारत तथा चीन के बीच शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह शिखर सम्मेलन कब तथा कहां होगा ; और

(ग) इसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की जायेगी ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : **प्रश्न नहीं उठते।**

सशस्त्र सेना के वेतन-क्रम

886. **श्री अ० व० राघवन :** **श्री पोट्टेकाट :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण करने के लिये एक वेतन आयोग बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब आयोग स्थापित किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका में भारतीयों के विरुद्ध जारी किये गये गिरफ्तारी के वारन्ट

887. **श्री कोल्ला वेंकैया :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा भारतीय चर्च न्यूयार्क के आर्चबिशप (के० चगालवरैया पिल्ले) दत्तामेय एफ० सावरकर नामक एक पत्रकार के विरुद्ध गिरफ्तारी के वारन्ट जारी किये गये थे ;

(ख) यदि हां तो गिरफतारी के वारन्ट जारी किये जाने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या सम्बन्धित व्यक्तियों के न्यायोचित हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने कोई प्रयास किया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) अमेरिकन नेशनल बैंक आफ पोर्ट्समाउथ वरजीनिया, को धोखा देने का षड़यंत्र रचने के आरोप में।

(ग) से (ङ) : चूंकि श्री पिल्ले देशीकृत अमरीकी नागरिक हैं, इस कारण हमारे लिए उनके हितों की रक्षा करने का प्रश्न नहीं उठता। श्री सावरकर ने, जो कि भारतीय राष्ट्रिक हैं, न तो वाशिंगटन-स्थित भारतीय राजदूतावास की मदद ली है और न न्यूयार्क-स्थित प्रधान कोंसलावास की। लेकिन, न्यूयार्क-स्थित भारतीय प्रधान कोंसलावास ने न्यूयार्क में श्री सावरकर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी किन्तु उनसे संपर्क हो नहीं पाया।

भारतीय सैनिक संग्रहालय

888. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक भारतीय सैनिक संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां तथा कब स्थापित किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) **तथा (ख)** : नेशनल डिफेन्स म्यूज़ियम स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया गया है। तदपि, उस पर आगे विचार करना स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि महसूस किया गया है इस प्रकार के म्यूज़ियम की स्थापना के लिए वर्तमान् समय उपयुक्त न होगा।

अर्जन्तीना की नई सरकार को मान्यता

889. **श्री रामहरख यादव** : **श्री प्र० चं० बरुआ** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्जन्तीना में हाल में हुई रक्तहीन क्रान्ति के पश्चात् सरकार ने वहां की नई सरकार को मान्यता प्रदान कर दी है ; और

(ख) उस सरकार के साथ किस प्रकार के राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये गये ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) :

(क) जी हां।

(ख) भारत और अर्जन्तीना दोनों का प्रतिनिधित्व राजदूतावास के स्तर पर बना हुआ है।

मारिशस

890. **श्री राम सेवक यादव** : **श्री मधु लिमये** :

श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारिशस संबंधी बैनवेल आयोग ने गैर-लोकतन्त्रात्मक चुनाव पद्धति की सिफारिश की है;

(ख) क्या बैनवेल प्रतिवेदन की कई दलों ने निन्दा की है जिसमें लेबर पार्टी भी शामिल है जो इस समय श्री रामगुलाम के नेतृत्व में शासन चला रही है ;

(ग) मारिशस की स्वतंत्रता के अवसर पर इस नई घटना के प्रति भारत के राष्ट्रमंडल का एक सदस्य होने के नाते सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या ब्रिटिश सरकार को यह प्रतिक्रिया बता दी गई है ; और

(ङ) यदि ब्रिटिश सरकार ने इस बारे में कोई उत्तर दिया है तो वह क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) भारत सरकार मारिशस में एक व्यक्ति-एक-वोट के आधार पर बहुसंख्यक शासन का समर्थन करती है और प्रतिबंधित मतदान के ऐसे किसी भी तरीके के खिलाफ है जो बहुसंख्यक आबादी के हितों के विरुद्ध हो। अगर जरूरी हुआ तो, भारत सरकार इस संबंध में अपने विचारों को सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रमंडल मंचों पर बलपूर्वक रखने के लिए तैयार है।

(घ) और (ङ) : ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि बैनवैल कमीशन की सिफारिशों में बहुत परिवर्तन कर दिए गए हैं जिससे मारिशस के प्रधान मंत्री, डा० रामगुलाम, सरकार में उनके सहयोगी तथा सभी राजनीतिक दलों के नेता प्रत्यक्षत: संतुष्ट हैं।

Anti-Indian Propaganda by Canada Broadcasting Corporation

891. **Shri Bade :** **Shri Kashi Kam Gupta :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Television Department of Canada Broadcasting Corporation broadcast on the 2nd May, 1966 that parents in East India were selling their children for 10 cent or 45 paise; and

(b) if so, the action taken by Government to counteract the same ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) :

(a) The Canadian Broadcasting Corporation in its newscast on the 2nd May, 1966 used a UPI message on severe food scarcity in parts of Orissa. This message quoted as its source a report published in an Indian paper by an Indian correspondent who claimed to have toured the affected area. The report stated **inter alia,** that children were being abandoned or sold for 50 cents.

(b) Our High Commission in Canada took up this matter with the Canadian Broadcasting Corporation. The latter stated that they used this news item in good faith in view of the widespread interest in Canada in giving food aid to India. Another reason given for using this news item was that it was stated to have emanated from an Indian correspondent and was published in an Indian newspaper. However, they promised to handle such material with due care in future. Subsequently the Canada Broadcasting Corporation also carried the story of the Food Minister's statement in the Rajya Sabha on the 5th May that reports of deaths in Orissa and other places had been investigated and found incorrect.

पालम हवाई अड्डा क्षेत्र से टायरों और ट्यूबों की चोरी

892. **श्री गुलशन :** **श्री काशी राम गुप्त :**
श्री बड़े : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना के 20,000 रूपये की लागत के टायर और ट्यूब 23 मई, 1966 को पालम हवाई अड्डा क्षेत्र से चोरी गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक पुलिस द्वारा की गई जांच से क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) कुछ विमानों के और एम० टी० टायर पालम के वायु सैनिक अड्डे से चोरी हो गए हैं। चोरी का पता 27 जून 1966 को चला था। चुराई गई मदों की कीमत एक कोर्ट आव इन्क्वायरी द्वारा निर्धारित की जा रही है। क्षति का अस्थायी अनुमान लगभग 20,000 रूपये का है।

(ख) असैनिक पौलीस द्वारा जांच अभी प्रगतिशील है।

सेना में भर्ती

893. **श्री मा० ल० जाधव :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में अधिकारियों की भर्ती किस तरीके से की जाती है ;

(ख) शारीरिक तथा बौद्धिक परीक्षाओं के सम्बन्ध में किन-किन मुख्य बातों को ध्यान में रखा जाता है ; और

(ग) उम्मीदवारों का साक्षातकार किस भाषा में किया जाता है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) :

(क) अफसरों को निम्न तरीकों से भर्ती किया जाता है और विभिन्न प्रकार की कमीशनें दी जाती हैं :—

स्थायी कमीशनें

यू० पी० एस० सी० द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा द्वारा और नियुक्तियों के लिये सर्विसिज़ सिलेक्शन वोर्डज द्वारा आयोजित इण्टर्व्यु द्वारा खुली भर्ती से

(1) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए, जहां उम्मीदवारों को भारतीय सैनिक अकादमी में भर्ती से पहले तीन वर्षों के प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे; और

(2) सीधे भारतीय सैनिक अकादमी के लिए ।

2. तकनीकी ग्रेजुएट्स के लिए भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश के लिए सर्विसिज़ सिलेक्शन बोर्डो द्वारा आयोजित इण्टर्व्यु के परिणामस्वरूप खुली भर्ती से ।

3. भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश के लिए सर्विसिज़ सिलेक्शन बोर्डो द्वारा आयोजित इण्टर्व्यु के परिणामस्वरूप (नेशनल केडेट कोर) आफिसर ट्रेनिंग यूनिट में सफलता से प्रशिक्षण पाए ग्रेजुएटों से ।

4. सर्विसिज़ सिलेक्शन बोर्डो द्वारा आयोजित इण्टर्व्यु के परिणामस्वरूप आर्मी केडेट कालिज में प्रवेश के लिए सेवा कर रहे सैनिकों से, जहां भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश से पहले केडेट 18 मास के लिए प्रशिक्षण पाते हैं ।

5. जहां तक आर्मी मेडिकल कोर में भर्ती का संबंध है स्थायी कमीशनें यू० पी० एस० सी० द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणामस्वरूप, ए० एम० सी० द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम-स्वरूप, ए० एम० सी० सिलेक्शन बोर्ड द्वारा इण्टर्व्यु के पश्चात् दी जाती हैं । उच्च अर्हता प्राप्त और अनुभवी असैनिक उम्मीदवारों की दशा में भर्ती यू० पी० एस० सी० परीक्षा के बिना ए० एम० सी० सिलेक्शन बोर्ड की इण्टर्व्यु के पश्चात् की जाती है ।

6. आर्मी डेंटल कोर के संबंध में भर्ती ए० डी० सी० सिलेक्शन बोर्ड की इण्टर्व्यु के परिणामस्वरूप की जाती है ।

7. जहां तक मिलिटरी नर्सिंग सेवा का संबंध है नर्सें तीन वर्षों के प्रशिक्षण के लिए प्रोबेशन पर भर्ती की जाती हैं, जिस की समाप्ति पर उन्हें स्थायी कमीशनें प्रदान की जाती हैं ।

अल्पकालीन सेवा कमीशनें ।

1. आफिसर ट्रेनिंग स्कूल मद्रास में प्रशिक्षण के लिए इण्टव्यु बोर्ड द्वारा चयन प्रिलिमिनरी तथा सर्विसिज़ सिलेक्शन बोर्डो की इण्टव्यु के बाद खुली भर्ती से ।

2. अनिवार्य सेवा देयता योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय/राज्य सरकारों राजकीय उपक्रमों में काम करने वाले इंजीनियर अफसरों से । वह प्रथम और द्वितीय श्रेणी अफसर एस० एस० बोर्डो द्वारा इण्टव्यु नहीं किए जाते जो यू० पी० एस० सी०/राज्य जन सेवा आयोग/सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों पर असैनिक सेवाओं में भर्ती किए गए थे, परन्तु अन्य प्रथम और द्वितीय श्रेणी अफसर सर्विसिज़ सिलेक्शन बोर्डों द्वारा इण्टव्यु के परिणामों के आधार पर चुने जाते हैं ।

3. आर्मी मेडिकल कोर में भर्ती के संबंध में चुनाव अकेन्द्रीकृत ए० एम० सी० सिलेक्शन बोर्डों द्वारा इण्टव्यु के आधार पर की जाती है ।

4. आर्मी डेंटल कोर के संबंध में चुनाव ए० डी० सी० सिलेक्शन बोर्ड द्वारा इण्टव्यु के परिणामों के फलस्वरूप की जाती है ।

आपाती कमीशनें

यह कमीशनें इस समय केवल आर्मी मेडिकल कोर में दी जाती हैं । चुनाव अकेन्द्रीकृत ए० एम० सी० सिलेक्शन बोर्डो द्वारा इण्टव्यु के आधार पर की जाती है ।

अस्थायी कमीशनें

यह कमीशनें केवल मिलिटरी नर्सिंग सेवा में दी जाती हैं । भर्ती लिखित परीक्षा के पश्चात सिलेक्शन बोर्ड द्वारा इण्टव्यु से की जाती है ।

(ख) उम्मीदवारों की उनकी अफसरी गुणों को निर्धारित करने के लिए विशेष अभिकल्पित वैज्ञानिक परीक्षाओं द्वारा, सिलेक्शन बोर्डो द्वारा परीक्षा ली जाती है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति किसी प्रकार की ऐसी निर्योग्यता से विमुक्त है जिस से उस के काम के क्षमतापूर्वक निष्पादन में बाधक होने की संभावना है, उम्मीदवार के मानसिक तथा शारीरिक क्षमता-स्तर का परीक्षण किया जाता है ।

(ग) सर्विसिज़ सिलेक्शन बोर्डो में उम्मीदवार की परीक्षा अंग्रेजी के माध्यम से की जाती है, क्योंकि प्रशिक्षण संस्थानों में सिखलाई का माध्यम अंग्रेजी है । तदपि अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को अनुचित महत्व नहीं दिया जाता ।

आकाशवाणी के कर्मचारियों के लिये सवारी सम्बन्धी सुविधाएं

894. **श्री जंबे :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रात के समय काफी देर तक काम करने वाले आकाशवाणी, नई दिल्ली के कर्मचारियों के परिवहन पर सरकार ने गत पांच वर्षो के दौरान, वर्षवार, कितना खर्च किया ;

(ख) उक्त प्रयोजन के लिये कुल कितनी मोटर गाड़ियां रखी गईं और (एक) उनकी खरीद पर कितना खर्च आया तथा (दो) उनके रख-रखाव और उनके चालकों आदि के वेतन पर पिछले पांच वर्षों में अन्य आवर्ती खर्च, अलग-अलग, कितना आया ; और

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों के लिये गोल मार्केट क्षेत्र में अथवा आकाशवाणी के निकट किसी

अन्य स्थान पर विशेष आवास की व्यवस्था करके सरकार के लिये मितव्ययता के हित में इस भारी फिजूल खर्च को बन्द करना सम्भव नहीं है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) :

(क) रात के समय काम करने वाले आकाशवाणी के कर्मचारियों को परिवहन देने पर खर्च के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ख) मोटर गाड़ियां तथा ड्राइवर आदि केवल रात में काम करने वाले कर्मचारियों को ले जाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किये जाते बल्कि अन्य कामों के लिए भी किये जाते हैं, जैसे कलाकारों और वार्ताकारों को दिन या रात में ले जाने के लिये, बाहर के समारोहों के प्रसारण का प्रबंध करने के लिये कर्मचारियों को ले जाने के लिए, आदि । इस लिये केवल रात के समय कर्मचारियों को ले जाने पर कितना खर्च आया यह बताना सम्भव नहीं । फिर भी, एक विवरण संलग्न हैं, [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल टी 6593–66] जिसमें यह बताया गया है कि पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितनी गाड़ियां इस्तेमाल में थीं, उनका क्या मूल्य है, उनके रख-रखाव पर क्या खर्चा हुआ और ड्राइवरों को कितना वेतन आदि दिया गया ।

(ग) नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवास, निर्माण तथा नगर विकास मन्त्रालय के बनाये गये नियमों के अनुसार 'जनरल पूल' से मकान दिए जाते हैं । ये नियम आकाशवाणी के कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं ।

आणविक प्रभाव

*895 **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री दशरथ देव : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जुलाई, 1966 को नई दिल्ली के साप्ताहिक 'सेंचुरी' में प्रकाशित निम्नलिखित टिप्पणी की ओर दिलाया गया है :

> "आणविक परीक्षण चाहे वे आकाश में, पानी में या भूमि के नीचे कहीं भी किये जाएं, मानव या पशुओं के भविष्य के लिये समान रूप से खतरनाक हैं । रेडियोधर्मी तत्व हमारे ऊपर से गिरें या पानी के जरिए मानव-शरीर में पहुँचाये जायें, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता खतरा किसी हालत में कम नहीं होता ।"

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में विशेषज्ञों की राय ले ली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) हमारे विशेषज्ञों के अनुसार आणविक परीक्षणों से होने वाले खतरे अनेक कारणों पर निर्भर करते हैं जैसे विस्फोट का साइज़, स्थान तथा रेडियोधर्मी संदूषण से बचाव के लिए की गई सावधानी, आदि । वायुमंडल में किए गए विस्फोट ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनसे पैदा रेडियोधर्मी धूलि वायुमंडल में चारों तरफ चक्कर काटती है, जबकि पानी में किए गए विस्फोट

से उत्पन्न संदूषण एक स्थान पर ही रहता है बशर्ते ऊपर का वायुमंडल भी दूषित न हो। यदि भूमि में अधिक गहराई पर विस्फोट किया जाये तथा पूरी तरह यह ध्यान रखा जाये कि भूमि की सतह से ऊपर कोई विस्फोट न हो तो भूमि पर रेडियोधर्मिता फैलने का कोई खतरा नहीं रहता।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

896. **श्री अ० क० गोपालन** : **श्री म० ना० स्वामी** :
श्री दशरथ देव : **श्री दीनेन भट्टाचार्य** :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 12 जुलाई, 1966 को प्रतिरक्षा कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल में कितने कर्मचारियों ने भाग लिया था ;

(ख) तो हड़ताल किन कारणों से हुई थी ; और

(ग) क्या हड़ताल में भाग लेने वाले कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) :

(क) तथा (ग) : आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है, और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) हड़ताल, रक्षा असैनिक कर्मचारियों के लिए, नेगोशिएटिंग मशीनरी फिर से चालू न करने के विरुद्ध की गई थी।

गाजा में भारतीय दस्ता

897. **श्री प० कुन्हन** : **श्री म० ना० स्वामी** :
डा० सारादीश राय : **श्री इम्बीचीबावा** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने गाजा में तैनात भारतीय सैनिक दस्ते की संख्या घटाने के लिये सरकार से कहा है ;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने सैनिकों की संख्या कम करने का प्रस्ताव रखा है ;

(ग) क्या संख्या कम करने का प्रस्ताव रुपये के अवमूल्यन के कारण किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र ने 110 कर्मचारियों को कम करने का प्रस्ताव किया था। यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया है और भारत सरकार ने इसे क्रियान्वित भी कर दिया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना पर खर्च कम करने के विचार से संयुक्त राष्ट्र ने गाजा-स्थित राष्ट्रीय सैन्यदलों में कमी करने का प्रस्ताव किया था।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों को भूमि का दिया जाना

898. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री बागड़ी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हर प्रतिरक्षा कर्मचारी को उसके अपने मूल निवास-स्थान में या उसके निकट कृषि के लिये अथवा मकान-निर्माण के लिये भूमि दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों के विभिन्न रैंकों के बारे में (श्रेणी-वार) इस योजना का क्या ब्यौरा है ;

(ग) इस भूमि को नियतन करने का किसको अधिकार होगा ;

(घ) एक सैनिक किस प्रकार की और कितनी अवधि तक सेवा करने के पश्चात् भूमि लेने का हकदार हो जाता है ; और

(ङ) चालू वर्ष में पंजाब में (जिले-वार) होशियारपुर और कांगड़ा जिलों को मिलाकर कितने मामलों में भूमि आवंटित की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) :

(क) प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक को अपने गांव में या उसके पास शामलात भूमि से कृषि के लिए अथवा मकान बनाने के लिए भूमि अलाट करने संबंधी किसी योजना का सरकार को ज्ञान नहीं है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) राज्य सरकार को कहा गया है, कि उन की यदि कोई ऐसी योजना है, तो आवश्यक सूचना दें, और जभी प्राप्त हुई, सूचना सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

Radio-active Fall-out Detection Centres

899. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of Centres at present in the country which can detect fall-out of radio active dust;

(b) the places where these Centres have been established; and

(c) whether any new schemes for the extension of such Centres have been framed ?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) Ten.

(b) These places are ;

1. Bangalore
2. Bombay
3. Calcutta
4. Delhi
5. Nagpur
6. Ootacamund
7. Srinagar
8. Gulmarg

9. Nainital

10. Gangtok (Sikkim)

In addition samples of milk are collected periodically from 30 stations spread all over the country.

(c) No Sir.

Assistance to Tanzania

900. **Shri Rameshwaranand ; Shri Raghunath Singh :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Government of Tanzania have recently approached Government for giving assistance in the shape of technicians and machine tools for running industries there; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) :

(a) to (b) :

Government of India have agreed to render the assistance requested by the Government of Tanzania. Machinery and Equipment for a Handicraft and Cottage Industries Training Centre, proposed to be established in Tanzania, is expected to be despatched by the end of August, 1966. Experts in wood-working, metal working and basket making are also being deputed for this Training Centre and they will be leaving shortly.

Literature on Family Planning

901. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry are supplying literature on family planning to the public direct by post;

(b) if so, to which class of the public this literature is being supplied; and

(c) whether any programme has been chalked out for its extension ?

Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) :

(a) Yes, Sir,

(b) The literature is supplied to anyone on request in response to our advertisements on Family Planning offering free supply of literature or otherwise.

(c) A scheme is now under consideration to introduce a direct mailing system of lirerature to supplement the present bulk distribution through State, district and block agencies.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

संयुक्त राज्य अमरीका से आयात किये गये खाद्यान्न में लोहे के टुकड़े, कंकड़ आदि पाये जाने के समाचार

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, I call the attention of the

Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation to the reported presence of iron strips, stones etc. in the wheat and other foodgrains imported from U. S. A. under PL-480 and request that he may give a statement in regard thereto.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : जैसा कि सदन को मालूम ही है, संयुक्त राज्य अमेरिका से पी० एल० 480 के अधीनगत कई वर्षों से, अब बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बन्दरगाहों पर जहाजों में माल लादने से पूर्व और भारतीय बन्दरगाहों पर माल उतारते समय इन खाद्यानों की विहित मानकों के अनुसार मानव उपभोग के लिए इसकी उपयुक्तता, किसी विजातीय पदार्थ की मिलावट आदि के बारे में विस्तृत निरीक्षण किया जाता है। भूतकाल में इन खाद्यान्नों में विजातीय पदार्थों जैसा कि लोहे की कतरनों के होने के बारे में नाम-मात्र ही शिकायतें रही हैं। तथापि, हाल ही में बम्बई और कलकत्ता से कुछ प्रेषणों में ऐसे विजातीय पदार्थों के होने के बारे में कुछ शिकायतें सरकार के ध्यान में लायी गयीं हैं। अनुमान यह है कि इन खाद्यानों में जो कुछ लोहे की कतरनें आदि मिली हुई पायी गयी हैं वे जहाजों के फलकों की फौलाद की अन्दरूनी जंगआलूदा दीवार के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। जिन जहाजों में खाद्यान्नों को बोरियों में डालने का काम जहाज के खावों में होता है वहां ऐसे विजातीय पदार्थों का अधिक आसानी से पता लगाना सम्भव होता है लेकिन उन टैंकरों के मामले में जहां अनाज जहाज के खावों से वायवीय विसर्जक मशीनों द्वारा खाद्यदानियों (हापर) में डाला जाता है और खाद्यदानियों से सीधे बोरियों में भरा जाता है वहां इसका पता लगाना बहुत ही कठिन है। कभी-कभी वायवीय विसर्जक मशीनों द्वारा ऐसी विचित्र धातु के टुकड़े खींचने और यन्त्रीकृत प्रक्रियाओं से अनाज के साथ बोरियों में भरे जाने की सम्भावना है। तथापि, जब कभी भी ऐसे धातु के टुकड़े पता न लगने पर बोरियों में चले जाते हैं तो आटा मिलों में प्राय: आवश्यक रूप से इनका पता लगा लिया जाता है और ये अलग कर दिए जाते हैं। इन मिलों में सक्रीन रूम मशीनरी जिनमें बहुत से मामले में चुम्बकीय पृथक्कारी यन्त्र भी शामिल है, होनी अपेक्षित है। हाल ही की शिकायतों के मामलों में आगामी विस्तृत छान-बीन का काम प्रगति पर है जबकि भारतीय सप्लाई मिशन, वाशिंगटन को कड़ी हिदायतें जारी की गयी हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि लदान बन्दरगाहों पर खाद्यान्न लाने वाले जहाजों के खावों को अच्छी तरह साफ किया जाए और खुले अनाज के साथ ऐसे विजातीय पदार्थों के मिलने की सम्भावना बहुत ही कम हो। भविष्य में इन घटनाओं को रोकने के लिए अपनी बन्दरगाहों पर भी विसर्जक उपकरणों में उपयुक्त सुधार करने के उपाय भी किए जा रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : Our Supply Mission used to inspect the foodgrains supplied under P. L. 480, but under the new agreement the food Minister has ordered direct supplies to be made from liberty ships. Ii have also come to know that the atta, which is imported, is being fumigated. May I know whether such atta is fit for human consumption ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : गेहूँ लिबर्टी जहाजों में जमा नहीं रखा जाता। मैंने ऐसा नहीं सुना है। हम आटे और मैदे का आयात नहीं कर रहे हैं। हमें अभाव के दिनों में कुछ मैदा और आटा उपहार में दिया गया है। मेरे विचार में मैदे तथा आटे को धुआं नहीं दिया जाता है।

Dr. Ram Manohar Lohia : (Farukhabad) : I would like to know the year in which the food was produced that was supplied to us during 1965 and 1966. I would like to know the percentage of this wheat affected by weevila insects.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह गेहूँ अवश्य ही एक अथवा दो वर्ष पहले पैदा किया गया होगा। हम जहाजों में ढुलाई से पहले यह देखते हैं कि क्या यह खाद्यान्न मानवीय उपयोग के लिए ठीक है। हम यह भी देखते हैं कि क्या उनको वीवल कीड़ा लगा हुआ है या नहीं। यदि ऐसा हो तो हम उसे अस्वीकार कर देते हैं।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Whether the Government are aware that the presence of bones, stones and scraps in wheat has spoiled the Components of flour mills ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे आटे की मिलों से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : वक्तव्य में कहा गया है कि अमरीका में माल जहाजों में लादने से पहले और यहां पर उतारने से पहले विस्तृत जांच की जाती है, क्या इसका अर्थ यह है कि हम क्रय के स्त्रोत पर खाद्यान्न की जांच नहीं कर सकते ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमें उसे स्वीकार करने अथवा रद्द करने का अधिकार है। हम माल की जांच करते हैं। हम खाद्यान्न लेने से पहले यह देखते हैं कि क्या वह हमारे निर्धारित स्तर पर पूरा उतरता है अथवा नहीं। हम पहले क्रय के स्थान पर और उसके बाद पत्तन पर गेहूँ की जांच करते हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : (शिवसागर) : आसाम, पश्चिमी बंगाल तथा बिहार में 35 मिलों में क्षमता से आधा काम हो रहा है। तब पी० एल० 480 के अन्तर्गत मैदा और सूजी का आयात क्यों किया जाता है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैदा तथा सूजी का पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात नहीं किया जाता। वह हमें विभिन्न देशों से उपहार में मिला था।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

चीन को भेजा गया सरकारी नोट

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं भारत सरकार के दिनांक 28 जुलाई, 1966 के नोट, जो भारत स्थित चीन के दूतावास को दिया गया था, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी** 6580/66]

सीमाशल्क अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 673 जो दिनांक 20 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) श्रीलंका असबाब (संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 2 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1047 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० एस० आर 1121 जो दिनांक 12 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी** 6581/66]

(2) केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय विक्रय-कर (रजिस्ट्रीकरण तथा कुल बिक्री) संशोधन नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 14 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 697 में प्रकाशित हुए थे।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी** 6582/66]

(3) वित्त अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत जारी किये गये आय-कर (निर्यात लाभों का निर्धारण) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 11 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2080 में प्रकाशित हुए थे।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी** 6583/66]

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

कार्यवाही सारांश

श्री सिद्धनजप्पा (हसन) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की 20 और 21 जुलाई, 1966 को हुई 24वीं और 25वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूँ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमान, मैंने पिछले अधिवेशन में भी यह मामला उठाया था कि संसद-कार्य मन्त्री के रवैये के कारण समिति का काम लगभग ठप्प हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में उत्तर मांगा है। उनका उत्तर मिलने पर आपको अवसर दिया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Mr. Speaker, Sir, I want to seek an information. On Friday you were pleased to ask the Government to make a statement regarding cow slaughter. I would like to know when that statement will be made.

Mr. Speaker : It is not proper for the hon. Member to raise this matter every day. The hon. Member may kindly sit down.

Shri Hukum Chand Kachhavaiya : I request you to kindly get this information from the Government.

Mr. Speaker : I have repeatedly asked the hon. Member to sit down.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Speaker, Sir,....

Mr. Speaker : Shri Kachhavaiya may kindly leave the House.

(इसके पश्चात श्री हुकमचन्द कछवाय सभा से उठकर चले गये।)

(Shri Hukam Chand Kachhavaiya then left the House)

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Mr. Speaker, Sir, we would like to know when that statement will be made.

Mr. Speaker : If you go on interrupting like this I will have to ask you to go out. (**Interruptions**) You may kindly sit down.

Shri Rameshwaranand : I am ready to obey you but I request you to kindly get this information.

Mr. Speaker : I ask you to leave the House.

इसके पश्चात्, श्री रामेश्वरानन्द सभा से उठकर चले गये ।

(**Shri Rameshwaranand then left the House.**)

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : औचित्य प्रश्न पर मैं यह पूछना चाहता हूँ कि श्री हुकम चन्द कछवाय और श्री रामेश्वरानन्द ने सरकार से केवल यह जानने की मांग की है कि उनके द्वारा उठाये गये प्रश्न पर सरकार कब तक वक्तव्य देगी ।

अध्यक्ष महोदय : जन संघ दल के नेता को जानना चाहिये कि उनकी यह बात आपत्ति जनक नहीं थी । मैंने उन्हें कई बार बैठ जाने को कहा था क्योंकि मैं ने सरकार से इस विषय पर अपनी नीति बताने को कहा हुआ है ।

श्री जसवन्त मेहता : श्रीमान जी मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने सरकार से एक वक्तव्य देने को कहा है परन्तु यह विषय राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखता है । इसमें केन्द्रीय सरकार कैसे वक्तव्य दे सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात सरकार कह सकती है । मंत्री महोदय यह कह सकते हैं ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : गोवध का विषय एक बार पहले भी संसद के समक्ष आया था और भारत के महान न्यायवादी को अपनी राय देने के लिये बुलाया गया था । उन्होंने कहा था कि यह विषय राज्यों का है और संसद इस बारे में विधान नहीं बना सकती । इस लिये हमें पहले राज्यों से सलाह करनी होगी । इसमें समय लगेगा । हमारे विचार में इस पर मंत्रि मंडल विचार करेगा । इस लिये इस में समय लगेगा ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल) 1966-67

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (KERALA) 1966,67

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैं 1966-67 के लिये केरल राज्य के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ ।

निष्कासित सदस्यों को वापस बुलाने के बारे में

RE: RECALLING OF EXPELLED MEMBERS

श्री उ० मू० त्रिवेदी : माननीय मंत्री के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए उन माननीय सदस्यों को बुला लिया जाये जिनको सभा से चले जाने को कहा गया था ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जो मांग उन्होंने की थी उस का उत्तर वक्तव्य में मिल गया है । इसलिये उन्हें बुला लिया जाये ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह मांग उचित है ।

अध्यक्ष महोदय : विषय के बारे में कोई बात नहीं थी । प्रश्न तो अध्यक्ष पीठ के आदेश के उल्लघंन का था ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (केरल)

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (KERALA)

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं वर्ष 1962-63 और 1963-64 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (केरल) के बारे में विवरण प्रस्तुत करता हूँ ।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान जी, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त हुए इन सन्देशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य-सभा ने अपनी 27 जुलाई, 1966 की बैठक में टेलीग्राफ वायर (अवैध कब्जा) संशोधन विधेयक, 1966 को पास किया ।

(दो) कि राज्य सभा ने अपनी 27 जुलाई, 1966 की बैठक में प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक, 1966 को पास किया ।

राज्य सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक-सभा पटल पर रखे गये

BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA-LAID ON THE TABLE

सचिव: : श्रीमान जी, मैं राज्य सभा द्वारा पारित इन विधेयकों की प्रतियां सभापटल पर रखता हूँ :—

(एक) टेलीग्राफ वायर (अवैध कब्जा) संशोधन विधेयक, 1966

(दो) प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक, 1966 ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द किये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : CLOSURE OF BANARAS HINDU UNIVERSITY

श्री प्रिय गुप्त : मैंने एक ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दी थी.....मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : 18 जुलाई 1966 को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जब खुला .....

श्री हेम बरुआ : यह एक लम्बा वक्तव्य है । इसे सभा पटल पर रख दिया जाये ।

श्री मु० क० चागला : मैं इसे सभा पटल पर रखता हूँ ।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 6585/66]

श्री प्रिय गुप्त : मैंने 30 तारीख को ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दी थी । यह एक बहुत महत्व का विषय है । विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया है । कार्यकारणी परिषद के सदस्य सब गड़बड़ करा रहे हैं । शिक्षा मन्त्रालय को एक प्रबन्धक नियुक्त करना चाहिये । इस बारे में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिये । इस विषय पर यहां चर्चा होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी बात कह ली है । इसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रश्न यह है कि ध्यान दिलाने वाली सूचना को मंत्री महोदय के वक्तव्य से पहले लिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में देखूंगा । आगे के लिये ध्यान दिलाने वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

•

भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : SITUATION ON INDIA PAKISTAN BORDER

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : सितम्बर, 1965 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद से पाकिस्तान अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने के हर संभव उपाय कर रहा है । उसने पाकिस्तानी सेना, वायु सेना तथा नौसेना में सैनिकों की भर्ती बड़ी संख्या में की है । और साज-सामान भी खूब बढ़ाया है ।

जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में सेना की सँख्या में वृद्धि की गई है । सैनिक महत्व की दृष्टि से संचार व्यवस्था का भी बड़ी तेजी से विकास किया जा रहा है । असैनिकों का प्रशिक्षण भी हो रहा है । पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में अपनी सेना और वायुसेना में वृद्धि की है ।

इन बड़े पैमाने की तैयारियों में पाकिस्तान को चीन से साज-सामान जिनमें टैंक और विमान शामिल हैं और विदेशी मुद्रा की सहायता बहुत बड़ी मात्रा में मिली है । चीन द्वारा सैनिक प्रशिक्षण दिये जाने की बात भी हमारे ध्यान में आई है । पाकिस्तान एक या दो अन्य देशों से भी हथियार तथा साज सामान की सहायता मिली है और इन देशों को बीच में डालकर उसने उन देशों से साज-सामान खरीदा है जो उसको सीधे नहीं बेच सकते थे ।

हम आशा करते हैं पाकिस्तान ताशकंद के उस समझौते का आदर करेगा जिसमें उसने शक्ति का प्रयोग न करने का समझौता किया है । सरकार देश की सुरक्षा तथा प्रादेशिक अखंडता कायम रखने के अपने कर्त्तव्यों के प्रति सदैव सजग है । और समय की आवश्यकता के अनुसार किसी भी स्थिति का मुकाबला करेगी ।

निलम्बित सदस्यों के अधिकारों के बारे में

RE : RIGHTS OF SUSPENDED MEMBERS

Shri Bagri : Mr. Speakar Sir, an hon. Member belonging to my party was suspended from the service of the House for 15 days. He is a member of the Public Accounts Committee. This Committee is going to hold an extraordinary meeting in the evening. I request that the hon. Member should be allowed to attend this meeting.

Mr. Speaker : A member who has been suspended from the service of the House, he cannot be allowed to attend a meeting of the Parliamentary Committee.

संयुक्त समाजवादी दल में सदस्य के शामिल होने के बारे में

RE : ADDITION OF MEMBER TO S. S. P. GROUP

Shri Bagri : I announce this with pleasure that an hon. Member of this House Chaudhry Lakhan Das, has joined S. S. P. Group in Lok Sabha.

अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम

ADVOCATES (AMENDMENT) BILL

विधि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चें० रा० पट्टाभिरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम 1961, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को जो कि राज्य सभा ने 3 नवम्बर, 1965 को पारित किया था और लोक सभा के पटल पर 10 नवम्बर, 1965 को रखा गया था, वापिस लेने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक, जो कि राज्य सभा ने 3 नवम्बर, 1965 को पारित किया था और जिसे 10 नवम्बर, 1965, को लोक सभा के पटल पर रखा गया था, को वापिस लेने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री चें० रा० पट्टाभिरामन : मैं विधेयक वापिस लेता हूँ ।

अवैध गतिविधियां (निवारण) विधेयक

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) BILL

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : इस समय आसाम तथा देश के कुछ अन्य भागों में ऐसी स्थिति है जिस में देश से अलग होने की मांग है। इसका यथोचित ढंग से मुकाबला करना होगा। इसके अतिरिक्त विधेयक का एक दूसरा भाग है। उसका उद्देश्य यह है कि यदि विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसा के द्वारा अथवा किसी परराष्ट्र के प्रभाव के कारण कुछ कार्यों द्वारा उलटने के उद्देश्य से कोई कार्य किये जाते हैं तो उन स्थितियों का मुकाबला किया जा सके । मैं यह

भी कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक के सिद्धान्त मूल अधिकारों से संगत हैं। मैं विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : यह विधेयक संविधान न केवल संविधान के प्रति बल्कि जनता के विश्वास के प्रति एक कपट है। सरकार का उद्देश्य यह मालूम होता है कि भारत रक्षा अधिनियम के अधीन जो शक्तियां उसे प्राप्त हैं उन्हें वह स्थायी रूप से कानून ग्रन्थ में रखना चाहती है। भारत रक्षा अधिनियम तो केवल संकट काल के लिये है परन्तु यह विधेयक जनता के अधिकारों के विरूद्ध है। मुझे खेद है कि श्री नन्दा ऐसा विधेयक लाये हैं। हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि व्यक्तियों तथा संस्थाओं की अवैध गतिविधियों के अधिक प्रभावयुक्त निवारण तथा तत्सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक सभा मतविभाजन हुआ।

पक्ष में 213 : विपक्ष में 63

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री नन्दा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

अवैध गतिविधियाँ (निवारण) अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT REGARDING UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ORDINANCE

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : मैं लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत अवैध गतिविधियों (निवारण) अध्यादेश, 1966 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी 6586/66]

भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) विधेयक

DEFENCE OF INDIA (AMENDMENT) BILL

श्री नन्दा : मैं भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ। मैंने 27 अप्रैल को एक वक्तव्य में इस निर्णय की घोषणा की थी कि भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के लागू होने कुछ सीमावर्ती राज्यों तथा अन्य राज्य क्षेत्रों तक और प्रतिरक्षा से सम्बन्धित कुछ उद्देश्यों के लिये ही सीमित रखा जायेगा। उसी के आधार पर यह विधेयक लाया गया है। इसके सम्बन्ध में हम ने विधि विशेषज्ञों की राय ले ली है और उनकी यह राय है कि यह उचित है।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : हम सरकार के इस निर्णय से सहमत नहीं हैं। हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे अधिनियम को रद्द कर दिया जाये। और संकट कालीन स्थिति की उद्घोषणा को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा दल प्रतिरक्षा अधिनियम के विरुद्ध और हम चाहते हैं कि आपात कालीन स्थिति तुरन्त समाप्त कर दी जानी चाहिये। इस विधेयक द्वारा सरकार अपनी शक्तियों में वृद्धि कर रही है। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री नन्दा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1966

ADVOCATES (AMENDMENT) BILL, 1966

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अधिवक्ता अधिनियम पर आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 पर आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Braj Raj Singh (Bareilly) : I request that the suspended members may now be called in.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इस समय हम एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा करने वाले हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि निलम्बित किये गये सदस्यों को सभा में वापस बुला लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है और न ही मेरे लिये यह कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न है। परन्तु विरोधी दल के सदस्यों को अपने साथियों को अच्छा व्यवहार करने का परामर्श देना चाहिये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मैंने भरसक प्रयत्न किया था परन्तु फिर भी कुछ सदस्य

सभा से उठकर चले गये। उनके लिये ऐसा करना उचित नहीं था। अध्यक्ष महोदय फिर भी मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने निर्णय को वापस ले लें।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : दल के नेता ने इस कार्यवाही को उचित नहीं ठहराया है परन्तु वह उनको रोक भी नहीं सके। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करुंगा कि वह इस मामले पर पुनः विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपति नहीं है।

मन्त्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN COUNCIL OF MINISTERS

श्री वासुदेवन नायर : (अम्बलपुजा) : अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के समय यदि प्रधान मंत्री सभा में उपस्थित रहें तो उचित होगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा मन्त्रि-परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है।"

स्वतंत्रता के पश्चात् से आज तक सरकार को संसद से कभी इतनी प्रतारणा नहीं मिली। इसके गलत कार्यों से सचमुच ही लोगों का धैर्य टूट गया है और हम देश के कोने-कोने से सरकारी कर्मचारियों समेत जनसाधारण के सभी वर्गों से आर्द्रपूर्ण चीत्कार सुनते हैं।

यह बात भी महत्वपूर्ण है कि ठीक उसी समय जब कि अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने वाले थे सरकार ने ऐसा कानून पेश किया है जिसको कि हम पुर-स्थापित अवस्था में ही विरोध करना चाहते हैं।

अवमूल्यन और सरकार के हाल ही के अन्य कार्यों से तो भारतीय जनता की कमर टूट गई है। सरकार के इस धोखे धड़ी के कार्यों से भारत के हित, आत्म सम्मान और गौरव को गहरी ठेस पहुँची है। यह एक विशेष गुट के हित में अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों तथा भारत में उसके सहयोगियों के समर्थन से देश को बेच देने का सरकार का एक प्रयास है। मन्त्रिमन्डल के दो अथवा तीन व्यक्तियों ने, जिनकी राजनैतिक सूझ बूझ बहुत कम है, डालर-देश की यात्रा के समय इस आत्म समर्पण की प्रक्रिया में अगुआपन किया था जिसका उन्हें कोई हक नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है उनको काफी हद तक प्रधान मन्त्री का समर्थन प्राप्त है। वे इस देश का शासन चलाने के अयोग्य तथा अनुपयुक्त हैं और वास्तव में उनको अपने पद से हट जाना चाहिये।

पिछले तीन महीने के बजट अधिवेशन में वित्त तथा योजना मन्त्री ने बार बार इस बात को दोहराया था कि सरकार रुपये का अवमूल्यन नहीं करने वाली है। 17 फरवरी को योजना मन्त्री ने कहा था कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है अवमूल्यन का प्रश्न ही नहीं उठता परन्तु जिस प्रकार यह निर्णय किया गया उससे देश चकित रह गया। सरकार संसद को जानबूझ कर और योजना बद्ध ढंग से झूठी बातें बताने में जरा भी नहीं हिचकिचाई है। जबकि अवमूल्यन के बारे में संसद को अन्धकार में रखा गया तब विदेशों में निहित स्वार्थ वाले अनेक दलों को पहले ही सूचना दे दी गई थी। मैं जानता हूँ कि सरकार अपने जुर्म पर पर्दा डालने का प्रयत्न करेगी परन्तु यह सब

जानते हैं कि अमरीका ने भारत को घुटने टेकने के लिये बाध्य करने के लिये पहले ही निर्णय ले लिया था और अब सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है।

अवमूल्यन से तो इस दुर्व्यवस्था का श्रीगणेश ही हुआ है और कई गलत कदम उठाये जाने की सम्भावना है। यदि हम सावधानी से कार्य नहीं करते हैं तो इस अवमूल्यन से हमारा समस्त आर्थिक ढांचा तथा राजनैतिक स्वतंत्रता समाप्त हो जायेगी। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार में शासन करने का न तो चरित्र है और न ही क्षमता है। जनता के साथ जो अपराध किया गया है उसमें सरकार भागीदार है और यह सभा उसको क्षमा नहीं कर सकती।

वैसे तो प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में समस्त मंत्रिमन्डल ही इस बदमामी में भागीदार हैं परन्तु उनमें से कुछ प्रमुख व्यक्ति तो विशेषरूप से जनता के सामने दोषी हैं। इनमें से सर्वप्रथम योजना मन्त्री हैं। यही व्यक्ति है जिसने अमरीकी पूंजी को, ईस्ट इन्डिया कम्पनी को नये रूप में यहां प्रवेश करने की अनुमति दी है। वह दोषी हैं और देश उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा।

खाद्य मन्त्री ने एक बार कहा था कि यदि हमें भूखा रहना है तो हम तैयार हैं परन्तु हम भीख नहीं मागेंगे। परन्तु आज इस बात को बिल्कुल भुला दिया गया है और हम अमरीका से मंगाये गये अनाज के सहारे जीवित रहने की बातें कर रहे हैं। इस समस्त स्थिति की जिम्मेदारी सरकार पर ही डाली जा सकती है। प्रधान मन्त्री या तो जानती ही नहीं अथवा वह कुछ परवाह नहीं करती हैं परन्तु मैं बता देना चाहता हूँ कि इस स्थिति को केवल अमरीका से अनाज के बड़े पैमाने पर अनाज के आयात अथवा भुखमरी ही एक विकल्प नहीं है बल्कि इस स्थिति को अनाज की बड़े पैमाने पर वसूली, अनाज के व्यापार पर नियंत्रण, भूमि सुधार, खेतिहरों को अधिक प्रेरणा देकर, जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करके, चावल की मिलों का राष्ट्रीयकरण करके तथा ऐसी ही दूसरी चीजों से ठीक किया जा सकता है। परन्तु खाद्य मन्त्री अमरीका से गठबन्धन करने की नीति पर चल रहे हैं।

वित्त मन्त्री को खुद को यह बात समझाने में अधिक समय नहीं लगा कि देश का आर्थिक प्रबन्ध विश्व बेंक को सौंपने में लज्जा की कोई बात नहीं हैं। फिर भी उनका मुख्य स्थान बना हुआ है। उनके साथ वहां अन्य भी कई शक्तिशाली व्यक्ति हैं।

प्रधान मन्त्री के देश का प्रधान मन्त्री बने रहने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने स्थिति की विडम्बना को नहीं देखा है कि अवमूल्यन व्यापार को बढ़ा कर अपने आर्थिक ढांचे को बनाये रखने के लिये नहीं बल्कि अधिक सहायता प्राप्त करने के लिये किया गया है। इसके फलस्वरूप हमारी आगामी पीढ़ी को अधिक बोझ उठाना पड़ेगा। सरकार में न तो इतनी बुद्धि और न ही विश्वास है कि वह बैंकों और आयात-निर्यात का राष्ट्रीयकरण कर सकें। ये दो कदम ऐसे हैं जिनसे अवमूल्यन अनावश्यक हो जाता है। निहित हितों पर निर्भर रहने के कारण सरकार राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये ठोस कदम उठाने में असमर्थ हैं। उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण तथा वितरण प्रणाली के नियन्त्रण की ओर प्रभावी कदम उठाकर अधिक उत्पादन तथा समान वितरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये आवश्यक दृढ़ता तथा विश्वास का भी उनमें अभाव है। सरकार मूल्यों में वृद्धि को रोकने में भी असफल रही है और न ही इस ओर सरकार का कोई रुझान दिखाई देता है। प्रधान मन्त्री तथा उनके मन्त्रिगण यह कहते हैं कि अवमूल्यन में कोई वृद्धि नहीं हुई है जबकि एक सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि दैनिक उपभोग की वस्तुओं के

मूल्यों में 15 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बहुत ही अनुचित है कि हमारी प्रधान मन्त्री इतनी स्पष्ट बात भी नहीं समझ पाईं कि अवमूल्यन, उर्वरक समझौता, असीमित खाद्य आयात केवल गलत कार्य हैं बल्कि इससे हमारी स्वतंत्रता, गरिमा और राजनैतिकता को धक्का लगा है। सरकार ने भारत-अमरीकी संस्थान जैसे करारों की मंजूरी दी है जिससे हमारे देश के देशभक्तिपूर्ण बुद्धि जीवियों पर आक्षेप हुआ है।

सरकार ने वियतनाम के प्रश्न पर जो रूख अपनाया है वह और भी धक्का पहुँचाने वाली बात है। काफी समय तक प्रधान मंत्री ने इस मामले पर चुप रहने का प्रयत्न किया क्योंकि उनमें सहायता देने वालों को नाराज करने का साहस नहीं था। परन्तु जब उन्होंने वियतनाम में शान्ति के बारे में अपने प्रस्तावों और कल्पनाओं को व्यक्त किया तो उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें इनके लिये किसी का भी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। वियतनाम में अर्न्तराष्ट्रीय व्यवहार और मानवता के सिद्धान्तों को ताक पर रखकर भारी युद्ध चल रहा है। अभी हाल ही में अमरीका ने उत्तर और दक्षिण के विसैन्यीकृत क्षेत्र में भी बम-बारी की है। अमरीकी ऐशियाई लोगों के विरूद्ध अधिक से अधिक घातक शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं जिस प्रकार जापान के विरुद्ध अणुबम और कोरिया तथा वियतनाम में कीटाणु बमों का प्रयोग किया गया है। जैसा कि अमरीका की सरकार कह रही है यदि वह वियतनाम में अपने चार लाख सैनिक भेज देते हैं तो उनका एक वर्ष का व्यय वहां के कुल उत्पाद से कुछ अधिक ही होगा। ऐसा वियतनाम के लोगों की आजादी को कुचलने के लिये किया जा रहा है।

अर्न्तराष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में हमारी सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सरकार को कम से कम यह बतायें कि विश्व के उस भाग में क्या हो रहा है। 7 जुलाई को बिना सोचे समझे एक प्रस्ताव रखकर प्रधान मंत्री ने भारत के मुंह पर कालिख पोत दी है। किसी भी देश में उसको थोड़ा भी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। हम कुछ बातें इस लिये नहीं कह सके कि नई परियोजनाओं सम्बन्धी ऋण की तलवार हमारे सर पर लटक रही है और अमरीका हमारी विदेश नीति के सम्बन्ध में कठपुतली के नाच का मजा ले रहा है। प्रधान मंत्री ने दक्षिण वियतनाम मुक्ति मोर्चे के नाम भी कभी नहीं लिया। उन्होंने वियतनाम में आक्रामक का भी नाम नहीं लिया। उन्होंने विश्व न्यायालय के निर्णय पर जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के सम्बन्ध में निन्दनीय था, सरकारी तौर पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। ज्यों-ज्यों सरकार हमारे विश्वास और आदर्श वाद और सर्वाकृष्ट परम्पराओं से दूर हुई है त्यों त्यों हम विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं।

यह आशा करना गलत है कि साम्यवाद के खतरे को बढ़ाचढ़ाकर कहने से भारत को मार्शल प्लान स्तर पर काफी अमरीकी सहायता मिल सकेगी। प्रधान मंत्री इस बात पर जोर दे रही हैं कि चीन के साथ हमारा संघर्ष सैद्धान्तिक है परन्तु इस विचार धारा को श्री नेहरु ने कभी नहीं अपनाया था।

उन्होंने चीन और साम्यवाद को सीमित रखने की भी बातें कही हैं।

जिस किसी देश ने भी अमरीका के सामने आत्म समर्थन किया है वहां लोकतंत्र को कुचल दिया गया है। यही कारण है हमने अभी हाल ही में अवैध कार्यवाही अध्यादेश को जो प्रकटरुप से विघटनकारी कार्यवाहियों को रोकने के लिये है, कानून का रुप दिया है। यह एक अपशकुन है।

वर्तमान सरकार कार्यकुशलहीन तथा भ्रष्ट है। सदन में उसका बहुमत होते हुए भी एक

दिन भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। जनता का विश्वास सरकार से उठ गया है इसलिये उसको गद्दी छोड़ देनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है।"

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जैलोर) : इस प्रस्ताव के प्रस्तावक इस प्रकार बोल रहे थे जैसे कि वह इस सरकार के विरुद्ध नहीं बल्कि अमरीका सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश कर रहे हों।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

वियतनाम में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हमारी सरकार ने किसी को संदेह में नहीं रखा है। हमें अर्न्तराष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के सभापति होने के नाते अपने ऊपर कुछ पाबन्दी रखनी है। सभा ने भी यह बात कई बार मान ली है कि वियतनाम की समस्या का समाधान सैनिक कार्रवाई में नहीं अपितु बातचीत में है। यह राजनीतिक समस्या है जिसे राजनीतिक तरीके से हल करना चाहिये। सभा ने यह स्वीकार किया है कि इस समस्या का समाधान जैनेवा करार के अर्न्तगत हो सकता है और ठीक यही स्थिति सरकार ने अपनाई है।

इस समय देश के सामने गम्भीर स्थिति है और हम सब के लिए आवश्यक है, चाहे किसी भी दल के हों, कि देश में मौजूद समस्याओं का साफ तथा उद्देश्यात्मक विश्लेषण करें और इसका सामना करने के लिए सोच-समझ कर एक योजना बनायें और उसे कामगर रूप से कार्यान्वित करें। हमारी आर्थिक स्थिति में क्या कठिनाइयां है और हमारे विदेशी मामलों में क्या त्रुटियां है आदि आदि को हमने समझना है और उस सम्बन्ध में उचित उपाय करने हैं। वास्तविक स्थिति को हम नहीं समझे हैं। साम्यवादी दल के नेता ने अवमूल्यन के फैसले पर आरोप लगाया है और कहा है कि ऐसा निश्चय बाहरी दबाव के कारण किया गया है। इस सम्बन्ध में अमेरिका, विश्व बैंक अथवा अर्न्तराष्ट्रीय मुद्रा निधि का दबाव हो या न हो परन्तु परिस्थितियों का दबाव अवश्य पड़ा था। स्वतंत्र पार्टी के अनुसार ऐसा उपाय करना पिछले 15 वर्ष के आर्थिक कुप्रबन्ध के कारण हुआ। श्री मसानी जी का कहना है कि नियन्त्रण ने उद्यम को खत्म कर दिया है और भ्रष्टाचार तथा मुनाफा खोरी को प्रोत्साहित किया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि विरोधी दल आपस में ही एक दूसरे के विरुद्ध बात करते हैं चाहे प्रश्न नियंत्रणों का हो अथवा सामान्य आर्थिक दशा की बात हो अथवा अवमूल्यन की बात हो और वह वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सके। वास्तविकता यह है कि केवल 1962 से ही हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ विकार पैदा हो गये हैं और मौजूदा स्थिति के लिए यही विकार उत्तरदायी हैं।

कीमतों में वृद्धि, निवेश और सभी बातें 1962 तक ठीक तरह चलती रहीं। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और हमें सार्वजनिक मांग के अनुसार प्रतिरक्षा कार्य बढ़ाने पड़े जिसके कारण भारी व्यय हुआ। प्रतिरक्षा कार्यों पर साधारणतय: 350–400 करोड़ रुपया खर्च होता था जो बढ़कर एक दम 800 करोड़ प्रतिवर्ष होगया। भारत में वही कुछ हो रहा है जो रूस की क्रान्ति के पश्चात रुस में हुआ। कुछ पश्चिमी लोकतन्त्र रूस के नये सामाजिक ढांचे को तबाह

करना चाहते थे । अपने विकास और अर्थव्यवस्था को बनाये रखने के लिए उन्हें बाहरी प्रभाव रोकने के लिए लोह-आवरण लगाने पड़े ।

सन् 1962 में चीन का इरादा हमारे लोकतन्त्रामक ढांचे और नियोजित अर्थव्यवस्था को उखाड़ फेंकने का था । वे इस उद्देश्य को प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल रहे । हमें मजबूरी में 500 से 600 करोड़ रुपये तक प्रतिवर्ष अधिक खर्च करना पड़ा क्योंकि अभी तक चीन का आक्रमण समाप्त नहीं हुआ है । हम चीन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं किन्तु चीन कोलम्बो योजना के बहुत ही उचित प्रस्ताव पर भी बात करने के लिए तैयार नहीं है ।

चीन ने केवल हमारे भू-भाग पर कब्जा करके ही आक्रमण को जारी नहीं रखा है बल्कि अब पाकिस्तान को उकसा कर उसे जारी रख रहा है । पाकिस्तान आक्रामक, छापामार और गुंडागर्दी की चालें अपनाना चाहता है । चीन ने यह स्पष्ट कह दिया है कि वह पाकिस्तान का समर्थन करेगा । चीन पाकिस्तान को सब सैनिक सामग्री भी दे रहा है । इस सब के बावजूद साम्यवादियों ने चीन के इस रवैये की कभी निंदा नहीं की । वे सदैव संयुक्त राज्य अमरीका की निन्दा करते रहे । चीन हमारा पड़ोसी देश है और अमरीका की अपेक्षा चीन से हमें कहीं अधिक ज्यादा खतरा है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हम यह कदापि नहीं कहते कि चीन ठीक कर रहा है । हम यह भी नहीं कहते कि अमरीका की अपेक्षा चीन से हमें कहीं अधिक खतरा है । चीन को रोकने के लिए आप के पास क्या समाधान है ? क्या चीन को रोकने के लिए अमरीका की सहायता लेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : आप का तर्क है कि चीन इस देश के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है । हम इकट्ठे बैठ कर फैसला कर सकते हैं । चीन से अवश्य ही अधिक खतरा है ।

यह कहना गलत है कि कांग्रेस सरकार को सफलताएं नहीं मिली हैं । गत 15 वर्षों में देश ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है । स्कूलों में बच्चों की संख्या 1950-51 में 230 लाख से बढ़कर अब 680 लाख हो गई है । आज 20 लाख अध्यापक हैं । कालेज के विद्यार्थियों की संख्या 3 लाख से बढ़कर 15 लाख हो गई है । इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेशार्थियों की संख्या 4,700 से बढ़कर 23,300 हो गयी है तथा पालीटैकनिकों में 48,000 छात्रों ने प्रवेश किया है । वैज्ञानिकों की संख्या 12,000 है । इस प्रकार विकास कार्यों पर काफी खर्च होता है । अकसर कहा जाता है कि देश के हर बच्चे को प्राइमरी शिक्षा मिलनी चाहिये । इन सबके लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता है । इस प्रकार लोग अधिक विकास के लिए शोर मचा रहे हैं । इस लिए प्रतिरक्षा के साथ साथ विकास कार्य भी चल रहे हैं ।

सरकार ने कई और भी सफलताएं प्राप्त की है । जीवन की आयु 32 वर्ष से बढ़कर 50 वर्ष हो गयी है । तीन योजनाओं की अवधि में हमने 280 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया है । कच्चे लोहे का उत्पादन 3 लाख टन से बढ़कर अब 150 लाख टन हो गया है तथा हम इसका निर्यात कर रहे हैं । उस निर्यात के कारण हमें लगभग 78 करोड़ से 80 करोड़ रुपया प्राप्त हो रहा है । मशीनी औजारों का उत्पादन 0.63 टन से बढ़कर अब 53-97 टन हो गया है । पहले हम 2,900 रेल के डिब्बे तैयार करते थे परन्तु अब उनका उत्पादन 24,300 हो गया है । सूती कपड़े का उत्पादन 42150 लाख मीटर से बढ़कर 74450 लाख मीटर हो गया है । चीनी का उत्पादन 11 लाख टन से बढ़कर 32 लाख टन हो गया है । आबादी में केवल 30 प्रतिशत की वृद्धि

हुई है परन्तु चीनी के उत्पादन में 250 प्रतिशत वृद्धि हुई है। खाद्यान्न का उत्पादन 68 प्रतिशत बढ़ गया है जबकि जन संख्या केवल 30 से 35 प्रतिशत तक बढ़ी है। खाद्यान्न की मांग इसलिए भी बढ़ी है कि पहले जो लोग आधे भूखे रहते थे वे अब कुछ अधिक खाने लगे हैं। इस प्रकार खाद्यान्न की मांग अधिक बढ़ गई है और इसके लिए हमने व्यवस्था करनी है। अब अगर छोटी छोटी वस्तुओं को लें तो यही स्थिति मिलेगी। पंखों का उत्पादन 2 लाख से बढ़कर 14 लाख हो गया है। सिलाई की मशीनों का उत्पादन 33,000 मशीनों से बढ़कर 3 लाख हो गया है। रेडियो का उत्पादन 54,000 से बढ़कर 5 लाख हो गया है। मोटर गाड़ियों का उत्पादन 16,000 से बढ़कर लगभग 7 लाख हो गया है। इस प्रकार ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां उत्पादन न बढ़ता रहा हो।

हमारी वर्तमान आर्थिक कठिनाइयां 1962 के चीन के आक्रमण जो अब भी जारी रखे जा रहे हैं, 1965 के पाकिस्तानी आक्रमण और दो वर्षों के सूखा के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। हमारी कठिनाइयां अस्थायी है न कि दीर्घकालिक। हमारे देश में मूल्यों का नियन्त्रण कृषि उत्पादन से, न कि औद्योगिक उत्पादन से, होता है। यदि दो वर्षों तक बहुत ही अच्छी फसलें हों तो सम्पूर्ण स्थिति बदल जाये। भारत में पिछले वर्षों में कीमतें बढी हैं ऐसा पिछले दो वर्षों में सूखा पड़ने के कारण हुआ है। यदि लगातार दो वर्ष अनाज का उत्पादन अधिक होता रहे तो मूल्य गिर जायेंगे।

जहां तक अवमूल्यन का सम्बन्ध है, सरकार ने रुपये का अवमूल्यन बड़े नेक इरादों से किया है। ऐसा देश के हित के लिए किया गया है, इसमें कांग्रेस दल का कोई हित नहीं है। सरकार ने ऐसा निर्णय करके बड़ी गलती की है उपभोक्ता वस्तुओं के अधिक आयात अथवा उपभोक्ता उद्योगों के लिए अधिक आयात से स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। वर्तमान स्थिति का जहां तक सम्बन्ध है, निराश होने का कोई कारण नहीं है। वर्तमान स्थिति अस्थायी है। हमने दृढ़ कदम उठाने हैं और यह देखना है कि हमारी अर्थव्यवस्था विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं रहती और विकास के लिए स्वयं प्रयत्न करना वांछनीय है। इस समय केवल अदम्य इच्छा-शक्ति तथा दृढ़ कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। हमें अपने संसाधनों का स्वयं ही निर्माण करना चाहिए।

श्री काशीराम गुप्ता : माननीय सदस्य ने बताया है कि अवमूल्यन के विषय पर उसका सरकार से मतभेद है। क्या उनके विचार से सरकार ने अवमूल्यन का फैसला विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए किया है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मंत्री-कक्ष इस का ठीक उत्तर दे सकते हैं। विचार-विमर्श के आधार पर ही मैं कुछ कह सकता हूँ।

श्री काशीराम गुप्ता : आप के दृष्टिकोण से क्या स्थिति है ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जैसा कि मैंने पहले कहा है सरकार ने रुपये का अवमूल्यन बड़े नेक इरादों से किया है और बिल्कुल राष्ट्रीय हित में है जैसा कि प्रधान मंत्री ने संकेत दिया है और बातचीत में इच्छा प्रकट की है।

जहां तक सरकारी क्षेत्र में उद्यमों का सम्बन्ध है, अच्छे सरकारी उद्यम भी हैं और खराब उद्यम भी है। यदि स्थायी समिति की स्थापना पहले की गई होती तो इस से सरकारी क्षेत्र के

उपक्रमों का काफी हित हो सकता था । ऐसे बहुत से कारखाने हैं जिनमें काफी सफलता मिली है । कुछ ऐसे उद्यम भी है, जिन की ठीक ढंग से व्यवस्था की जाये और यदि प्रत्याशित पग उठाये गये तो उनसे सरकार को बहुत अधिक राजस्व प्राप्त होगा और वे उस उच्च स्थान के पात्र होंगे जो कि सरकार ने उन्हें दिया है ।

सरकारी उद्यमों में एक कठिनाई यह है कि परियोजना सहायता के अन्तर्गत हमें मशीनें मिलेंगी परन्तु उनका पूंजीगत परिव्यय बहुत अधिक होगा । यह पूंजीगत परिव्यय उत्पादन-लागत में शामिल हो जाता है । इनकी तुलना पिछले परिव्यय से करना गलत है । कई उद्यमों का काफी विस्तार हुआ है । हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में गड़बड़ी ही गड़-बड़ी है । उनमें बहुत कुछ प्रशंसनीय बातें भी हैं ।

अवमूल्यन को देखते हुए कुछ उपाय करना आवश्यक है । पूंजीगत माल तथा पुर्जों के आयात को कम करके सर्वथा न्यूनतम रखा जाए । अगले दो अथवा तीन वर्षों में हमारा औद्योगिक विकास देश में बनी मशीनों तथा उन मशीनों पर आधारित होना चाहिये जिन्हें हमने माल के आयात में कमी लाने के लिए आयात किया है । किसी भी अवस्था में, देशी उपभोग के लिए कच्चे माल के आयात को बढ़ावा न दिया जाए । उसका केवल उतना ही आयात किया जाए जितना कि कारखानों को चालू रखने के लिए आवश्यक हो ।

सरकारी क्षेत्र में प्रबन्धकों को सुधारा जाए और क्रियाशील बनाया जाए । विचार-विमर्श के पश्चात उनको लक्ष्य बताये जायें और प्रत्येक सम्बन्धित मन्त्री महोदय प्रतिमास अपने विषय पर रिपोर्ट दें । सरकारी क्षेत्र में भारी मशीनरी तथा बिजली उपकरणों का निर्माण तीन पारियों में किया जाए । इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की जाए । प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में, सम्बद्ध उद्योगों का विश्वास प्राप्त किया जाए और यथार्थता पर आधारित उत्पादन का कार्यक्रम बनाया जाये और मंत्री महोदय स्वयं प्रगति पर निगाह रखें । उनको आयातित वस्तुओं के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं तथा निर्यात के सम्बन्ध में लक्ष्य बताये जायें । आयात के कोटे में कार्यक्रम के अनुसार धीरे धीरे कमी की जाये ।

जहां किसी उद्योग में से नियंत्रण हटा लिया गया हो, तो उस उद्योग को वितरण की व्यवस्था करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाये । उसी उद्योग को वितरण की व्यवस्था करने की पूर्ण स्वतंत्रता न दी गई तो चोर-बाजारी को बढ़ावा मिल सकता है । इसका उदाहरण सीमेंट है जो आज 18-20 रुपये प्रति थैला अर्थात वास्तविक मूल्य से 8-9 रुपये अधिक पर बेची जा रही है ।

भारी राजकोषीय दण्ड के लिए व्यवस्था की जाए और उस दण्ड द्वारा अनुचित लाभ का सफाया किया जाए ।

1966-67 के दौरान सभी लघु और मझौली सिंचाई परियोजनाएं पूरी तरह क्रियान्वित की जानी चाहिये ।

पम्पिग सेटों के प्रयोग द्वारा सिंचाई के पुराने तरीकों पर जो इस समय खर्च आता है उसमें 50 प्रतिशत की कमी की जा सकती है । और यदि बिजली दो आने प्रति यूनिट की दर से दी जाये तो इसमें 50 प्रतिशत अग्रेतर कमी की जा सकती हैं । अनाज की उत्पादन लागत में कमी करने का केवल यही एक मात्र तरीका है । प्रत्येक जिले के लिये कृषि उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये जाने

चाहिये मैं बड़ी पारियोजनाओं के विरुद्ध नहीं हूँ, परन्तु ये दो वर्ष हमें उन योजनाओं की तैयारी में लगाने चाहिये। ताकि उनमें कोई त्रुटि न रह जाये।

श्री रंगा (चित्तूर) : सरकारी उपक्रमों में राष्ट्र का 8,000 करोड़ से भी अधिक रुपया लगाया गया है, परन्तु जब हम उसकी आमदनी को देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी रकम लगाने पर भी समूचे तौर पर एक प्रतिशत मुनाफा भी नहीं हुआ है। राष्ट्र का बहुत अधिक धन इन उपक्रमों में डुबो दिया गया है। सरकार ने स्वयं इस बात को माना है कि मूल्यों में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उनको रोकना काबू से बाहर है। 1959 में स्वतन्त्र दल ने सरकार को मुद्रास्फीति के खतरे से खबरदार किया था, परन्तु सरकार ने हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार ने जान बूझकर मुद्रा स्फीति को अपनाया है और नोट छाप छाप कर योजनाओं के व्यय को पूरा किया है। सरकार ने ही हमारे देश की यह दयनीय दशा कर दी है।

मैसूर के मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं, राजस्थान के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप हैं; बिहार के मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री और उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप हैं। भ्रष्टाचार हमारे राजनैतिक जीवन को खोखला बना रहा है। कुछ केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध भी आरोप थे। कल ही राज्य सभा में सदस्यों ने, उस अधिकारी को एक राजदूत के रुप में विदेश भेजने से रोकने के लिये समय पर कार्यवाही न करने के बारे में प्रधान मंत्री और उसकी सरकार का कड़ा विरोध किया था और बाद में सरकार ने अपनी गलती को माना था। सभा में विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा आगाह किये जाने पर भी सरकार ने ओम्बुड्समैन जैसी संस्था स्थापित नही की है। सम्पूर्ण भारत में जो कुछ हो रहा है वह मानो मधुमेह से पीड़ित सरकार के शरीर पर उठते हुए फोड़ों की भांति है। इन सब बातों ने कल उत्तर प्रदेश में एक बन्द का रुप धारण किया। कितनी आश्चर्य की बात है कि इस बन्द में सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों ने भी भाग लिया।

माननीय गृह मंत्री से किसी ने कहा नहीं था, परन्तु उन्होंने स्वयं ही देश को यह वचन दिया कि यदि वह दो वर्ष में भ्रष्टाचार समाप्त करने में सफल न हुए तो वह त्याग पत्र दे देंगे। क्या उनको इस कार्य में सफलता मिली है ? प्रत्येक व्यक्ति को अपना वचन पूरा करना चाहिये। यदि वह असफल हुए थे तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी छोड़ देने के लिये तैयार हो जाना चाहिये था और देश को यह दिखाना चाहिये था कि वह एक योग्य व्यक्ति हैं। इस दृष्टि से गृह-कार्य मंत्री निन्दा के पात्र हैं। अब तक जो भी प्रधान मंत्री बने हैं वे भी निन्दा के पात्र हैं क्योंकि उनमें से किसी का भी श्री नन्दा से इस्तीफा मांगने का साहस नहीं हुआ। जब मंत्रियों का यह हाल है तो आप प्रशासन के शुद्ध होने की आशा कैसे कर सकते हैं। प्रशासन के इतना अधिक दूषित होने का एक कारण यह है कि यहां परमिट, लाइसेंस, कोटा और दल प्रधान प्रशासन है। हम चाहते हैं कि प्रशासन को एक निष्पक्ष अर्ध न्यायिक आयोग को सौंप दिया जाये जिसका प्रधान एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, परन्तु सरकार इस सुझाव को मानने के लिये तैयार नहीं है।

प्रधान मंत्री ने बार बार इस बात को दोहराया है कि मितव्ययिता की आवश्यकता है। परन्तु वास्तव में सरकार ने मितव्ययिता की दिशा में कुछ भी नहीं किया है। सरकार ने संसद की स्वीकृति के बिना ही प्रधान मंत्री के निवास स्थान को, करोड़ों रुपयों की राष्ट्रीय सम्पत्ति को,

पल भर में खर्च करके उसे एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया है। दूसरे प्रधान मंत्री एक साधारण निवास स्थान चाहते थे। फिर भी सरकार ने उनके निवास स्थान के पुनर्निमाण पर एक लाख से अधिक रुपया खर्च कर डाला ताकि प्रधान मंत्री के लिये वहां सुरक्षा, अतिथिगण, स्वागत और अन्य साज सामान सम्बन्धी व्यवस्था की जा सके। नये प्रधान मंत्री को यह भवन पसंद नहीं आया क्योंकि इसके कमरे उनके अतिथियों के लिये छोटे हैं। अब सुना गया है कि वह निजाम के महल में जाना चाहती हैं।

जिन परिस्थितियों के कारण अवमूल्यन हुआ उनके लिये भी सरकार ही जिम्मेदार है। ऐसी दयनीय हालत पैदा करने के लिये सरकार की निन्दा की ही जानी चाहिये। मैं अपने माननीय मित्र श्री मुकर्जी को बता देना चाहता हूँ कि अवमूल्यन की घोषणा इसलिये नहीं की गई थी कि अमरीका ने इसके लिये जोर दिया था अपितु इसलिये कि इसके अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं था। वस्तुत: अवमूल्यन का यह दूसरा चरण था। यदि चुनाव में कांग्रेस फिर से बहुमत से जीत गई तो अवमूल्यन का तीसरा और चौथा चरण भी सामने आ जायेगा।

अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देने के मामले में भी सरकार को सफलता नहीं मिल पाई है। हमारे संविधान में अनिवार्य और निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा देने की पवित्र प्रतिज्ञा हमने की है। और इस प्रतिज्ञा के पालन में सरकार की असफलता का पता इस बात से लगता है कि आज भी हमारे देश में 75 प्रतिशत मतदाता निरक्षर हैं। इसका परिणाम यह है कि निरक्षर लोग आज भी बैलों की जोड़ी के गुलाम बने हुए हैं।

साम्यवादी यह चाहते हैं कि हम अमरीका की निन्दा करें। चीन के आक्रमण के समय केवल अमरीका और ब्रिटेन ही ऐसे देश थे जिन्होंने हमें सहायता मांगने पर तुरन्त सहायता दी थी। यह लज्जा की बात है कि आज भी सरकार यह कहने को तैयार नहीं है कि वह चीनियों को अपने भूभाग से खदेड़ने के लिये हर सम्भव कार्य करेगी। हम इस प्रकार की सन्देहात्मक देश भक्ति के विरुद्ध हैं।

कांग्रेस दल सत्ता से तब तक जोंक की भांति चिपटे रहना चाहता है जब तक कि देश का विनाश नहीं हो जाता। वह सत्तारुढ़ होने योग्य नहीं है और उसे त्यागपत्र दे देना चाहिये। इसके त्यागपत्र दिये जाने के पश्चात ही चुनाव किये जाने चाहिये। संसद के लिये चुनाव पृथक होने चाहिये। ऐसा होने पर ही हम दिखा सकते हैं कि देश में जनमत स्थिर नहीं है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के मंत्रिमण्डल भी बर्खास्त किये जाने चाहिये ताकि उनके लिये भी चुनाव करवाये जा सकें। इन सब चुनावों के बाद हमारे लिये यह संभव हो सकेगा कि हम सब मिल कर कार्य करें और तभी ही हम यह देख पायेंगे कि क्या हमारे यहां सर्वदलीय सरकार नहीं बनाई जा सकती है। हमारे जैसे देश के लिये एकदलीय शासन की व्यवस्था उपयुक्त नहीं है।

श्री हेडा (निजामाबाद) : श्री रंगा ने एक राष्ट्रीय सरकार बनाने की बात कही। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यदि उनके विचारों के अनुसार एक राष्ट्रीय सरकार बना भी दी जाये और उनको उसमें स्थान भी मिल जाये तो क्या वह श्री मुकर्जी को उसमें रखना चाहेंगे ?

श्री हो० ना० मुकर्जी : मैं इसके लिये उम्मीदवार नहीं हूँ।

श्री हेडा : आप उम्मीदवार भले ही न हों, परन्तु यदि उनके विचारों को क्रियान्वित करना है तो नतीजा यही होगा। इस सभा में पहले दिन कुछ सदस्यों ने जो शोरोगुल मचाया और जिस

तरीके से इस सभा की कार्यवाही के चलने में विघ्न डाला उसको देखते हुए श्री रंगा की कल्पना व्यावहारिक नहीं है।

दोनों प्रतिपक्षी सदस्यों के भाषणों में राजनैतिक तत्व अधिक था और आर्थिक तत्व कम। अवमूल्यन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। प्रतिपक्षी सदस्यों ने यह कहा है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था बहुत कमजोर पड़ गई थी और इसके लिये किसी कठोर उपचार की आवश्यकता थी और वह कठोर उपचार है अवमूल्यन। अवमूल्यन की तुलना एक गम्भीर रोगी के आपरेशन से की गई है। मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। इस में संदेह नहीं कि हमारी अर्थ व्यवस्था कुछ कमजोर पड़ गई है परन्तु इतनी नहीं जितना कि बढ़ा चढ़ा कर यहां बताया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि हम अपने देश में बहुत तीव्र गति से विकास चाहते थे।

यह ठीक है कि हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है परन्तु साथ साथ हमारे आयात में भी वृद्धि हुई है। हमने मुख्य रूप से पूजीगत सामान मंगाया हूँ। इस कारण से भुगतान-शेष में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। अतः हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी अधिक खराब नहीं जितनी कि समझी जा रही है।

दूसरे अवमूल्यन एक कठोर उपाय नहीं है। यह एक ऐसा उपाय है जिसे सरकारें प्रायः अपना कर निर्यात को बढ़ाती हैं और आयात को कम करती है। हमें आजकल की स्थिति में इसकी आवश्यकता थी। अतः यह एक ठीक कदम है।

यह बात ठीक नहीं कि अवमूल्यन के कारण कीमतें बढ़ी है। यह प्रवृत्ति तो 1952 में ही ध्यान में आयी थी।

हमारे देश के लोगों के सभी वर्गों में यह प्रवृत्ति बन गई है कि अधिक लाभ प्राप्त किया जाये। इस से मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसके अलावा हमारे देश में लोगों के खाने की आदतों में भी परिवर्तन हो रहा है। अब अधिक लोग गेहूँ और चावल खाने लगे हैं। यह भी मूल्यों की वृद्धि का एक कारण है। आप दिल्ली की स्थिति का अवलोकन करें तो पता चलेगा कि यहां पर भी मूल्यों में बहुत भिन्नता है। सुपर बाज़ार के खुल जाने से मूल्यों में स्थिरता लाने में सहायता मिली है। सरकार को इस प्रकार और बाजार खोलने चाहियें। इससे मूल्यों में कमी लाने में सहायता मिलेगी और व्यापारी लोग मनमानी नहीं कर सकेंगे।

कुछ सरकारी परियोजनाएं सफल हुई है परन्तु कुछ परियोजनाओं को पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली है। इसका मुख्य कारण वहां पर कार्य कुशल व्यक्तियों का अभावं है। सरकार को ऐसे उपक्रमों में व्यापार निपुणता वाले व्यक्तियों को रखना चाहिये।

[श्रीमती रेणुका राय पीठासीन हुईं
SHRIMATI RANUKA RAY *in the Chair.*]

मैंने अपने नगर में देखा है कि फैक्ट्रियों के प्रबन्धकों के बदलने पर उत्पादन में कितनी अधिक वृद्धि हुई। यह पहले से चार गुनी हो गई है। यह सब कार्यकुशल व्यक्तियों के लगाने से हुआ है। हमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये और इनके कार्य संचालन में आवश्यक सुधार करने चाहिये।

प्रति दिन आकाशवाणी द्वारा कीमतों की घोषणा से मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता

मिलेगी। इससे वस्तुओं के खरीदने वालों को जानकारी मिलती रहती है। संसद को चाहिये कि सरकार को दे दे कि यदि कोई व्यापारी घोषित मूल्यों से अधिक कीमत लेता है तो उसे कड़ा दण्ड दे सके।

प्रतिपक्ष वालों को जान लेना चाहिये कि उनका प्रयत्न विफल होगा और आगामी चुनाव के बाद कांग्रेस की ही सरकार बनेगी।

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur) : This is fourth motion of no-confidence during the term of this Lok Sabha. These motions indicate the people's resentment against Government's policies. The Government is guilty of ignoring the Directive principles of State policy laid down in the Constitution. Government has done nothing for banning the cow slaughter. Constitution enjoins upon Government to take steps in this direction. It was promised that uniform civil Code would be made for Hindus and Muslims. It is another instance of Government's disregard of the directive principles of state policy.

The foreign policy of Government is nothing but appeasement of other nations. Our Government unnecessarily involving itself in Vietnam. Our Communist freinds always think in terms of appeasement of Russia and China. It is not in the interest of India. Our Government and the Communists did not raise their voice when China had swallowed Tibet and subjected the Tibetan to cruel atrocities. They did not say anything when North Vietnam, with the help of China attacked South Vietnam. This type of policy is not good. It is our misfortune that our Government kept quiet at the time Russian attack on Hungary. We are not prepared to give recognition to Israel because we do not want to displease the Arab countries. I say that Government should not be afraid of any country. We should lay down our policy in the interests of our own Country. We should not be under the influene or pressure of any country. We must have an independent foreign policy. Shri Heda has said that Congress Party would emerge victorious in next election. I do not see any logic in this. You will find that it would be Jan Sangh that will achieve remarkable successes at the polls.

Devaluation is the biggest blunder which the Government has committed. The result of devaluation is that the price of almost every commodity has gone up and Government is unable to check it. This super market will not prove a lasting solution.

Conditions were very bad in almost every field of administrative activity. The Ministers were not heeded in the administrative sphere. They were practically in the hands of bureaucratic officers. The real power was in the hands of officers. Corruption and other evil practicesare everywhere. Conditions were deteriorating. The Government's failure in performing its duties prevalent properly could be seen in frequent strikes in the country. The employees of U. P. Government are on strike. It shows how Government is functioning.

In the matter of Nagas, the Government policy of appeasing the hostile elements was most regrettable. Our policemen who fired in self defence against Nagas were taken to task. This type of policy should be done away with.

The Government has miserably failed in managing the affairs of the country in a manner it should. Government has a dismal record and the sooner it quits, it would be better for the country.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): The opposition do not have a common ideology. They are opposed to each other's programme. I do not know why they have brought this motion. The criticism made against the Government by members belonging to the communist and Swatantra parties was unfounded. The Communist party is opposed to Indo- U.S. foundation. The Swatantra party says that there should be no control on imports, that foreign capital should be allowed to come without any restriction and that there should be no planning.

The Congress party can not agree with this type of policy. We have to keep the country's

interests above all. The policy which has been laid down by Jawaharlal Nehru will be adhered to. We would accept all aid that was necessary for the development of the country. We could not develop the country unless we had a plan for development for the uplift of the poor and the down-trodden. A plan has got to be formulated. The Swatantra party is not concerned for the poor. It is for the rich and the capitalist.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

During these last 18 years we have made considerable progress. Our national income has gone up. We have appointed Monoplies commission. Its report is under consideration. I do not know as to how opposition side can say that we have not made any progress. The devaluation of rupee is another step to overcome the difficulties on the way of our forward progress.

The important work is the follow up action of devaluation. We have to hold the price line. France and Yugoslavia had benefitted from devaluation. We should also follow their example. The Congress Party first considers every question of national importance and then the decision is taken. The opposition parties have no common programme. How can they ask Congress party to quit office ?

After this mutual introduction I may say that we shall be able to run the administration of the Country because we have been empowered to do that by the people. Opposition should try to understand others, view points also. They should learn to behave in a more dignified manner.

I have myself criticised the economic policy. Our Prime Minister and our food Minister have repeated more than once that every thing is not going well in this country. Our Prime Minister has never concealed any thing. She has rather confessed the difficulties. Shri Ranga suggests Potassium cyanide rather than insuline for the patient of diabetes. Is it the way of healthy criticism. Who can say that most of us do not 68 Paise a day. Some of our Minister says that. These opposition Members advance beseless arguments at times. Most of these were sleeping when we won freedom for the country. I admit that we are not free from short comings and weaknesses and have not been running administration in Gandhian ways.

Now I come to our Foreign Policy. Shri Hiren Mukherjee has said that the policy of our Prime Minister with regard Vietnam has been wavering. That is not so. Our Prime Minister has consistently been saying that there can be no military solution of the problem. Bombardments should cease and all the concerned countries should meet together under Geneva Convention and thrash out some solution through negotiations. As regards aggression, it is well known to every body. So there is no point of shift in our foreign policy and we have constantly been sticking to our ideals and principles.

He has raised another point of Trial of American Pilots as War Criminals. This of course we could not advance in the larger interests of world peace. If Pilots are tried as War Prisoners America will inevitably augment its bombardments and some more countries may also meddle and the world will thus be brought on the brink of war. This type of war was once averted by wise diplomacy of our late Prime Minister Shri Jawahar Lal Nehru when America and Russia were at daggers drawn on the issue of Cuba and now his daughter Indira Gandhi follows her father in the same noble cause. He has also criticised the Prime Minister for accepting transmitters from America under Voice of America Agreement. This is also a wrong hypothesis, since the matter was dropped long back. He has further referred to Indo-U. S. Foundation. This was discussed in the time of late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri also. We reviewed the terms and conditions in a democratic way and concluded that we would only be able to accept it if the Administrative Control of this foundation is wielded by the Indians. We have admitted our weaknesses shortcomings on food and economic fronts and are prepared to bring about necessary changes. We want to increase the procurements and bring our imports to the tune of four millions.

It is all the more deplorable that the motion of non-confidence has been brought before us at this hour of our National Crisis. The Country is face to face with grave danger on our borders from Pakistan and China. Shri Hiren Mukherjee wants our Prime Minister to appreciate the imperialistic designs and the aggressive activities of China. Today when heinous and black jaws of China are on NEFA and Bomdilla and Pakistan has been trying to spreading its spies on our border in Kashmir and thinking of attacking the beautiful gorges of Baramulla etc. after having obtained Tanks and jets, it is at this juncture that they have leisure to bring this motion before the House instead of extending their Cooperation in order to solve all these national problems. Recently in the joint communique with Russia our Prime Minister denounced American policy in Vietnam and sought cessation of Bombardment.

As a matter of fact the opposition have thrown their principles to the winds and brought this motion in view of approaching General Election. They are all out for defeating us in the General Elections but if Congress does not return to power there is bound to be anarchy in the country.

This motion has been based on wrong figures and facts, ill timed and illogical and brought forth by biased and wrong men at this hour of National crisis.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : भाग्य की विडम्बना यह है कि यह अविश्वास प्रस्ताव कम्युनिस्ट पार्टी ने ही रखा तथा उन्हीं के कुछ सदस्यों ने श्रीमती इन्दिरा गान्धी का प्रधान मन्त्री बनने के समय समर्थन किया था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : आप श्री मोरार जी देसाई का समर्थन करते।

श्री हेम बरुआ : मैं एक रहस्य प्रकट करता हूँ और वह यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत से सदस्य उस समय मेरे पास आये जब प्रधान मन्त्री पद के लिये चुनाव हो रहा था। इन लोगों ने मुझसे श्रीमती इन्दिरा गान्धी का समर्थन करने का पुरजोर अनुरोध किया था। मैं उन्हें आश्वासन न दे सका क्योंकि मैं कांग्रेस की नीतियों के और सम्पूर्ण दल के ही विरुद्ध हूँ। अब श्रीमती इन्दिरा गान्धी के मित्र ही उनके विरुद्ध हैं।

श्री खाडिलकर (खेड) : उन से अनुरोध नहीं किया गया था।

श्री हेम बरुआ : मैंने श्री आजाद का भाषण सुना और उससे मुझे ब्रिटेन के 150 साल के शासन की याद आई। अंग्रेज लोग अपने सारे शासन काल में अपने को इस देश का मालिक समझते थे और हर अंग्रेज अपने आपको ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षक समझता था। श्री आजाद भी उसी मनोविज्ञान के शिकार जान पड़ते हैं तथा अपने को हर कांग्रेसी के साथ भारत के भाग्य का विधाता समझते हैं।

श्री मनुभाई शाह (वाणिज्य मन्त्री) : इसमें क्या सन्देह है ?

श्री हेम बरुआ : हर भारतीय को अपने को इस देश का मालिक समझना चाहिये और इसके लिये बड़ा सा बड़ा त्याग करने को तय्यार रहना चाहिये।

श्री मनुभाई शाह : इसमें कोई विरोधाभास नहीं है।

श्री हेम बरुआ : शासनतंत्रीय मनोविज्ञान की दृष्टि से सोचना उचित नहीं है। इस प्रवृत्ति का निराकरण होना चाहिये। सभी परिस्थितियों में शासक के विशेषाधिकार नहीं दिये जाने चाहिये।

एक माननीय सदस्य : वे विशेषाधिकार जो सेवा करने के लिये दिये जाते हैं।

श्री हेम बरुआ : इन विशेषाधिकारों को वे अपनी ही सेवाओं के लिये प्रयोग करते हैं। गान्धीजी के नेतृत्व में जिस जन-मानस या सामाजिक व्यक्तित्व का उदय हुआ था उसका ह्रास होता जा रहा है और व्यक्ति की महत्वाकांक्षायें उभर रहीं है और उन्हीं का पृष्टपोषण हो रहा है। यही दुःख का विषय है। यही श्री जवाहर लाल नेहरू ने 19 सितम्बर, 1947 को कहा था : "मैं भारत की पिछले 30 साल की परिस्थितियों में सन्तुष्ट नहीं रहा। दर असल हम स्थिति का मुकाबला कुछ मनोविज्ञान और कुछ शक्ति से कर सकते हैं।"

दुर्भाग्य यह है कि किसी ने भी गिरती हुई स्थिति को न मनोविज्ञान के द्वारा ही सम्हाला और न शक्ति के द्वारा। कांग्रेस का 19 वर्ष का शासन काल हर प्रकार असफल रहा-चाहे राष्ट्रीय जीवन हो या अन्तर्राष्ट्रीय, आर्थिक हो या राजनीतिक, नैतिक हो या आध्यात्मिक। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को देश की शक्तियों को निर्माणोन्मुख बनाने की दिशा से प्रयत्नशील होना चाहिये क्योंकि यह देश अभी स्वतन्त्रता के समुज्ज्वल प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। हमने विदेशी दासता के अन्तर्गत कई कष्ट झेले। स्वतन्त्रता के बाद हमारे नेताओं में पदलोलुपता आ गई और सामाजिक शक्ति के स्त्रोतों को हम क्रियाशील नहीं बनाये रख सके।

हमारा चीन से झगड़ा है। भारत और चीन में कौन बड़ा है इसका निर्णय रक्षा के मामलों में नहीं अपितु आर्थिक मामलों में ही होना चाहिये यदि हमारी आर्थिक दिशा में प्रगति हुई तो हम आगे बढ़ सकेंगे। चीन ने पिछले चार वर्षों में अपने कृषि-उत्पादन को दुगुना कर दिया है और इस्पात-उत्पादन चारगुना बढ़ गया है।

एक माननीय सदस्य : उनको कैसे पता है ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Figures given by Shri Hem Barua are correct.

श्री हेम बरुआ : सरकार अपने आंकड़े रख सकती है। तथ्य यह है कि चीन ने हमसे अधिक प्रगति की है।

श्रीमती रेणुका राय (मालदा) : अव्वल दर्जे के प्रचारक।

श्री हेम बरुआ : मुझे पहिले दर्जे का.....

श्रीमती रेणुका राय : आपको नहीं, चीनियों को।

श्री हेम बरुआ : प्रशासनिक कार्यों के लिये कुछ भवन और इस्पात के कारखाने प्रगति के चिन्ह नहीं हो सकते। भारत की गरीबी वास्तव में और अधिक और व्यापक है। खूब उधार लेने और व्यय करने के बावजूद हमारे जीवन स्तर में पर्याप्त बढ़ावा नहीं आया है। औद्योगिक प्रगति सुस्त है तथा कृषि की स्थिति अच्छी नहीं है। सारे देश में अकाल की स्थिति है। बाढ़ें भी आ रही हैं। कहीं सूखा पड़ रहा है। बच्चे पैदा करने की दिशा में अवश्य प्रगति हो रही है-80 लाख बच्चे एक साल आ रहे हैं।

श्री मुहम्मद कोया (कोझिकोड) : लूप के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री हेम बरुआ : ये प्रसाद के तौर पर गांव में बांटे जा रहे हैं। उनके प्रयोग की कला ग्रामीणों को नहीं सिखाई जा रही है। श्रीमती सुशीला नायर को इस दिशा में स्त्रियों में एक चेतना पैदा करनी चाहिये और तीन बच्चों के बाद लूप का प्रयोग होना चाहिये।

पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद खाद्यान्न और उपभोक्ता वस्तुओं की बहुत कमी है। मार्च

1961 से सितम्बर 1963 के दर्मियान 14.4 लाख लोगों में बेकारी बढ़ी। इनमें से 7.2 लाख लोग प्रशासनिक शाखाओं में लगे हुये हैं जो कोई उत्पादन नहीं बढ़ाते। इस तरह पार्किन्सन की सेना ही बढ़ रही है। 1964 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा था कि योजना की क्रियान्विति में तो दोष है ही स्वयं योजना भी दोष मुक्त नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रीय सम्पत्ति का अपव्यय हो रहा है। आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। हाल ही में जो अवमूल्यन का निर्णय हुआ उससे सरकारी तौर पर यह मान लिया गया कि हमारी आर्थिक स्थिति समाप्ति के निकट है। उसे पुनर्जीवित करने को अवमूल्यन हुआ है। 1964 से हमारे विदेशी मुद्रारिजर्व (कोष) घटते जा रहे थे और तब से इसे पूरा करने के लिये कुछ नहीं किया गया। आयात घटाने और निर्यात बढ़ने से यह किया जा सकता था।

कितनी लिमोसीन गाड़ियां विदेशों से आ रही है। बदसूरत औरतों के लिये लिपस्टिक मंगाये जा रहे हैं।

श्री मनुभाई शाह : दोनों का आयात नहीं हो रहा है।

श्री हेम बरुआ : मंत्रियों की कारों के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री मनुभाई शाह : वे आयात की जाती हैं। विदेशी उन्हें लाते हैं और हमें बेच देते हैं। उन्हें विदेशी मुद्रा नहीं दी जाती है।

श्री हेम बरुआ : पुर्जे आप इनके अमरीका से मंगाते हैं। हाल ही हमारी प्रधान मंत्री ने एमबैसेडर जैसी छोटी गाड़ी में चलने की पेश कश की। मैं समझता हूँ यह हमारे जैसे गरीब देश के लिये कोई बड़ी खबर नहीं है यह सब चुनावों के लिये हो रहा है।

कर प्रवंचन हमारी अर्थव्यवस्था की एक पुरानी बीमारी है। 200 करोड़ रुपये के लगभग सालाना कर प्रवंचन होता है। कौलिनक्लार्क के शब्दों अगर यह प्रवंचन न होता तो भारतीय बजट व्यवस्था संतुलित हो सकती थी। सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया।

अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने के लिये अवमूल्यन का कठोर कदम उठाया गया है। किन्तु अनुवर्ती कार्यों की दिशा में सरकार बहुत सुस्त है। निर्यात तथा आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी इन समस्याओं को सुलझाने में कोई प्रगति नहीं दिखाई। उन्हें कई पैतृक विभूतियां प्राप्त हैं। उनकी सफलता इन समस्याओं के हल पर ही निर्भर करती है।

हमने राष्ट्रीय हितों की कीमत पर अन्तर्राष्ट्रीय हितों को देखा। कोई भी विदेश नीति तब तक सफल नहीं होती जब तक उसके पीछे मजबूत आर्थिक एवं सैनिक शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने भी चीनी आक्रमण के समय इन्हीं दो पहलुओं पर ज़ोर दिया था।

चीनी आक्रमण के समय की हमारी भगदड़ से हमारी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति में बड़ी क्षति पहुँची। हमारा अपमान हुआ। 14,500 वर्गमील क्षेत्र हस्तान्तरित करने के अलावा नेफा को विसैन्यीकृत क्षेत्र माना गया। यह सब कुछ चीन के कहने के अनुसार हुआ। हमारे सैनिक अभी नेफा में नहीं हैं। दोस्तों की स्थिति भी अजीब है। केवल यूगोस्लेविया ने ही पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में पाकिस्तान को आक्रमणकारी कहा शेष सभी मौन रहे। रूस भी पाकिस्तान के साथ

अपने सम्बन्ध सुधारने की होड़ में उसे आक्रमण कारी नहीं कहता। अपनी जिम्मेदारी को टालने के लिए उसने ताशकन्द समझौते करवाने की कोशिश की। यह समझौता भारत के लिये पाकिस्तान और रूस की ओर से धोखा था क्योंकि यह भारत के लिये अपमान जनक था और है। मेरा ख्याल है स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की दुखद मृत्यु भौतिक कारणों से नहीं हुई। इसके कुछ भावनात्मक कारण हो सकते हैं क्योंकि यह समझौता भारत के हित में नहीं था। हाल ही हमारी प्रधान मंत्री रूस गई तो उन्होंने संयुक्त वक्तव्य में कुछ साम्राज्य वादियों की ओर अस्पष्ट सा संकेत किया। जब चीन के बारे में उन से पूछा गया तो वह अस्पष्ट ही रहीं।

दोनों जर्मनियों के बारे में भारत सरकार ने जो नीति अबतक अपनाई थी उसमें प्रधान-मंत्री ने एक और अन्तर्राष्ट्रीय समस्या खड़ी करदी है। भारत-रूस संयुक्त-विज्ञप्ति में जो भाषा प्रयोग की गई है वह रूस की भाषा है न कि भारत की। ऐसा करके भारत ने अपनी ही नहीं सारे देश की शान पर धब्बा लगाया है।

जहां हम स्वेज के मामले में बड़े मुखर हुये वहां हम हंगरी के मामले में मौन रहे। यह पक्षपात ठीक नहीं। यदि हमारी नीति वास्तव में गुटों से अलग रहने की है तो इसमें हमें भावुकता में नहीं आना चाहिये। अमेरिका तथा रूस की सही दृष्टि से आंकना चाहिये। यदि समाजवादी या गान्धीवादी व्यक्ति भी कुछ बुरे काम करता है तो उसकी निन्दा करनी चाहिये।

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : अगर गान्धीवादी भी दुराचारी बनता है तो वह वास्तव और अधिक घृणित व्यक्ति होगा।

श्री हेम बरुआ : श्री बजाज जैसे वरिष्ठ सदस्य मेरे विचार का अनुमोदन कर रहे हैं इसकी मुझे बहुत खुशी है। इन्सान इन्सान में कोई भेद भाव नहीं बरतना चाहिये। हममें से बहुत से सदस्य अपने फ्लैटों या सर्वेन्ट्स क्वार्टरों को किराये पर चढ़ा रहे हैं। यह हम नुमा-इन्दों के लिये बड़ी अशोभनीय बात है। यदि हमारे आचरण ही गिर गये हैं तो हम सरकार की आलोचना कैसे कर सकते हैं ?

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, 2 अगस्त 1966/11 श्रावण, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 2 nd August 1966/Sravana 11, 1888 (Saka).

Tirthraj Press, Allahabad.